RNI No. DELMUL/2012/47011

27 अगस्त, 2026 गुरूवार

नई दिल्ली
मूल्य : 01 रुपए
पृष्ठ : 08
वर्ष : 14
अंक : 147

अनोखे अंदाज़ और निराले तेवर के साथ इन्साफ की डगर पर

टाइम्स ऑफ़ पीडिया

www.timesofpedia.com Email : timesofpedia@gmail.com

टेस्ट क्रिकेट में जिम्बावे के एंडी फ्लावर के नाम है सबसे अधिक स्कोर का रिकॉर्ड 07

संक्षिप्त वार्ता

हिमाचल में भूकंप, किचन में रखे वर्तन गिरे

शिमला। हिमाचल की राजधानी शिमला सहित आस पास के शहरों में आए भूकंप ने लोगों को डरा दिया। घरों की किचन में रखे वर्तन गिरने लगे। जब तक लोग समझ पाते तब तक झटके लगने लगे। लोग डर के चलते घरों से बाहर निकले तब पता चला कि भूकंप के झटके आ रहे हैं। सुबह 5 बजकर 46 मिनट और 50 सेकंड पर आए इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.0 दर्ज की गई। इसका केंद्र शिमला से करीब 66 किलोमीटर पूर्व-दक्षिण दिशा में, जमीन से 10 किलोमीटर नीचे जुब्बल-कोटखाई की तरफ था।

यह झटका लगभग तीन सेकंड तक महसूस किया गया, जिसके दौरान धरती डोलने पर कई लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। हालांकि, उस समय कई लोग नींद में थे, जिस वजह से उन्हें इसका पता नहीं चल पाया। कुछ नागरिकों ने सोशल मीडिया के माध्यम से तेज झटका लगने की जानकारी साझा की।

जम्मू-कश्मीर में नहीं बढेगा बिजली दर , सीएम उमर का बड़ा ऐलान

बारामूला। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बिजली दरों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार आम लोगों पर बिजली की कीमतों का अतिरिक्त बोझ नहीं डालेगी और मौजूदा सरकार के कार्यकाल के साथ-साथ इसके बाद भी बिजली दरों में और बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री उमर ने करहामा, टंगमर्ग के वुस्सन बंगिल में नई फल एवं सब्जी मंडी की आधारशिला रखते हुए यह ऐलान किया।

इस दौरान उमर अब्दुल्ला ने पिछली पीडीपी-भाजपा सरकार पर बिजली दरों में बढ़ोतरी करने का आरोप लगाया। उन्होंने मंगलवार को कहा, कि जब महबूबा मुफ्ती मुख्यमंत्री थीं, उस समय बिजली की दरों में करीब 13.5 से 14 प्रतिशत तक वृद्धि हुई थी। उन्होंने सवाल उठाया कि उस समय इस मुद्दे पर विरोध या सवाल क्यों नहीं उठाए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने जनता पर इसके मुकाबले काफी कम बोझ डाला है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि भविष्य में बिजली की दरों में अनावश्यक बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। सरकार लोगों की परेशानियों को समझती है और आम जनता को राहत देना उसकी प्राथमिकता है।

शिवराज का पलटवार:कांग्रेस ने ही बिगाड़ा एक देश, एक चुनाव का सिस्टम

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस सांसद पी. चिदंबरम द्वारा एक देश, एक चुनाव के विरोध पर तीखा पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री चौहान ने तर्क दिया कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव पहले एक साथ ही होते थे, लेकिन तत्कालीन सत्ताधारी कांग्रेस ने असंवैधानिक तरीकों से व्यवस्था को बिगाड़ दिया। इससे पहले, चिदंबरम ने एक देश, एक चुनाव को संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन बताकर कहा था कि इस 2029 में लागू करना संभव नहीं होगा। उन्होंने संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के समक्ष अपनी बात रखी थी। केंद्रीय मंत्री चौहान ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि 1970 के दशक में विपक्ष की चुनी हुई सरकारों को गिराकर इस सुचारु व्यवस्था को खत्म किया गया था।

मानसून टर्फ और हवा के साइक्लोनिक सकुर्लेशन बारिश का माहौल कर रहे मजबूत

मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी

झारखंड में कई इलाकों में बारिश से राहत की उम्मीद थी, लेकिन मौसम ने फिर करवट ले ली है। झारखंड और आसपास के इलाकों में बने नए लो-प्रेशर के क्षेत्र में सिस्टम सक्रिय हो गया है। आईएमडी ने 23 राज्यों के लिए बारिश, आंधी और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है।

वेब वार्ता, नई दिल्ली

कहीं मूसलाधार बारिश तो कहीं 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं यानी अगले कुछ दिन सफर करने वालों से लेकर किसानों और समुद्र में जाने वाले मछुआरों तक सभी को मौसम पर नजर रखनी होगी। खासकर उन इलाकों में परेशानी बढ़ सकती है जहां पहले से जलभराव या भूस्खलन का खतरा बना हुआ है।

आईएमडी के मुताबिक दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, केरल और पूर्वोत्तर के कई राज्यों समेत 23 राज्यों में बारिश का असर देखने को मिल सकता है। कुछ जगहों पर बारिश के साथ आंधी भी चल सकती है। तेज हवा से पेड़ और बिजली के खंभे गिरने का खतरा भी रहता है। इसलिए मौसम बिगड़ने पर सुरक्षित जगह पर रहना ज्यादा बेहतर होगा।

कमजोर कंस्ट्रक्शन से दूरी बनाये रखने की सलाह

इस मौसम बदलाव की सबसे बड़ी वजह झारखंड और उसके आसपास बना लो-प्रेशर का क्षेत्र है। यह सिस्टम धीरे-धीरे पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में बढ़ने वाला है। इसका असर झारखंड के साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक दिखाई देगा। इसके अलावा मानसून टर्फ और ऊपरी हवा के साइक्लोनिक सकुर्लेशन भी बारिश का माहौल मजबूत कर रहे हैं। आईएमडी के अलर्ट को देखते हुए लोगों को खुले इलाकों, पेड़ों और कमजोर कंस्ट्रक्शन से दूरी बनाए रखने की सलाह दी गई है। तेज बारिश में सड़क पर विजिबिलिटी भी घट सकती है। ऐसे में बिना जरूरत यात्रा करना परेशानी बढ़ा सकता है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में 26 अगस्त को भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।

दिल्ली-एनसीआर में 26 अगस्त को मौसम फिर करवट ले सकता है। आईएमडी ने दिल्ली के सभी प्रमुख इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश में भी मौसम का मिजाज बिगड़ने वाला है। 26 अगस्त को कई जिलों में भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट है। कुछ स्थानों पर 60 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। बिहार में मौसम का असर और ज्यादा तेज नजर आ सकता है। यहां हवा की रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। ऐसे में खुले में खड़े लोगों को खास सावधानी बरतने की जरूरत होगी। पेड़ों और बिजली के तारों से दूरी बनाना जरूरी है।

राजस्थान में भी मानसून का असर कमजोर पड़ता नहीं दिख रहा है। कुछ जिलों में हवा की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। तेज हवाओं में खुले मैदानों और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचने की जरूरत होगी। ग्रामीण इलाकों में भी मौसम की अचानक बदलती स्थिति पर नजर रखना जरूरी होगा। मध्य प्रदेश के कई जिलों में 26 अगस्त को भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी है। इन इलाकों में 50 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। भारी बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव और स्थानीय नदियों-नालों का जलस्तर बढ़ने जैसी स्थिति बन सकती है। लोगों को तेज बारिश के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी जाती है।

उत्तराखंड में बागेश्वर, चंपावत, देहरादून, पिथौरागढ़, ऋषिकेश, हरिद्वार और टिहरी गढ़वाल में भारी बारिश की चेतावनी है। यहां हवा की रफ्तार 55 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश में सोलन, कांगड़ा, ऊना, लाहौल-स्पीति, मंडी, कुल्लू और बिलासपुर समेत कई इलाकों में तेज बारिश की आशंका है।

केरल में भी भारी बारिश ने चिंता बढ़ा दी है। उत्तरी कन्नूर जिले के कुछ हिस्सों में बारिश के कारण भूस्खलन हुआ है। इलायवूर में राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण स्थल पर सुरक्षा दीवार गिरने के बाद स्थिति बिगड़ी. यातायात भी प्रभावित हुआ है। जिला प्रशासन ने प्रभावित इलाकों में गैर-जरूरी आवाजाही से बचने की सलाह दी है। आईएमडी ने केरल के कई जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश वाले पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने को कहा है।

जबलपुर कोर्ट में फर्जी वकील बनकर घूम रहा था युवक

जबलपुर। जबलपुर जिला कोर्ट परिसर में फर्जी वकील बनकर घूम रहे एक युवक का मामला सामने आया है। काला कोट पहनकर कोर्ट पहुंचे युवक पर खुद को अधिवक्ता बताने और हाईकोर्ट बार का फर्जी आई-कार्ड दिखाने का आरोप है। अधिवक्ताओं को शक होने पर कार्ड की जांच कराई गई, जिसमें उसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। शिकायत के बाद ओमती पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जिला कोर्ट परिसर में मंगलवार शाम उस समय हड़कंप मच गया, जब अधिवक्ताओं ने एक युवक को संदिग्ध अवस्था में देखा। युवक काला कोट पहनकर पेशी पर आए लोगों से केस के संबंध में बातचीत कर रहा था। शक होने पर अधिवक्ताओं ने उससे पूछताछ की तो उसने खुद को वकील बताया और हाईकोर्ट बार का आई-कार्ड दिखाया।

कार्ड की जांच में नहीं मिला रिकॉर्ड.....

युवक ने अपना नाम सचिन ताम्रकार बताया। अधिवक्ताओं ने उसके कार्ड पर दर्ज जानकारी की जांच की तो संबंधित नंबर का हाईकोर्ट बार में कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। कार्ड पर बार सचिव के हस्ताक्षर भी दर्ज थे। इसके बाद अधिवक्ताओं ने संदिग्ध युवक को पकड़कर ओमती थाना पुलिस के हवाले कर दिया। अधिवक्ता अरविंद दुबे की शिकायत पर ओमती पुलिस ने सचिन ताम्रकार के खिलाफ बीएनएस की धारा 319(1) और 336(1) के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, सचिन ताम्रकार ने गढ़ा थाना क्षेत्र के ज्योति नगर स्थित अपने घर के बाहर भी एडवोकेट का बोर्ड लगा रखा था। बोर्ड पर उसके नाम के साथ मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर और मोबाइल नंबर दर्ज था। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि वह कब से खुद को अधिवक्ता बताकर लोगों से संपर्क कर रहा था और क्या उसने किसी पक्षकार से केस के नाम पर रुपए या अन्य लाभ लिया है। साथ ही फर्जी आई-कार्ड कहां और किसने तैयार किया, इसकी भी जांच की जा रही है। मामले के बाद अधिवक्ताओं ने लोगों से अपील की है कि किसी व्यक्ति को वकील नियुक्त करने से पहले उसकी बार सदस्यता और पहचान संबंधी दस्तावेजों की पुष्टि जरूर करें। पुलिस के मुताबिक जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

एक्स प्लेनः भारत के किफायती स्पेस मॉडल पर उठे सवाल

श्रीहरिकोटा। भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम लंबे समय से अपनी कम लागत और किफायती इंजीनियरिंग के लिए पूरी दुनिया में सराहा जाता रहा है। 2014 में मंगलयान की पहली बार में ही सफल स्थापना ने भारतीय स्पेस मॉडल को दुनिया का सबसे किफायती कार्यक्रम बना दिया था। हाल ही में, जब भारत अपने ऐतिहासिक चंद्रयान-3 मिशन की सफलता का जश्न मना रहा था, तब एक नए वैज्ञानिक अध्ययन ने इस स्थापित धारणा पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

एक यूरोपीय विश्वविद्यालय और एक इतालवी संस्थान के अर्थशास्त्रियों द्वारा किए गए इस शोध में दावा किया गया है कि प्रति किलोग्राम पेलोड लॉन्च करने की लागत के मामले में भारत, अमेरिका के मुकाबले लगभग चार गुना अधिक खर्च करता है। यह अध्ययन एक प्रतिष्ठित अकादमिक जर्नल में प्रकाशित हुआ है। शोधकर्ताओं ने अमेरिका, यूरोपीय संघ, रूस, चीन, जापान और भारत सहित दुनिया के छह प्रमुख अंतरिक्ष बाजारों में उपग्रह लॉन्च करने की प्रति किलोग्राम लागत का गहन विश्लेषण किया।अध्ययन के आंकड़ों के अनुसार, 2025 के अंत तक भारत में प्रति किलोग्राम उपग्रह लॉन्च की अनुमानित लागत लगभग 12.70 लाख रुपए पाई गई, जो अमेरिका की 3.11 लाख की तुलना में सबसे अधिक है। यह निष्कर्ष इसलिए भी चौंकाने वाला है क्योंकि भारत ने दशकों से खुद को एक ऐसे देश के रूप में प्रस्तुत किया है जो बेहद सीमित बजट में बड़े अंतरिक्ष अभियानों को अंजाम दे सकता है। अतीत में, मंगलयान जैसे मिशनों की तुलना हॉलीवुड फिल्मों के बजट या ऑटो-रिक्शा के किराए से भी की गई है, जो इसकी लागत-प्रभावशीलता को दर्शाती थी। हालांकि, भारतीय अंतरिक्ष बिरादरी ने इन दावों का कड़ा विरोध किया है।

जबलपुर में युवक 37 लाख की ऑनलाइन ठगी का शिकार

जबलपुर। जबलपुर के अधारताल थाना क्षेत्र में 29 वर्षीय युवक से होटल रेटिंग के नाम पर 37 लाख रुपए से अधिक की ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। टेलीग्राम और एक ऐप के जरिए जालसाजों ने युवक को घर बैठे कमाई का झांसा दिया। शुरूआत में मुनाफा देकर भरोसा जीतने के बाद उससे अलग-अलग माध्यमों से लाखों रुपए ट्रांसफर कराए गए। शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

हैदराबाद-विजयवाड़ा जा रही बस ट्रक से टकराई, 6 की मौत

हैदराबाद। तेलंगाना के सूर्यापेट जिले में बुधवार सुबह एक भीषण सड़क हादसे में छह लोगों की मौत हो गई। हादसा करीब सुबह 5:20 बजे दुगार्पुरम स्टेज के पास हुआ, जब हैदराबाद से विजयवाड़ा जा रही एक निजी ट्रैवल बस की ट्रक से टक्कर हो गई। बस में कुल 43 यात्री सवार थे। हादसे में कई यात्री घायल हुए हैं, जिन्हें स्थानीय अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।

सूर्यापेट पुलिस ने मीडिया को बताया, कि यात्री बस हैदराबाद से विजयवाड़ा की ओर जा रही थी। इसी दौरान कोडद मंडल के द्वारकुंटा के पास दुगार्पुरम स्टेज के नजदीक बस की एक कंटेनर ट्रक से टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस में सवार यात्रियों में अफरा-

तफरी मच गई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और राहत दल मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल पहुंचाया।

पुलिस ने बताया कि दुर्घटना में अब तक छह लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि दुर्घटना के वक्त बस और ट्रक की गति कितनी थी और टक्कर किन परिस्थितियों में हुई।

हादसे पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने दुख जताया है। तेलंगाना मुख्यमंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को घायलों के बेहतर इलाज के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। सरकार की ओर से घायलों को हरसंभव चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने को कहा गया है। प्रशासन की प्राथमिकता घायलों को तत्काल उपचार उपलब्ध कराना है।

बांग्लादेश में चोरों ने सोना-चांदी-नगदी नहीं इंसानी बाल चुराकर किया हैरान

वैन से 330 किलो बाल लूटे, कीमत करीब 1 करोड़ टका, दो आरोपी गिरफ्तार

वेब वार्ता, ढाका। बांग्लादेश में चुआडांगा जिले में हथियारबंद बदमाशों ने एक वैन को रोककर 330 किलो इंसानी बाल से भरे 23 बोरे लूट लिए। चोरी किए गए बालों की कीमत करीब 1 करोड़ टका बताई जा रही है जो भारतीय रुपए में 79 लाख है। इस मामले में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। घटना दमुरहुदा इलाके के कोशाघाटा में शनिवार की बताई जा रही है।

पुलिस के मुताबिक 7-8 हथियारबंद लोगों ने बालों से लदी वैन को रास्ते में रोका। इसके बाद बदमाशों ने वैन से बालों से भरे 23 बोरे उतारे और फरार हो गए। आमतौर पर चोरी की घटनाओं में सोना, नकदी, मोबाइल या दूसरे महंगे सामान निशाने पर होते हैं, लेकिन इस मामले में चोरों ने 330 किलो इंसानी बाल लूटे हैं। स्थानीय कारोबारियों के मुताबिक इन बालों की बाजार कीमत 1 करोड़ टका से ज्यादा है। यानी जिस चीज को आम लोग बेकार समझकर फेंक देते हैं, वह बांग्लादेश में एक बड़ा कारोबार बन चुकी है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मामला और भी दिलचस्प इसलिए है क्योंकि ये बाल किसी ब्यूटी पार्लर या दुकान से चोरी नहीं हुए थे। इन्हें एक फैक्टरी से प्रोसेसिंग के लिए ले जाया जा रहा था। बांग्लादेश हेयर प्रोसेसिंग स्मॉल बिजनेस कोऑपरेटिव एसोसिएशन के अध्यक्ष के मुताबिक यह खेप करपसडांगा की एक फैक्टरी भेजी जा रही थी। इसमें 22 कारोबारियों का माल शामिल था यानी एक ही वैन में कई कारोबारियों की करोड़ों की खेप जा रही थी और बदमाशों ने रास्ते में लूट लिया।

वाहनों की रोशनी और सुरक्षा नियमों में संशोधन का प्रस्ताव तैयार

वेब वार्ता, नई दिल्ली

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में संशोधन का एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया है, जिसे अप्रैल दो हजार सत्ताईस से पूरे देश में लागू किए जाने की संभावना है। भारत सरकार देश में सड़क हादसों पर लगाम लगाने और रात के समय ड्राइविंग को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए वाहनों से जुड़े नियमों में एक बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव करने जा रही है। इस नई पहल का मुख्य उद्देश्य सड़क पर चलने वाले वाहनों की रोशनी को अधिक प्रभावी ढंग से नियंत्रित करना, सामने से आने वाली तेज रोशनी के कारण चालकों की आंखों पर पड़ने वाली चकाचौंध को रोकना और खराब मौसम या अंधेरे में भारी वाहनों की दृश्यता में सुधार करना है। यह सरकार का एक दूरगामी कदम है जिसका लक्ष्य भारत की सड़कों को सभी उपयोगकर्ताओं के लिए सुरक्षित बनाना है। ताजा अपडेट के अनुसार, अब नई दोपहिया वाहनों में मिलने वाली स्वचालित हेडलाइट प्रणाली केवल लो-बीम मोड पर ही कार्य करेगी। वर्तमान में, स्वचालित लाइटें कई बार हाई-बीम पर जलती रहती हैं, जिससे सामने से आ रहे अन्य चालकों को रास्ता देखने में काफी परेशानी होती है और दुर्घटना का जोखिम बढ़ जाता है।

नया नियम लागू होने के बाद, जैसे ही स्वचालित लाइटें ऑन होंगी, वे स्वतः ही लो-बीम पर सेट हो जाएंगी। इससे सामने से आ रहे लोगों को गाड़ी चलाने में कोई असुविधा नहीं होगी। हालांकि, यह स्पष्ट किया गया है कि यह नियम केवल भविष्य में निर्मित होने वाली नई गाड़ियों पर लागू होगा, और सड़कों पर पहले से चल रही पुरानी गाड़ियों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इतना ही नहीं, सरकार गाड़ियों की रोशनी की चमक (ब्राइटनेस) को भी कम करने जा रही है ताकि आंखों पर पड़ने वाले तनाव को कम किया जा सके। नए नियमों के तहत, दोपहिया वाहनों की लाइट की अधिकतम चमक सीमा डेढ़ लाख कैंडेला से घटाकर एक लाख कैंडेला की जाएगी। इसी प्रकार, चारपहिया वाहनों के लिए यह सीमा सवा दो लाख कैंडेला से घटाकर डेढ़ लाख कैंडेला निर्धारित की जाएगी।

साथ ही, अत्यधिक सफेद और चुभने वाली रोशनी पर प्रतिबंध लगाने के लिए लाइट का अधिकतम रंग तापमान छः हजार पाँच सौ केल्विन तय किया गया है, जो अधिक आरामदायक और सुरक्षित रोशनी प्रदान करेगा। शहरों के अंदर अनावश्यक रूप से तेज रोशनी (हाई-बीम) का उपयोग करने वाले चालकों को नियंत्रित करने के लिए गाड़ियों में एक नया बीप या आवाज वाला अलर्ट सिस्टम भी देने की तैयारी चल रही है। यदि कोई चालक शहर के भीतर गाड़ी चलाते समय जानबूझकर हाई-बीम ऑन करेगा, तो गाड़ी में एक चेतावनी ध्वनि बजेगी, जो उसे तुरंत लाइट धीमी करने की याद दिलाएगी। हालांकि, यह प्रणाली राजमार्गों पर साठ किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति पर गाड़ी चलाने पर सक्रिय नहीं होगी, क्योंकि अंधेरे राजमार्गों पर दूर तक देखने के लिए तेज रोशनी की आवश्यकता होती है।

रात के अंधेरे और घने कोहरे में होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए बसों और भारी ट्रकों जैसे बड़े वाहनों को लेकर भी नए निर्देश आ रहे हैं। अब ऐसी बड़ी गाड़ियों पर अच्छी गुणवत्ता वाला असली रिफ्लेक्टिव टेप लगाना अनिवार्य किया जाएगा। अक्सर देखा जाता है कि रात में सड़कों के किनारे खड़ी या धीमी गति से चल रही बड़ी गाड़ियाँ अंधेरे में ठीक से दिखाई नहीं देतीं, जिससे पीछे से आ रही गाड़ियाँ उनसे टकरा जाती हैं। रिफ्लेक्टिव टेप लगने से पीछे से आने वाली गाड़ी की रोशनी पड़ते ही ये वाहन दूर से ही चमकने लगेंगे, जिससे रात का सफर कहीं अधिक सुरक्षित हो जाएगा।

संपादकीय

आरक्षण हक नहीं, व्यवस्था है

भारत में आरक्षण की व्यवस्था को समाप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह राजनीति और चुनाव का अमोघ अस्त्र बन चुका है। संविधान में भी अनुच्छेद 340, 341 में उल्लेख है कि सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक विषमताओं, विसंगतियों को खत्म करने और कुछ समुदायों को समानता की मुख्यधारा में लाने को आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई है। यह व्यवस्था आजादी और संविधान लागू होने के बाद सिर्फ 10 सालों के लिए थी, लेकिन 79 साल की आजादी के बाद भी जारी है और उसे निरंतर जारी रखना सरकारों की विवशता भी है। आरक्षण संवैधानिक अधिकार नहीं है, मौलिक अधिकार भी नहीं है, सिर्फ एक व्यवस्था है, जिसे बढ़ाया जाता रहा है। अनुच्छेद 15 और 16 में आरक्षण की शक्ति राज्य को दी गई है, लेकिन सर्वोच्च अदालत यह भी स्पष्ट कर चुकी है कि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं, बल्कि एक व्यवस्था है। संविधान में आर्थिक रूप से गरीब, कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था क्यों नहीं की गई, इसका जवाब हम नहीं दे सकते। क्या ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, भूमिहार आदि सवर्ण वर्ग गरीब नहीं हैं? हमारे पुरखों ने यह कल्पना क्यों नहीं की? क्या उस समय देश में कोई भी सवर्ण कमजोर नहीं था? ये सवाल निरंतर अनुत्तरित रहेंगे। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों के लिए 10 फीसदी का आरक्षण संसद से पारित कराया था, जिसे सर्वोच्च अदालत ने भी न्यायिक माना, लेकिन वह पर्याप्त नहीं है। दरअसल रूढ़ि और विसंगतियां आरक्षण की व्यवस्था में हैं। उस संदर्भ में सर्वोच्च अदालत ने क्रीमी लेयर का फैसला सुनाया था। क्रीमी लेयर की आय-सीमा 8 लाख रुपए सालाना तय है। उससे अधिक आय वाले आरक्षित वर्गों के बच्चों को आरक्षण नहीं मिलेगा। लेकिन यह न्यायिक व्यवस्था पूरी तरह लागू नहीं है। हम ऐसे कई परिवारों को जानते हैं, जिनमें पीढ़ी-दर-पीढ़ी आईएएस, आईपीएस अधिकारी हैं। उनके परिवारों को आरक्षण क्यों चाहिए? या क्यों दिया जाना चाहिए? लोकसभा में 131 सांसद आरक्षित हैं। अनुसूचित जाति के 84 और जनजाति के 47 सांसद हैं।

राज्यों की विधानसभाओं में भी सैकड़ों आरक्षित विधायक हैं। मंत्री, राज्यमंत्री और अन्य पदों पर भी आरक्षित चेहरे हैं। यदि राष्ट्रीय स्तर के चेहरों का उल्लेख करें, तो बसपा प्रमुख एवं उप्र की चार बार मुख्यमंत्री रहीं मायावती, लोकसभा सांसद एवं उप्र के ही पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और रामदास अठावले आदि के परिवारों और बच्चों को आरक्षण क्यों मिलना चाहिए? पासवान परिवार में रामविलास पासवान (अब दिवंगत) के समय से भाई, भतीजा, दामाद सभी सत्ता में रहे अथवा सांसद-विधायक रहे। आखिर सामाजिक पिछड़ेपन, विषमताओं से उबरने का मापदंड क्या है? यह सरकारों ने तय नहीं किया और सर्वोच्च अदालत ने भी कोई फैसला नहीं सुनाया। राजनीति और सरकारें तो आरक्षण के सामने नतमस्तक हैं, बंधक बनी हैं। क्रीमी लेयर की परवाह कौन करता है? आप शिक्षित हैं, आर्थिक रूप से सम्पन्न हैं, सामाजिक रुतबा भी है, विषमताओं से बाहर आने का और क्या आधार होना चाहिए? हम यह विश्लेषण इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि सवर्ण युवाओं ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन किया था। उन्होंने यह मुद्दा उठाते हुए आरक्षण की समीक्षा करने, उसमें सुधार करने की मांग की है। वे खुद को संवैधानिक अछूत मान रहे हैं। यह नौबत क्यों आई? वे भी जेन-जी के चेहरे हैं। वे प्रतिभाशाली हैं, अच्छे अंकों से परीक्षाएं पास कर रहे हैं, लेकिन उनकी सामान्य श्रेणी की इतनी रिक्तियां नहीं हैं कि उन्हें नौकरी मिल सके। आरक्षण का मुद्दा उठा है, तो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जैसे नेतागण इस मुद्दे पर विमर्श को ही तैयार नहीं हैं। आरक्षण को संवैधानिक अधिकार करार दे रहे हैं। विपक्ष ने एक बार फिर नेरेटिव गढ़ना शुरू कर दिया है कि भाजपा-संघ आरक्षण के साथ-साथ संविधान को भी खत्म करना चाहते हैं। यही नेरेटिव 2024 के लोकसभा चुनाव में इस्तेमाल किया गया था। गृहमंत्री अमित शाह संसद में वक्तव्य दे चुके हैं कि यदि बाबा अंबेडकर भी आज आ जाएं, तो भी आरक्षण खत्म नहीं होगा। समीक्षा में क्या दिक्कत है? सवर्ण भी देश के नागरिक हैं।

उच्च शिक्षा का काला सच

हजारों योग्य नेट-पीएचडी धारक शिक्षक 15 से 20 हजार रुपए के मानदेय पर ठेके पर पढ़ाने को मजबूर हैं। जिस शिक्षक के पास खुद का भविष्य सुरक्षित नहीं है, वह छात्रों के भविष्य का निर्माण कैसे करेगा? फर्जी जर्नल्स और कट-कॉपी-पेस्ट रिसर्च हो रही है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का पेटेंट और मौलिक शोध में योगदान बेहद कम है। अकादमिक तरक्की पाने के लिए पेड जर्नल्स में नकली शोध पत्र छपवाने का एक पूरा रैकेट फल-फूल रहा है।

देश में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या में वृद्धि चिंता का कारण है। आज से 40-50 साल पहले व्यवसायी का बच्चा 10-12 क्लास पढ़ कर व्यापार में लग जाता था और कुछ लोगों को नौकरी भी देता था। आज उनके बच्चे भी नौकरी देने के बजाय उच्च शिक्षा प्राप्त कर नौकरी की लाइन में खड़े हो गए हैं। इधर पढ़ने के बाद सबको आराम की नौकरी चाहिए। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा लोग सरकारी नौकरी खोजते हैं। शिक्षित युवा छोटा काम करने से गुरेज करते हैं। जब यह मानसिकता हावी रहेगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। इसके लिए हमारा उच्च शिक्षा का सिस्टम भी जिम्मेवार है। आईये, इस सिस्टम की वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पड़ताल करें। हमेशा से भारतीय समाज में शिक्षा को सदियों से बौद्धिक उत्थान का माध्यम माना गया था। आधुनिक दौर में इसका स्थान आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक प्रतिष्ठा की गारंटी ने ले लिया है। बचपन में जब कोई बच्चा पहली बार स्कूल जाता है, तो परिवार और समाज मिलकर उसके दिल और दिमाग में एक ही विचार ठोकते जाते हैं कि बस बारहवीं पास कर लो, फिर जीवन संवर जाएगा। बारहवीं के बाद यह वादा ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन तक खिसक जाता है। माता-पिता अपनी जीवनभर की जमा पूंजी, जमीन-जायदाद या पेंशन का पैसा दांव पर लगाकर संतान को हायर एजुकेशन की अंधी दौड़ में झोंक देते हैं। वर्षों की मेहनत और लाखों के खर्च के बाद जब यह युवा डिग्री लेकर बाजार में खड़ा होता है, तो जीवन की हकीकत का काला सच उसके सारे भ्रम तोड़ देता है। तब अहसास होता है कि जिस व्यवस्था को छात्र अच्छा भविष्य समझ रहा था, वह असल में उसकी उम्मीदों का शमशान साबित हुई। आज उच्च शिक्षा रूपी उद्योग हर साल लाखों की तादाद में इंजीनियर, डॉक्टर, एमबीए, वकील और आर्ट्स-साइंस ग्रेजुएट्स तैयार करने वाली एक विशाल डिग्री फैक्टरी बन चुका है। लेकिन इस संख्यात्मक विकास के पीछे गुणात्मक पतन का एक भयावह सच छिपा है। विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय रोजगार सर्वेक्षणों के आंकड़े बताते हैं कि देश के लगभग 50 प्रतिशत से अधिक ग्रेजुएट सीधे तौर पर उद्योग की जरूरतों के अनुरूप नहीं हैं।

इसको कौन ठीक करेगा? विश्वविद्यालयों का पाठ्यक्रम आज की तकनीकी क्रांति (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, ऑटोमेशन) से कोसों दूर दशकों पुराने ढर्रे पर चल रहा है। कॉलेज कक्षाओं में छात्रों को कुछ नया करना या समस्या समाधान नहीं

सिखाया जाता, बल्कि केवल परीक्षा पास करने के लिए सिद्धांतों को रटने की कला सिखाई जाती है। नतीजा यह है कि हाथ में प्रथम श्रेणी की डिग्री होने के बावजूद युवा एक साधारण फॉर्म भरने या ईमेल ड्राफ्ट करने में असहज महसूस करते हैं। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? हायर एजुकेशन का प्रवेश द्वार अब एक बहु-अरब डॉलर के कोचिंग उद्योग से होकर गुजरता है। कोटा, दिल्ली, पटना, हैदराबाद और इंदौर जैसे अनेक शहर अब ज्ञान के केंद्र नहीं, बल्कि फैक्टरियों में तब्दील हो चुके हैं। 13-14 साल के बच्चों को स्कूल छोडकर 14-16 घंटे कोचिंग और टेस्ट सीरीज के अंतहीन भंवर में डाल दिया जाता है। नीट से पैदा हुई परेशानियों को कौन भूल सकता है। होर्डिंग्स पर चमकते टॉपर्स के चेहरों के पीछे उन लाखों गुमनाम छात्रों की चीखें दब जाती हैं जो अफलता के डर, एकाकीपन और परिवार की भारी अपेक्षाओं के बोझ तले दब जाते हैं। हर साल आने वाली छात्रों की आत्महत्याओं और डिप्रेशन की खबरें इस बात का प्रमाण हैं कि यह व्यवस्था युवाओं को भविष्य देने के बजाय उनका वर्तमान छीन रही है। इसे कौन ठीक करेगा? शिक्षा का यह बाजारीकरण मध्यमवर्गीय परिवारों की जेब और युवाओं की मानसिक शांति दोनों को खाली कर रहा है। पिछले दो दशकों में निजी शिक्षण संस्थानों की जो बाढ़ आई है, उसने शिक्षा को एक शुद्ध मुनाफा कमाने वाले व्यवसाय में बदल दिया है। संगमरमर से सजे परिसर, एसी क्लासरूम, गोल्फ कोर्स और स्विमिंग पूल दिखाकर लाखों रुपए की फीस वसूली जाती है।

लेकिन जब बात फैकल्टी और लैब की गुणवत्ता की आती है, तो ये संस्थान पूरी तरह खोखले साबित होते हैं। अनेक अध्यापकों को अनेक जगह पर मजदूर से कम अदायगी हो रही है। न्यूनतम उपस्थिति और बिना किसी बौद्धिक मशक्कत के ग्रेड्स बांटे जाते हैं ताकि अगले साल के दाखिलों के लिए आकर्षक ब्रोशर तैयार किए जा सकें। शिक्षा के इस व्यवसायीकरण ने एक गहरी सामाजिक खाई पैदा कर दी है। जहां धनाढ्य वर्ग का औसत छात्र मोटी फीस देकर मैनेजमेंट कोटा से डिग्री हासिल कर लेता है, वहीं प्रतिभाशाली गरीब छात्र फीस के अभाव में प्रवेश से वंचित रह जाता है। मध्यमवर्गीय परिवार अपने जीवन की सारी सुरक्षा त्यागकर बच्चों की उच्च शिक्षा में निवेश करते हैं। इसे वे अपने भविष्य की सबसे सुरक्षित एफडी मानते हैं। लेकिन इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बेहद निराशाजनक है। जब 20 लाख रुपए का एजुकेशन लोन लेकर पढ़ाई पूरी करने वाले युवा को 15000 रुपए की नौकरी मिलती है, तो वह लोन की किस्त चुकाने में ही असमर्थ हो जाता है। चपरासी या नगर निगम की सफाई कर्मचारी भर्ती में जब पीएचडी और एम.टेक पास युवा कतार में खड़े दिखते हैं, तो यह केवल बेरोजगारी का संकट नहीं, बल्कि पूरी शिक्षा व्यवस्था के दिवालियापन का प्रमाण है। इसके लिए कौन जिम्मेवार है। किसी भी उच्च शिक्षण संस्थान की रीढ़ उसके शिक्षक और शोध की संस्कृति होती है।

भारत की अधिकांश यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों में यह रीढ़ ही टूटी हुई है। हजारों योग्य नेट-पीएचडी धारक शिक्षक 15 से 20 हजार रुपए के मानदेय पर ठेके पर पढ़ाने को मजबूर हैं। जिस शिक्षक के पास खुद का भविष्य सुरक्षित नहीं है, वह छात्रों के भविष्य का निर्माण कैसे करेगा? फर्जी जर्नल्स और कट-कॉपी-पेस्ट रिसर्च हो रही है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का पेटेंट और मौलिक शोध में योगदान बेहद कम है। अकादमिक तरक्की पाने के लिए पेड जर्नल्स में नकली शोध पत्र छपवाने का एक पूरा रैकेट फल-फूल रहा है। अनेक राज्यों में उच्च शिक्षा का पूरा सिस्टम ही लीपापोती का शिकार हो चुका है। इस निराशाजनक दलदल से बाहर निकलने के लिए केवल नारों की नहीं, बल्कि बुनियादी और कठोर सुधारों की जरूरत है। कौशल-आधारित शिक्षा की आवश्यकता है। समाज को यह समझना होगा कि हर किसी के लिए परंपरागत कॉलेज डिग्री जरूरी नहीं है। कारपेंट्री, प्लंबिंग, डिजाइनिंग, कोडिंग और नर्सिंग जैसे वोकेशनल ट्रेड्स को सामाजिक प्रतिष्ठा और बेहतर आर्थिक विकल्प के रूप में स्थापित करना होगा। डिग्री केवल कागज का एक टुकड़ा है, यदि उसके पीछे ज्ञान, कौशल और आत्मनिर्भरता की ताकत न हो। यदि हमने तुरंत अपनी उच्च शिक्षा की दिशा और दशा को नहीं बदला, तो यह डिग्रियों का समुंदर देश के जनसांख्यिकीय लाभांश को एक जनसांख्यिकीय आपदा में बदल देगा। शिक्षा को बाजार के चंगुल से छुड़ाकर वापस ज्ञान और सशक्तीकरण का माध्यम बनाना आज के समय की सबसे बड़ी राष्ट्रीय आवश्यकता है। लेकिन इसे कौन करेगा?

डा. वरिंद्र भाटिया
कालेज प्रिंसीपल

भूत को छोड़ो, वर्तमान और भविष्य की चिंता करो

भारत की राजनीति पिछले तीन दशकों से लगातार भूतों के सहारे चल रही है। कभी बोफोर्स, कभी 2जी, कभी कोयला घोटाला, कभी राम मंदिर, कभी स्वतंत्रता आंदोलन, कभी नेहरू-गांधी परिवार, कभी भारत-पाकिस्तान विभाजन और अब दशकों पुराने घटनाक्रमों की फाइलें खोलकर राजनीति को वर्तमान से हटाकर अतीत में धकेला जा रहा है। सवाल यह है, क्या भूतों को बार-बार कब्र से निकालने से देश का भविष्य बनेगा? बोफोर्स का मामला दशकों तक राजनीतिक हथियार बना रहा। जांच हुई, अरबों रुपए खर्च हुए, देश-विदेश में यात्राएं हुईं, राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप चलते रहे। अंततः फाइल बंद करना पड़ी, क्योंकि कोई भी सबूत नहीं मिला। हां राजनीति से गांधी परिवार जरूर बाहर हो गया। 1989 से लेकर 2026 तक गांधी परिवार का कोई भी सदस्य सरकार के किसी पद पर नहीं रहा। यह सत्य है। इसी तरह मनमोहन सिंह सरकार के समय लगाए गए कई बड़े घोटालों के आरोप, जांच और न्यायिक प्रक्रिया में अलग-अलग रूप में सामने आए। 2जी और कोयला आवंटन इसके उदाहरण हैं। कैग के तत्कालीन सर्वेसर्वा विनोद राय ने कथनी और करनी को लेकर क्षमा भी मांग ली। साजिश एवं राजनीति की इन घटनाओं से सबक लेने के बजाय उन्हें सत्ता तक पहुंचाने के लिए सीढ़ी बना लेने से आज देश स्वतंत्रता के समय की स्थिति में पहुंचने जा रहा है।

2012 के बाद तो जैसे अतीत ही राजनीति का सबसे बड़ा हथियार बन गया है। सवाल यह नहीं है, आज रोजगार कहां है, शिक्षा कैसी है, स्वास्थ्य व्यवस्था क्यों कमजोर है, किसानों की आय और युवाओं का भविष्य क्या होगा। करोड़ों डिग्रीधारी और असंगठित क्षेत्र के युवा बेरोजगार हैं। लाखों स्कूल बंद हो गए हैं। अनपढ़ों की जमात बढ़ती जा रही है। 35, 50 या 75 साल पहले किसने क्या गलती की थी? इस पर राजनीति हो रही है। ऐसी स्थिति में वर्तमान और भविष्य कैसे सुधरेगा? 1998 का जम्मू-कश्मीर वंधामा नरसंहार की जांच फिर से शुरू करने की चर्चा सामने आ रही है। उस घटना में 23 लोगों की हत्या हुई थी, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी थे। अपराधियों को सजा और पीड़ितों को न्याय पहले भी दिया जा चुका है। सवाल यह है, न्याय और राजनीति के बीच की सीमा कौन तय करेगा? जो पहले हुआ है, वह सही है, या गलत है। सत्ता की लड़ाई में पुराने जख्मों को भरने के बजाय उन्हें कुरेदकर कश्मीरी पंडित बनाम मुसलमान के बीच एक नई खाई तैयार की जा रही है? भूत को न्याय देना, भूत के सहारे राजनीति करना यह दो अलग बातें हैं। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है, जो चला गया, वह वापस नहीं आता। मृत्यु के बाद जीवन रुकता नहीं है। परिवार को आगे बढ़ना पड़ता है। बच्चों को भोजन चाहिए, शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए। इसलिए मृत शरीर को सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार के रूप में विदा करके हम उसे भूलते हैं। यह कहने में कठोर लग सकता है, लेकिन यही जीवन का सत्य है। राष्ट्र भी इसी नियम से चलता है। भारत मे कब तक कब्रें खोद-खोदकर हम भूतों को निकालते रहेंगे?

आज देश में राज्य सरकार, केंद्र सरकार, स्थानीय प्रशासन और आम आदमी कर्ज बढ़ने से हैरान और परेशान है। 20 करोड़ लोगों के पास कोई काम नहीं है। रोजगार की चुनौती, कमजोर होती सार्वजनिक व्यवस्थाओं, बंद होते स्कूलों, महंगी शिक्षा, चिकित्सा और 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज, तथा सरकारी सहायता पर निर्भरता बुनियादी सवाल हैं। सामाजिक व्यवस्था धर्म और जाति के संघर्षों में उलझती जा रही है। देश की राजनीति बार-बार अतीत में लौट जाती है।

जनरेशन-जी और जनरेशन-अल्फा इस राजनीति को अलग नजर से देख रही है। यह पीढ़ी मोबाइल, इंटरनेट और डिजिटल दुनिया के बीच पैदा होकर बड़ी हुई है। उसके लिए 50 साल पहले क्या हुआ, यह इतिहास है, उसके लिए आज नौकरी मिलेगी या नहीं, शिक्षा कैसी होगी, तकनीक उसके जीवन को कैसे बदलेगी, भविष्य सुरक्षित होगा या नहीं,यह उसकी वास्तविक चिंता है। नई पीढ़ी अपने मां-बाप से कह रही है, आपने जो किया, वह इतिहास बन गया है। हमारी आज की जरूरतें पूरी करें। यदि आप हमारी जरूरत पूरी नहीं कर सकते हैं, तो अपना भविष्य हम स्वयं बनाएंगे। यह संदेश सत्ता और व्यवस्था में बैठे लोगों को समझना होगा।

न्यायपालिका को भी समझना होगा। भारतीय संविधान ने मौलिक अधिकारों के साथ नागरिक अधिकार पैदा किए हैं। ध्यान रखना होगा, भूख और बेरोजगारी का कोई धर्म नहीं होता है। खाली पेट की भीड़ को धर्म एवं इतिहास नहीं, रोटी पानी की जरूरत होती है। बेरोजगार युवा को पुरानी लड़ाइयां नहीं, वर्तमान में रोजगार और नौकरी चाहिए। बीमार व्यक्ति को भाषण नहीं, चिकित्सा के लिए अस्पताल चाहिए। विद्यार्थी को अतीत की बहस नहीं, अच्छी शिक्षा के अवसर चाहिए।

सत्ता में बने रहने के लिए यदि हर बार नया भूत निकाला जाएगा। एक दिन वर्तमान सत्ता इतनी कमजोर हो जाएगी। भविष्य के लिए उसके पास कुछ नही बचेगा। सबसे बड़ा खतरा यही है। भूतों के साथ रहते-रहते भूत न बन जाएं। भारत की राजनीति को अब भूत से निकालकर वर्तमान और भविष्य के लिए प्रयोग शालाओं, स्कूलों, अस्पतालों, उद्योगों और रोजगार तकनीकी और शोध के मैदान में सारी दुनिया के साथ प्रतिस्पर्धा के लिए मैदान में आना होगा। अतीत से सीखना जरूरी होता है, अतीत में रहना आत्मघाती होता है। समय गतिशील है, वर्तमान और भविष्य भी इस गतिशीलता से बदलता है। अतीत मे अटक कर वर्तमान और भविष्य को खो देते हैं। भूतों को इतिहास के पन्नों में रहने दीजिए, वर्तमान को बचाइए। भविष्य का निर्माण वर्तमान से जुड़ने पर होगा। यही वर्तमान भारत की सबसे बड़ी जरूरत है।

(लेखक- सनत जैन)

हमारे देश में पिछले एक दशक से भारत को विश्वगुरु बनाने का ढोल पीटा जा रहा है। इसी विमर्श के समानांतर इस समय देश में शिक्षा को लेकर भी बड़ी बहस छिड़ी हुई है। अतः इसी सन्दर्भ में यह सवाल भी जरूरी हो गया है कि क्या शिक्षा के बिना या शिक्षित हुये बिना भी भारत विश्वगुरु बन सकता है? नीति आयोग और शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट बताती है कि पिछले एक दशक में देशभर में लगभग 94,000 सरकारी स्कूल या तो पूरी तरह बंद किये जा चुके हैं या उनका अन्य स्कूलों में विलय कर दिया गया है।

शिक्षित राष्ट्र के बिना विश्व गुरु की अवधारणा बेमानी

यूडीआईएसई अर्थात यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफोर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन के हालिया आंकड़े व नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, एक साल के भीतर देश भर में 4,791 स्कूल बंद हुए हैं। इसकी वजह से शहरों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी निजी स्कूलों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। परिणामस्वरूप शिक्षा गरीबों की पहुँच से दूर हो चुकी है। और जो स्कूल चल भी रहे हैं उनमें से अधिकांश की हालत किसी से छुपी नहीं है। यहाँ अक्टूबर 2022 की गुजरात की उस घटना का जिक्र भी प्रासंगिक है जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधीनगर के अडालज में मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस के शुभारंभ के दौरान अस्थाई रूप से बनाये गये एक मॉडल क्लासरूम में बच्चों के साथ बैठे नजर आये थे। सरकार के अनुसार, इस योजना का उद्देश्य गुजरात के सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब और डिजिटल बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण करना बताया गया था। उस समय विपक्षी नेताओं ने दावा किया कि प्रधानमंत्री जिस क्लासरूम में बैठे थे, वह एक अस्थायी या कृत्रिम क्लासरूम था। संबंधित तस्वीरों का हवाला देते हुए दीवारों और खिड़कियों के पेंटिंग के स्टिकर होने का दावा किया गया था और इसे फोटो शूट करार दिया था। परन्तु अधिकारियों ने इसके जवाब में यह कहा था कि यह आगामी डिजिटल स्मार्ट स्कूलों का एक मॉडल प्रस्तुतीकरण था जो यह प्रदर्शित करने के लिए था कि भविष्य के क्लास रूम कैसे नजर आयेंगे। तो सवाल यह है कि गत चार वर्षों में मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस योजना के तहत अब तक उन मॉडल क्लासरूम की तरह देश में कितने आधुनिक क्लासरूम व आधुनिक स्कूल बनाये गये?

दूसरी ओर इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार के दौरान अमेरिका की प्रथम महिला मेलानिया ट्रम्प ने 25 फरवरी 2020 को नई दिल्ली के मोतीबाग स्थित सर्वोदय सह-शिक्षा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का दौरा किया था। दिल्ली के सरकारी स्कूलों और यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को देखने के लिए कई अन्य विदेशी मेहमान और प्रतिनिधिमंडल भी आ चुके हैं। समय-समय पर विभिन्न देशों के शिक्षाविद, राजनयिक और प्रतिनिधिमंडल दिल्ली के सरकारी स्कूलों की बुनियादी संरचना, कक्षाओं और शैक्षणिक गतिविधियों का निरीक्षण करने दिल्ली आते रहे हैं। क्या इसी तरह के आधुनिक सरकारी स्कूल पूरे देश में संचालित नहीं हो सकते? क्या वजह है कि देश के अधिकांश राज्यों में अनेकानेक सरकारी स्कूल भवन जर्जर हैं? कहीं स्कूल में भैंसों के तबेले हैं तो कहीं पेड़ के नीचे व खुले आसमान तले क्लास लगाई जा रही है। कहीं क्लासरूम नहीं। कहीं अध्यापक नहीं तो कहीं बिजली व पीने का पानी नहीं तो कहीं शौचालय नहीं। कहीं बच्चे रोज नदी पार कर स्कूल आते जाते हैं तो कहीं कीचड़ और दलदल भरी गड्ढेदार सड़कों से गुजर कर स्कूल आना जाना होता है। यदि देश की सरकारें शिक्षा के प्रति गंभीर होतीं और उनका भारत को विश्वगुरु बनाने का ढिंढोरा महज ढोल पीटना न होता तो आज सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले को महाराष्ट्र में शिक्षा पर घटते बजट और सरकारी मराठी माध्यम के स्कूलों के बंद होने पर गहरी चिंता जताते हुये यह न कहना पड़ता कि नासिक कुंभ मेले के लिए लगभग 32,000 करोड़ का भारी-भरकम बजट तय किया गया है। अगर इस राशि का मात्र 0.1% यानी लगभग 32 करोड़ भी शिक्षा पर खर्च किया जाता, तो राज्य के 100 से 125 बंद हो रहे मराठी स्कूलों को बचाया जा सकता था। आखिर जस्टिस प्रसन्ना को क्यों कहना पड़ा कि देश में छात्रों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन शिक्षा का बजट बढ़ने के बजाय घट रहा है, जो पिछले कई वर्षों से 13% के आंकड़े को भी नहीं छू सका है। उन्होंने गढ़चिरौली की एक घटना का उदाहरण भी दिया जहां जरूरी सुविधाओं की कमी के कारण फर्श पर सोने की वजह से तीन छात्राओं की सांप के काटने से मौत हो गई थी। जस्टिस प्रसन्ना ने यह भी बताया कि उन्होंने स्वयं 10वीं कक्षा तक की पढ़ाई जिला परिषद के मराठी मीडियम स्कूल से की थी, जिसने उनके करियर में कभी बाधा नहीं डाली बल्कि उनके दृष्टिकोण को और व्यापक बनाया। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार को यह नहीं भूलना चाहिए कि प्राथमिक शिक्षा और स्वास्थ्य हर नागरिक का मूलभूत अधिकार है।

देश में बढ़ती बेरोजगारी, शिक्षा,शिक्षण संस्थाओं की कमी व दुर्दशा तथा परीक्षा व्यवस्था में होने वाली धांधलियों व पेपर लीक जैसे मुद्दों ने देश के युवाओं को आंदोलन करने पर मजबूर कर दिया है। इससे घबराई सरकार कहीं स्कूल की वीडिओ ग्राफी करने पर रोक लगा रही है तो कहीं शिक्षण संस्थाओं की हक़ीकत को उजागर करने वालों पर सत्ता समर्थित गुंडों द्वारा हमला किया जा रहा है। और कहीं सोशल मीडिया पर सरकारी स्कूल की अव्यवस्थाएं दिखाने पर लोगों को जेल भेजा जा रहा है। परन्तु इस बीच कुछ जगहों से सकारात्मक खबरें भी आनी शुरू हुई हैं। जैसेकि राजस्थान के रामपुरा के उस स्कूल का नवनिर्माण करने का फैसला किया गया है जहाँ कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकताओं के साथ सत्ता के समर्थक गुंडों ने मारपीट की थी। यह स्कूल भैंसों के तबेले में चल रहा था। स्कूल की इमारत जर्जर होने के कारण एक स्थानीय ग्रामीण ने अपनी निजी जगह दी हुई है, इसी जगह भैंसों का चारा भी रखा जाता है और बच्चे भी पढ़ते हैं। पंजाब से भी खबर है कि सरकार ने स्कूलों के अनेक नए भवन बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इन ग्रीनफील्ड भवनों का निर्माण मौजूदा जमीनों से परे अन्य खाली जमीनों पर नए सिरे से किया जाएगा। हरियाणा में भी शिक्षा मंत्री द्वारा सरकारी स्कूल्स का औचक निरीक्षण कर विद्यालय की व्यवस्थाओं एवं शैक्षणिक गतिविधियों का जायजा लेने व विद्यार्थियों से संवाद करने की खबर है। Geaf Z और युवा पीढ़ी के आंदोलन से ही सही परन्तु शायद अब सत्ताधीशों को यह बात समझ आने लगी है कि शिक्षित राष्ट्र के बिना विश्व गुरु की अवधारणा पूरी तरह बेमानी है।

(लेखिका- निर्मल रानी)

(यह लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं इससे संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है)

आलेख

सरकारी स्कूल सोशल मीडिया के लिए मंच नहीं है

आजकल सरकारी स्कूलों के प्रति लोगों का नजरिया एक चलन बनता जा रहा है, और यह अच्छा नहीं है। फोन, कैमरा और कैमरा-युक्त स्मार्टफोन होते ही लगभग कोई भी सरकारी स्कूल में जाकर शिक्षकों से सवाल पूछ सकता है, कक्षाओं की तस्वीरें खींच सकता है और कुछ ही मिनटों में पूरी शिक्षा व्यवस्था के बारे में अपनी राय बना सकता है। कभी-कभी, यह इरादा नेक होता है। नागरिकों को शिक्षा की गुणवत्ता, सार्वजनिक संस्थानों के कामकाज और बच्चों के भविष्य के बारे में चिंतित होने का पूरा अधिकार है।

इसका मतलब यह है कि एक सीधा-सा सवाल अक्सर उठाया जाता है, लेकिन उस पर शायद ही कभी ध्यान दिया जाता है: निरीक्षण को लेकर यह उत्साह अक्सर सरकारी स्कूलों तक ही सीमित क्यों रहता है? कितनी बार स्वघोषित निरीक्षक बड़ी मुश्किल से और घड़ी की चुभती निगाहों से देखते हुए कुलीन निजी स्कूलों में घुसते हैं और वहाँ की फीस, बुनियादी ढाँचे, प्रवेश नीतियों, शिक्षकों के कार्यभार, परिवहन या अन्य किसी भी चीज के बारे में और भी अटपटे सवालों का सामना करते हैं? लोग महंगे निजी स्कूलों के गेट पर कैमरा लेकर घुस जाते हैं और शिक्षकों से सवाल पूछने लगते हैं। जवाब स्पष्ट है। हर निजी स्कूल की अपनी विशिष्ट प्रवेश प्रक्रिया, सुरक्षा, प्रशासन और फोटोग्राफी/रिकॉर्डिंग की सीमाएँ होती हैं। बिना अनुमति के किसी को भी कक्षाओं में घूमने की अनुमति नहीं दी जाएगी। दूसरी ओर, सरकारी स्कूलों में अक्सर खुला और सुलभ वातावरण होता है। वे समाज के कमजोर वर्गों और निम्न आर्थिक स्तर के बच्चों का पालन-पोषण करते हैं। वे खुले तो हैं, लेकिन नियमों से मुक्त नहीं हैं। हर पहुँच का मतलब पूर्ण अधिकार नहीं होता।

सरकारी विद्यालयों के शिक्षक सरकार, विद्यालय प्रशासन, अभिभावकों, छात्रों और कानून के प्रति उत्तरदायी होते हैं। उन्हें उचित संस्थागत माध्यमों से अपने पेशेवर कर्तव्यों के संबंध में पूछताछ का अधिकार और दायित्व दोनों है। हालांकि, उचित निरीक्षण और अनौपचारिक निगरानी में स्पष्ट अंतर होता है। अधिकृत निरीक्षण प्रशासन के निर्धारित ढांचे के भीतर होता है। इसके लिए प्रक्रियाएं, रिकॉर्ड, जिम्मेदारियां और जवाबदेही आवश्यक हैं। किसी परिसर में मोबाइल फोन रखना और बिना अनुमति के शिक्षकों की रिकॉर्डिंग करना दिखावा हो सकता है, लेकिन दिखावा निरीक्षण नहीं है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि शैक्षणिक संस्थानों में पारदर्शिता और गरिमा की आवश्यकता है।

यहां एक और बड़ा सवाल उठता है: शिक्षकों की गरिमा। शिक्षक कक्षाओं में बैठे सरकारी अधिकारी नहीं होते। वे विशेषज्ञ होते हैं जो बच्चों के बौद्धिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास के लिए जिम्मेदार होते हैं। ऐसी प्रक्रियाएं होनी चाहिए जिनसे यह पता चल सके कि कोई शिक्षक अपने कर्तव्य में विफल हो रहा है, इसकी जांच की जाए और यदि शिक्षक वास्तव में विफल हो रहा है तो सुधारात्मक कार्रवाई की जाए। हालांकि, आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि शिक्षकों को सार्वजनिक रूप से अपमानित करना, बिना अनुमति के उनकी रिकॉर्डिंग करना या सोशल मीडिया पर चुनिंदा वीडियो पोस्ट करना यह जरूरी नहीं दशार्ता कि इससे शिक्षा का स्तर बेहतर हो रहा है। इसके विपरीत, इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। यदि हर बातचीत सोशल मीडिया पर वायरल होने की संभावना बन जाए, तो शिक्षक छात्रों के साथ स्वाभाविक रूप से बातचीत करने की बजाय उनके द्वारा रिकॉर्ड किए जाने को लेकर अधिक चिंतित हो सकते हैं। कक्षा धीरे-धीरे एक प्रदर्शन स्थल में बदल सकती है और वायरल कंटेंट की होड़ में शिक्षा का उद्देश्य भुलाया जा सकता है।

इसका यह मतलब बिलकुल नहीं है कि सरकारी स्कूलों को जांच से छूट मिलनी चाहिए। बल्कि इसके विपरीत। सार्वजनिक धन और उससे भी अधिक महत्वपूर्ण, बच्चों के भविष्य से जुड़े मामलों में, सरकारी स्कूलों को पारदर्शी और जवाबदेह होना चाहिए। इसलिए शिक्षक और प्रशासक अपने कर्तव्यों के प्रति जवाबदेह हैं। माता-पिता और नागरिक निःसंकोच अपनी चिंताओं को व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन उचित मंच पर चिंताएं उठाना एक बात है और अनधिकृत निरीक्षण और सोशल मीडिया पर परीक्षण के माध्यम से उन्हें उठाना बिलकुल अलग बात है।

शिक्षा प्रशासन के क्षेत्र में वास्तव में रुचि रखने वालों के लिए व्यवस्था के भीतर रहकर सार्थक योगदान देने का एक वैध तरीका भी है। तो क्यों न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी या अन्य प्राधिकरण पदों के लिए आवेदन करें? कड़ी मेहनत करें, योग्यता प्राप्त करें, नियमों को जानें, जिम्मेदारी लें और सरकार द्वारा प्रदत्त अधिकार के साथ विद्यालयों में प्रवेश करें। इस स्तर पर, निरीक्षणकर्ता और शिक्षक के बीच संबंध में महत्वपूर्ण बदलाव आता है। एक अधिकृत शिक्षा अधिकारी केवल कमियों को इंगित नहीं करता। एक अधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उन कमियों के कारणों को समझे, अभिलेखों की समीक्षा करे, कार्यान्वयन का मूल्यांकन करे, शिक्षकों का मार्गदर्शन करे, व्यवस्थागत मुद्दों को उजागर करे और समाधान खोजने में सहायता करे। निरीक्षण और हस्तक्षेप में यही अंतर है।

एक समस्या को कैमरे से पल भर में पहचाना जा सकता है, लेकिन एक सक्षम प्रशासक को समस्या के कारणों का पता लगाने और उसे हल करने के लिए आवश्यक संसाधनों, प्रशिक्षण, नीति या संस्थागत सहायता का पता लगाने में हफ्तों या महीनों लग सकते हैं। अपमान शिक्षा को बेहतर बनाने का साधन नहीं हो सकता। हर शिक्षक का वीडियो वायरल करके शिक्षा को बेहतर नहीं बनाया जा सकता। सरकारी स्कूलों जैसे आसान लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करके भी शिक्षा को बेहतर नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि उनके दरवाजे खुले होते हैं। बेहतर स्कूलों के लिए हमें बेहतर सवालों की जरूरत है। किसी विशेष स्कूल में बुनियादी ढांचे की कमी का क्या कारण है? शिक्षकों को प्रशासनिक कार्यों में कठिनाइयों का सामना क्यों करना पड़ता है? क्या शिक्षण संसाधन अच्छे हैं? क्या छात्र-शिक्षक अनुपात सही है? क्या अभिभावकों की भागीदारी पर्याप्त है? क्या सरकारी योजनाएं उन लोगों तक पहुंच रही हैं जिनके लिए वे बनाई गई हैं? क्या शिक्षकों को पर्याप्त प्रशिक्षण मिलता है?

समस्या पर कैमरा घुमाना सबसे आसान तरीका है। समस्या का समाधान करना उतना ही मुश्किल होता है। इसका मतलब यह नहीं है कि नागरिकों को बोलने से रोका जाए, न ही इसका मतलब यह है कि वास्तविक भ्रष्टाचार को उजागर न किया जाए। यदि भ्रष्टाचार, दुर्व्यवहार, लापरवाही या गंभीर कदाचार व्याप्त है, तो इसकी रिपोर्ट करना और उचित माध्यमों से इसकी जांच कराना आवश्यक है। पेशेवर रवैया का मतलब चुप्पी नहीं है। अब आलोचना जिम्मेदारी से होनी चाहिए—और जवाबदेही भी, कानूनी जवाबदेही।

स्कूल कोई कंटेंट स्टूडियो नहीं है। कक्षा सोशल मीडिया रील्स के लिए कोई मंच नहीं है। शिक्षक ऑनलाइन किसी कहानी में किसी और की कहानी नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यूज, लाइक्स और फॉलोअर्स की होड़ में शिक्षा को दरकिनार नहीं किया जाना चाहिए। बड़ा सवाल यह नहीं है कि कौन स्कूल का सबसे खराब वीडियो बना सकता है।

स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए कैमरे ही एकमात्र साधन नहीं हैं। स्कूलों का विकास सहयोग, जिम्मेदारी, समन्वय, संसाधनों और सुविचारित प्रशासन के फलस्वरूप होता है। इसलिए, किसी सरकारी स्कूल में स्वयं को निरीक्षक घोषित करने से पहले, आपको स्वयं से पूछना चाहिए: क्या मेरे पास यह कार्य ठीक से करने का अधिकार, समझ और जिम्मेदारी है? यदि आपको लगता है कि इसका उत्तर नहीं है, तो शायद कैमरे के बजाय बातचीत के माध्यम से प्रवेश करना बेहतर होगा। सलाह देना आसान होता है, लेकिन बदलाव लाना कठिन। शिक्षा का मूल्यांकन होना आवश्यक है, लेकिन साथ ही उसे संवेदनशील, पेशेवर और सम्मानजनक बनाना भी जरूरी है।

(डॉ. सत्यवान सौरभ, पीएचडी
(राजनीति विज्ञान)
एक कवि और सामाजिक विचारक है।)

(यह लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं इससे संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है)

संक्षिप्त वार्ता

आईआईटी दिल्ली में अब तक 160 छात्रों ने की आत्महत्या

नई दिल्ली, 26 अगस्त (वेब वार्ता)। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), दिल्ली के एमएससी के छात्र ऋषिकेश कुमार की आत्महत्या की घटना के बाद छात्रों द्वारा व्यवस्था में बदलाव को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसे लेकर आईआईटी-दिल्ली में बीटेक के दूसरे वर्ष के छात्र सक्षम ने सिस्टम में सुधार और छात्रों की सुरक्षा के लिए कड़े उपायों की मांग की है। उन्होंने कहा कि ऋषिकेश पूर्वांचल कम्युनिटी का हिस्सा थे। आईआईटी-दिल्ली में पूर्वांचल कम्युनिटी द्वारा सरस्वती पूजा आयोजित की जाती है, जिसमें मैं उनसे पहली बार मिला था। पूजा में उन्होंने बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने के साथ स्टेज होस्ट किया था। वह भी बिहार से ही आते थे और पूर्वांचल कम्युनिटी में हमारे एक साथी कार्यकर्ता थे।

क्षमा करना ही शक्ति की सर्वोच्च कसौटी है : विजेंद्र गुप्ता

नई दिल्ली, 26 अगस्त (वेब वार्ता)। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने बुधवार को बाड़ा हिंदू राव में ईद मिलाद-उन-नबी के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि शक्ति की परीक्षा केवल दंड देने की क्षमता से नहीं होती, बल्कि उसकी सर्वोच्च कसौटी यह है कि प्रतिशोध लेने की सामर्थ्य होने के बावजूद व्यक्ति क्षमा करने का रास्ता चुनता है।

पैगंबर मुहम्मद के जीवन का उल्लेख करते हुए विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि उनका जीवन ईमानदारी, विश्वसनीयता, करुणा, धैर्य और क्षमा का शाश्वत संदेश देता है। उन्होंने पैगंबर मुहम्मद द्वारा सहन किए गए अत्याचारों का उल्लेख करते हुए कहा कि उन पर पत्थर तक बरसाए गए, लेकिन बाद में जब मक्का विजय का अवसर आया, तब उनके पास प्रतिशोध लेने का पूरा अधिकार और सामर्थ्य था। इसके बावजूद उन्होंने क्षमा का मार्ग चुना। गुप्ता ने कहा कि वे बदला ले सकते थे, अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर सकते थे और पुराने हिसाब चुकता कर सकते थे, लेकिन उन्होंने क्षमा करना चुना।

एक सितंबर को उपराज्यपाल से मुलाकात करेंगे आआपा विधायक

नई दिल्ली, 26 अगस्त (वेब वार्ता)। आम आदमी पार्टी (आआपा) के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली में कथित घोटालों और स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर उपराज्यपाल से मुलाकात का समय मांगा था। उन्होंने कहा कि आआपा के नेता अब एक सितंबर को शाम साढ़े चार बजे उपराज्यपाल से मिलने पहुंचेंगे। आआपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार के करीब डेढ़ साल के कार्यकाल में कई घोटाले सामने आए हैं। उन्होंने सभी मामलों को लेकर उपराज्यपाल पर सवाल उठाया है। सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र में करीब 650 करोड़ रुपये, साइकिल खरीद में 90 करोड़ रुपये, चावल वितरण और स्कूल ट्रस्ट से जुड़े मामलों में कथित घोटाले सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि आआपा विधायक इन मुद्दों को लेकर उपराज्यपाल से मुलाकात करना चाहते हैं।

लोकसभा स्पीकर ने टीएमसी से 20 बागी सांसदों को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

नई दिल्ली। तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में 20 बागी सांसदों को अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिका दायर की थी। इस मामले में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने उन सांसदों को नोटिस जारी कर सात दिन में जवाब मांगा है। यह घटनाक्रम तब हुई जब सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को टीएमसी की अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला लेने में हो रही देरी को चुनौती देने वाली अभिषेक बनर्जी की याचिका पर उन 20 सांसदों से जवाब मांगा।

अंकित शर्मा हत्याकांड: ताहिर हुसैन की उम्रकैद को हाईकोर्ट में चुनौती

नई दिल्ली। दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) अधिकारी अंकित शर्मा की निर्मम हत्या के मामले में दोषी साबित हुए दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन ने अपनी उम्रकैद की सजा को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट अगले सप्ताह उनकी अपील पर सुनवाई कर सकता है। आईबी अधिकारी शर्मा की हत्या 2020 के नॉर्थ ईस्ट दिल्ली दंगों के दौरान दयालपुर इलाके में हुई थी। उनका शव चांदबाग इलाके में एक नाले से बरामद हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने खुलासा किया था कि अंकित के शरीर पर 40 से अधिक घाव थे, जो बर्बरता का प्रमाण थे। इस गंभीर मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने 31 जुलाई को ताहिर हुसैन सहित पांच लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

मेरी बहनें जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ें क्योंकि मैं हूं ना

दिल्ली लक्ष्मी योजना के शुभारंभ पर बोलीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता

नई दिल्ली, 26 अगस्त (वेब वार्ता)। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को दिल्ली लक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया। उन्होंने हजारों महिलाओं को स्वीकृति पत्र वितरित किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम रेखा ने कहा, मैं यही चाहती हूं कि मेरी सारी बहनें खुश रहनी चाहिए, उनके चेहरे पर ये मुस्कुराहट बनी रहनी चाहिए। मेरी बहनें जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ें क्योंकि मैं हूं ना।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आगे कहा, दिल्ली लक्ष्मी योजना आज दिल्ली भर में मेरी सभी बहनों के घर-घर तक पहुंची है, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूं और आपके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देती हूं। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा इस बात पर जोर देते हैं कि अगर हम देश को आगे ले जाना चाहते हैं, तो हमें अपनी महिलाओं और बहनों को सशक्त बनाना होगा। जब तक घर की महिला तरक्की नहीं करती, खुशहाल नहीं होती और उसकी चुनौतियां हल नहीं होतीं, तब तक देश की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता।

पत्रकारों से बातचीत करते हुए सीएम रेखा ने कहा, पहले दिन ही हमारी ओर से कह दिया गया था कि दिल्ली की बहनों को 2,500 रुपए देना हमारा संकल्प है, तो आज ह्यदिल्ली लक्ष्मी योजना वास्तविक रूप से जनता तक पहुंचाने वाले इस दिन पर मैं दिल्ली की बहनों को खुश देखकर बहुत खुश हूं।

सीएम ने आगे कहा, 1 अगस्त को हमने इस योजना को शुरू किया और सिर्फ 1 महीने के अंदर 9.5 लाख के करीब बहनों ने इसके अंतर्गत रजिस्ट्रेशन किया और आज इस कार्यक्रम के माध्यम से 2,500 की योजना की पहली ढाई हजार लाभार्थियों को हमने अप्रूवल लेटर भेज दिया है और 1 सितंबर को उनके खातों में अगस्त महीने का पैसा पहुंच जाएगा। ऐसा नहीं है कि किसी तय तारीख को इस योजना का रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा। यह लगातार चलने वाली योजना है।

...ये वादा पूरा किया जा सकता था

दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा, यह एक ऐतिहासिक दिन है। प्रधानमंत्री का वादा और मुख्यमंत्री का हमारी बहनों के लिए लिया गया संकल्प राखी के शुभ अवसर पर पूरा हो रहा है। दिल्ली के लोगों और देश भर की महिलाओं ने देखा है कि जब कोई सरकार सच्ची निष्ठा से काम करती है, तो वादे एक साल के भीतर पूरे हो जाते हैं। कपिल मिश्रा ने आगे कहा, इसके विपरीत, अरविंद केजरीवाल ने 10 साल तक दिल्ली पर शासन किया, जहां झुग्गी-बस्तियों में बार-बार फॉर्म भरवाए गए और झूठे वादे किए गए, जिसके बाद आप कार्यकर्ताओं ने महिलाओं का निजी डेटा तक बेच दिया। 10 वर्षों तक दिल्ली में किसी भी महिला के खाते में एक रुपया भी नहीं पहुंचा। अगर ईमानदार होते तो पंजाब में भी ये वादा पूरा किया जा सकता था।

देश के 1 करोड़ छात्रों को मिलेगी फ्री कोचिंग...

वेब वार्ता, नई दिल्ली। भारी-भरकम फीस वसूलने वाले निजी कोचिंग संस्थानों से मध्यम वर्गीय और गरीब परिवारों को मुक्ति दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़े अभियान की शुरूआत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त को की गई घोषणा के बाद, अब देश भर के छात्रों को प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के लिए मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण ऑनलाइन कोचिंग उपलब्ध कराने के रोडमैप पर तेजी से काम शुरू हो गया है।

इस महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत 12वीं तक के स्कूलों, कॉलेजों और ग्रामीण क्षेत्रों के कॉमन सर्विस सेंटर्स को सीधे डिजिटल नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। प्रस्तावित नए मुफ्त कोचिंग नेटवर्क के पहले चरण में नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट और जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जैसी देश की सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी।

इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का विस्तार कर बाद में संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग और अन्य प्रमुख प्रतियोगी परीक्षाओं के पाठ्यक्रमों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। वर्तमान में आईआईटी कानपुर के सहयोग से संचालित 'साथी' पोर्टल की क्षमता सीमित है। नए प्लेटफॉर्म को इस प्रकार विकसित किया जा रहा है कि एक साथ 1 करोड़ से अधिक छात्र बिना किसी तकनीकी रुकावट के पढ़ाई कर सकें। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रल्हाद जोशी ने हाल ही में शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की, जिसमें इस प्लेटफॉर्म को निजी कोचिंग संस्थानों से अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने पर सहमति बनी।

दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने एनसीआर में स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई, जारी की एडवाइजरी

नई दिल्ली, 26 अगस्त (वेब वार्ता)। दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन (डीएमए) ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में स्वाइन फ्लू (एच1एन1) के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई है। खबरों के अनुसार, अब तक 2000 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं।

दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन दिल्ली में इन्फ्लूएंजा की स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है और इस संक्रमण से होने वाली बीमारी और मौतों की निगरानी कर रही है। इन्फ्लूएंजा के मामलों में मौसमी बढ़ोतरी को देखते हुए डीएमए ने लोगों से सतर्क रहने और बचाव के जरूरी उपाय अपनाने की अपील की है। एसोसिएशन ने लोगों को सलाह दी है कि वे सांस से जुड़ी स्वच्छता का ध्यान रखें, साफ-सफाई बनाए रखें, भीड़-भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें और इन्फ्लूएंजा के लक्षण दिखने पर समय रहते डॉक्टर की सलाह लें।

डीएमए ने स्वाइन फ्लू से संक्रमण से बचने के लिए उपाय बताए हैं। डीएमए ने कहा कि खांसते या छींकते समय अपना मुंह और नाक रूमाल या टिश्यू से ढकें। साबुन और पानी से बार-बार हाथ धोएं या अल्कोहल-बेस्ड हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। बिना धुले हाथों से अपनी आँखों, नाक और मुंह को छूने से बचें। भीड़-भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें, खासकर तब जब इन्फ्लूएंजा का असर ज्यादा हो।

दिल्ली के दो प्रसिद्ध होटलों के किचन में कॉकरोच-गंदगी मिली

नई दिल्ली, 26 अगस्त (वेब वार्ता)। दिल्ली के एयरोसिटी स्थित अंदाज हयात और जेडब्ल्यू मैरियट के किचन में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) की जांच में बड़ी कमियां मिली हैं।

जांच के दौरान अंदाज के किचन में वेज और नॉनवेज खाने को अलग रखने की व्यवस्था में कमी मिली। इसके अलावा कॉकरोच, मक्खियां और बदबू की शिकायतें दर्ज हुई। कुछ ब्रेड पैकेट एक्सपायरे स्टिकर के साथ भी मिले। हलवाई एरिया में करीब 87 किलो एक्सपायर्ड मिठाइयां मिलीं, जिन्हें मौके पर नष्ट किया गया। पेस्ट्री सेक्शन में एक्सपायर्ड केक बेस, मक्खियां और कॉकरोच मिले।

नई दिल्ली के जेडब्ल्यू मैरियट होटल में करीब दो दिन चली जांच में 59 कमियां दर्ज की गईं। कुछ खाद्य उत्पादों के लिए जरूरी एफएसएसएआई लाइसेंस या एंडोर्समेंट उपलब्ध नहीं मिला। पैक्ड उत्पादों की लेबलिंग में भी गड़बड़ी सामने आई। फफूंद लगे सेब और सड़े टमाटर भी मिले। कई खाद्य पदार्थ खुले में रखे मिले और वेज-नॉनवेज स्टोरेज में भी गड़बड़ी मिली। बेकरी में कॉकरोच और टूटे कंटेनर पाए गए। इसके पहले भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने निरीक्षण के दौरान खाद्य सुरक्षा नियमों के गंभीर उल्लंघन और अनुपालन में कमी पाए जाने के बाद दिल्ली और दमन की दो खाद्य कारोबार इकाइयों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की थी। एफएसएसएआई ने नई दिल्ली स्थित मार्शे रिटेल प्राइवेट लिमिटेड का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से 30 दिनों के लिए निलंबित कर दिया था।

अंकित शर्मा हत्याकांड: उम्रकैद की सजा के खिलाफ ताहिर हुसैन ने हाईकोर्ट का किया रुख

नई दिल्ली, 26 अगस्त (वेब वार्ता)। दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) हत्या मामले में दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन ने निचली अदालत के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। ताहिर हुसैन की अपील पर दिल्ली हाईकोर्ट अगले सप्ताह सुनवाई कर सकता है।

आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या 2020 के नॉर्थ ईस्ट दिल्ली दंगों के दौरान दयालपुर इलाके में हुई थी। उनका शव चांदबाग इलाके में एक नाले से बरामद किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि अंकित के शरीर पर 40 से ज्यादा घाव थे। इस मामले में ताहिर हुसैन समेत 5 लोगों को कड़कड़डूमा कोर्ट ने 31 जुलाई को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। उम्रकैद की सजा के खिलाफ अब ताहिर हुसैन ने हाईकोर्ट का रुख किया है। वहीं, अंकित शर्मा के भाई अंकुर शर्मा ने कहा कि हमारी जंग जारी रहेगी। हमारी लीगल टीम भी काम कर रही है। हाईकोर्ट ताहिर हुसैन जाएंगे तो हम भी हाईकोर्ट में लड़ेंगे और हमें भरोसा है कि हमें जीत मिलेगी।

इसके पहले अंकित शर्मा हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा पाए जावेद की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था। दिल्ली हाईकोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 2 दिसंबर को होगी। जावेद के वकील ने बताया था कि अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि अभियोजन पक्ष घटना के समय आरोपी की भूमिका साबित करने में विफल रहा। इसके बाद दोषी जावेद ने दिल्ली हाईकोर्ट में निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी है। वहीं, मामले में दोषी ठहराए गए नाजिम और कासिम ने भी निचली अदालत के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। 12 अगस्त को जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस विकास महाजन की बेंच के सामने यह मामला सुना गया। बाद में हाईकोर्ट ने नाजिम और कासिम की सजा के खिलाफ अपील पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया। अदालत ने कहा, ह्लहम नोटिस जारी करेंगे। ये अपीलें 13 जुलाई के उस फैसले से जुड़ी हैं जिसके तहत अपील करने वाले को दोषी ठहराया गया था। उन्हें अलग-अलग धाराओं के तहत उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।

होटल की चौथी मंजिल से कूदने से 37 वर्षीय व्यक्ति की मौत, जांच में जुटी पुलिस

नई दिल्ली, 26 अगस्त (वेब वार्ता)। मध्य दिल्ली स्थित एक होटल की चौथी मंजिल से कथित तौर पर कूदने के बाद 37 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

पुलिस के अनुसार, दोपहर करीब 3 बजे पीसीआर कॉल के जरिए सूचना मिली कि ले मेरिडियन होटल की चौथी मंजिल पर स्थित स्विमिंग पूल क्षेत्र से एक व्यक्ति ने छलांग लगा दी है। मृतक की पहचान दिविज मारिया (37) के रूप में हुई है, जो नई दिल्ली के निवासी थे। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि दिविज मारिया ने करीब छह महीने पहले गुरुग्राम स्थित एक कंपनी की नौकरी छोड़ दी थी। पुलिस के मुताबिक, वह पिछले कुछ महीनों से डिप्रेशन का इलाज भी करा रहे थे। वह विवाहित थे।

घटना के बाद उन्हें तुरंत डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना स्थल का निरीक्षण करने के लिए क्राइम टीम को बुलाया गया। टीम ने मौके से आवश्यक साक्ष्य एकत्र किए हैं। पुलिस ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए सुरक्षित रख लिया गया है।

विवादित बयान पर कंगना रनौत को माफी मांगनी चाहिए : उदित राज

नई दिल्ली, 26 अगस्त (वेब वार्ता)। कांग्रेस नेता उदित राज ने अभिनेत्री कंगना रनौत के संदर्भ में कहा कि उन्हें किसी की भी जिंदगी में तांकझांक करने का हक नहीं है। ये तो भारत है, तो कुछ चीजों को नजरअंदाज कर दिया जा रहा है। अगर अमेरिका होता है, तो अब ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे भेज दिया जाता। मैं तो कुल मिलाकर यही कहूंगा कि अगर कंगना में थोड़ी सी भी नैतिकता है, तो उन्हें सामने आकर कृति सेनन से माफी मांगनी चाहिए। कुछ भी कहने से पहले अभिनेत्री को खुद पर आत्मचिंतन करना चाहिए। इसके बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचना चाहिए। इसके अलावा, उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान पर भी प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने कहा था कि यह देश कोई धर्मशाला नहीं है। उदित राज ने कहा कि ये लोग कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ देश का सत्यानाश करेंगे। दुनियाभर में देश की गरिमा पर इन लोगों ने कुठाराघात किया है। अब आगे देखते हैं कि ये लोग क्या कुछ करते हैं। 2004 से लेकर 2014 तक 88 हजार बांग्लादेशियों को निर्सावित किया गया और अब इस सरकार ने क्या किया?

दिल्ली पुलिस ने 100 से अधिक सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद झपटमार को किया गिरफ्तार

नई दिल्ली, 26 अगस्त (वेब वार्ता)। दिल्ली पुलिस ने बुधवार को एक स्नैचिंग (झपटमारी) मामले में 25 साल के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के विश्लेषण और लगभग 30 किलोमीटर लंबे रास्ते की जांच-पड़ताल के बाद की गई।

दक्षिण-पश्चिम जिले के सरोजिनी नगर पुलिस स्टेशन की टीम ने नेपाल के रहने वाले आरोपी विकास गुरुंग को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि जांच के दौरान एक चोरी की स्कूटी, सोने का पेंडेंट, चांदी की पायल की एक जोड़ी और दो मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार, इस गिरफ्तारी से दिल्ली के अलग-अलग पुलिस स्टेशनों में दर्ज स्नैचिंग, चोरी और सामान खोने से जुड़े पांच मामलों और घटनाओं को सुलझाने में मदद मिली है। जांच तब शुरू हुई जब 3 अगस्त को सरोजिनी नगर पुलिस स्टेशन में स्नैचिंग की एक घटना के सिलसिले में एफआईआर दर्ज हुई। इस केस को सुलझाने के लिए एक टीम बनाई गई।

पुलिस ने बताया कि टीम ने टेक्निकल और फील्ड जांच की, जिसमें स्थानीय पूछताछ और अलग-अलग जगहों से मिले सीसीटीवी फुटेज की बारीकी से जांच भी शामिल थी। जांच के दौरान, संदिग्ध व्यक्ति और अपराध में इस्तेमाल हुई गाड़ी की पहचान और मूवमेंट का पता लगाने के लिए 100 से ज्यादा उउळश कैमरों की रिकॉर्डिंग की जांच की गई। जांच करने वालों ने अलग-अलग कैमरों के फुटेज को जोड़कर एक लगातार विजुअल ट्रेल बनाया और लगभग 30 किलोमीटर के रास्ते की फिज़िकल तौर पर पुष्टि की।

टेक्निकल एनालिसिस और फील्ड वेरिफिकेशन समेत लगातार 16 दिनों की कोशिशों के बाद पुलिस ने गुरुंग की पहचान की और उसे पकड़ लिया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने सरोजिनी नगर केस और झपटमारी व चोरी की कई अन्य घटनाओं में अपनी भूमिका कबूल की। पुलिस ने बताया कि वह इन कथित अपराधों को अंजाम देने के लिए चोरी की स्कूटी का इस्तेमाल कर रहा था।

पुलिस के मुताबिक, गुरुंग ने 11वीं क्लास तक पढ़ाई की है और 2022 में नौकरी की तलाश में नेपाल से भारत आया था। शुरू में उसने अलग-अलग जगहों पर हाउसकीपर और हेल्पर के तौर पर काम किया। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने खुलासा किया कि करीब छह महीने पहले, जब वह मुनिरका में रह रहा था, तो उसने एक व्यक्ति को नशे की हालत में एक स्कूटी के पास सोते हुए देखा, जिसकी चाबी इग्निशन में ही लगी हुई थी। उसने गाड़ी चुरा ली और बाद में स्कूटी लेकर करोल बाग रहने चला गया। इसके बाद आरोपी ने अपने खर्च पूरे करने के लिए दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में झपटमारी और चोरी की घटनाओं को अंजाम देने के लिए चोरी की गाड़ी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया।

पुलिस ने बताया कि उसके काम करने का तरीका यह था कि वह चोरी की स्कूटी से दक्षिण और मध्य दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में घूमता था और आसानी से शिकार बनने वाले पैदल चलने वालों, खासकर मोबाइल फोन, बैग या अन्य कीमती सामान लिए महिलाओं को निशाना बनाता था।

खिचड़ीपुर फ्लाईओवर पर दर्दनाक हादसा, 24 वर्षीय युवक की मौत

नई दिल्ली, 26 अगस्त (वेब वार्ता)। पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर इलाके में खिचड़ीपुर फ्लाईओवर पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने पुलिस और एम्बुलेंस के पहुंचने में देरी का आरोप लगाया।

युवक की पहचान 24 वर्षीय निखिल के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि युवक गाजियाबाद से अपने घर जनकपुरी जा रहा था, तभी फ्लाईओवर पर वह हादसे का शिकार हो गया। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि करीब 30 से 40 मिनट बाद पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची थी। इसको लेकर लोगों में नाराजगी भी देखने को मिली।

हालांकि, देरी से पहुंचने के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल भेज दिया। साथ ही, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए आगे की जांच की जा रही है। हादसा किस वाहन या किस परिस्थिति में हुआ, इसकी भी जांच की जा रही है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर पूरे घटनाक्रम की जानकारी जुटाने में लगी है।

मृतक के चाचा सतीश ने बताया कि उन्हें फोन पर निखिल के एक्सीडेंट की जानकारी मिली थी। वह अपने बड़े भाई के घर से लौट रहा था। उन्होंने कहा कि अभी हादसे के सही कारण का हमें पता नहीं चला है। जांच के बाद ही कुछ चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। इससे पहले, दिल्ली के ग्रेटर कैलाश-1 में कैलाश कॉलोनी मेट्रो स्टेशन के पास रविवार शाम को एक एसयूवी ने पैदल जा रही दंपति को टक्कर मार दी। इस घटना में महिला की मौत हो गई और उसके पति घायल हो गए। मृतक महिला की पहचान 71 वर्षीय शशि के रूप में हुई। एसयूवी चालक ने कई और गाड़ियों को भी टक्कर मारी थी। हालांकि, हादसे के बाद ड्राइवर तपन अहीर को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया।

बारावफात पर उमड़ा अकीदत का सैलाब, जोशोखरोश से निकले जुलूस

शाहाबाद में उमड़ा अकीदत का सैलाब, पिहानी, पाली, गोपामऊ समेत कई कस्बों में निकले जुलूस

वेब वार्ता, लक्ष्मीकान्त पाठक

हरदोई। पैगंबर-ए-इस्लाम हजरत मोहम्मद साहब की पैदाइश और वफात की याद में मनाए जाने वाले बारावफात के मौके पर जिलेभर में अकीदत और एहतराम का माहौल रहा।

पिहानी, पाली, गोपामऊ और शाहाबाद समेत कई कस्बों में जुलूस-ए-बारावफात पूरे जोशोखरोश के साथ निकाले गए। जुलूस में बड़ी तादाद में अकीदतमंदों ने शिरकत की। हाथों में परचम और मजहबी पैगाम लिखी तख्तियां लिए लोग नात-ए-पाक पढ़ते हुए आगे बढ़ते रहे।

शाहाबाद में उमड़ा अकीदत का सैलाब

शाहाबाद में बारावफात के मौके पर अकीदतमंदों का सैलाब उमड़ पड़ा। कस्बे के विभिन्न मोहल्लों से लोग जुलूस में शामिल होने के लिए पहुंचे। जुलूस निर्धारित मार्गों से पूरे जोशोखरोश के साथ निकला। बुजुर्गों के साथ बड़ी संख्या में नौजवान और बच्चे भी परचम लेकर जुलूस में शरीक हुए। नातख्वानी और मजहबी नारों से पूरा माहौल गूंज उठा। जगह-जगह लोगों ने जुलूस का इस्तकबाल किया और अकीदतमंदों के लिए पानी व जलपान का इंतजाम किया गया। जुलूस के दौरान अमन और भाईचारे का पैगाम दिया गया।

पाली में भी उमड़ा अकीदतमंदों का हुजूम

पाली कस्बे में बारावफात का जुलूस मोहल्ला शेख सराय स्थित जामा मस्जिद से शुरू हुआ। चेयरमैन रिजवान खां ने झंडी दिखाकर जुलूस को रवाना किया। जुलूस सुंदर चौराहा, इमाम चौक, इस्लामिया स्कूल और बाजार से होता हुआ थाना चौराहा पहुंचा। इसके बाद मोहल्ला आबिद नगर और काजी सराय उत्तरी से गुजरते हुए जुलूस वापस जामा मस्जिद पहुंचा, जहां दुआ के साथ इसका इख्तिताम हुआ। जुलूस में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक ने बढ़-चढ़कर शिरकत की।

पाली और शाहाबाद में छह घंटे बंद रही बिजली

जुलूसों के दौरान विद्युत तारों और खंभों से किसी तरह की अनहोनी न हो, इसके लिए बिजली विभाग ने विशेष एहतियात बरती। पाली और शाहाबाद पावर हाउस से जुड़े क्षेत्रों में करीब छह घंटे विद्युत आपूर्ति बंद रखी गई। जुलूस मार्गों पर बिजली व्यवस्था को लेकर विभागीय कर्मचारी भी सतर्क रहे। बिजली आपूर्ति बंद रखने से जुलूस के दौरान करंट से होने वाली दुर्घटना की आशंका को टाला जा सका।

चप्पे-चप्पे पर रही पुलिस की निगहबानी

बारावफात के जुलूसों को लेकर पुलिस-प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। संवेदनशील स्थानों और प्रमुख चौराहों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहा। पुलिसकर्मी जुलूस के साथ चलते रहे और लगातार निगरानी करते रहे। अधिकारियों ने भी मौके पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी पुलिसकर्मी मुस्तैद रहे।

अमन और भाईचारे का दिया पैगाम

जिले के विभिन्न कस्बों में निकले जुलूसों में अकीदत के साथ अमन, भाईचारे और आपसी सौहार्द का पैगाम भी नजर आया। प्रशासन की सतर्कता, पुलिस की मुस्तैदी और आयोजकों के सहयोग से जुलूस शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुए।

पिहानी और गोपामऊ में भी दिखा जोशोखरोश

पिहानी और गोपामऊ में भी बारावफात के जुलूस निकाले गए। बड़ी संख्या में अकीदतमंद जुलूस में शामिल हुए। नात-ए-पाक और मजहबी नारों से रास्ते गूंजते रहे। जुलूसों में नौजवानों और बच्चों में खासा उत्साह दिखाई दिया। निर्धारित मार्गों से शांतिपूर्ण ढंग से जुलूस निकाले गए।

संक्षिप्त वार्ता

कुशीनगर में हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से 3 मदरसा छात्रों की हालत गंभीर

कुशीनगर। कुशीनगर में धार्मिक झंडा लगाने के दौरान 11 हजार वोल्ट की हाईटेंशन विद्युत लाइन की चपेट में आने से तीन मदरसा छात्र गंभीर रूप से झुलस गए। हादसे के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई। ग्रामीणों और मदरसा शिक्षकों ने तीनों घायलों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) तमकुहीराज पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उपचार शुरू किया।

पुलिस के अनुसार तरयासुजान थाना क्षेत्र के सलेमगढ़ पैठानी टोला में मंगलवार सुबह करीब 10 बजे छात्र धार्मिक झंडा लगाने के लिए लंबा बांस खड़ा कर रहे थे। इसी दौरान बांस ऊपर से गुजर रही 11 हजार वोल्ट की विद्युत लाइन से छू गया और तीनों छात्र करंट की चपेट में आ गए। घायलों की पहचान रमैना निवासी अरसद (15), राजपुर निवासी शमीम (17) और जमुनिया निवासी इरसाद (20) के रूप में हुई है। अरसद और शमीम शरीर के कई हिस्सों में झुलसे हैं, जबकि इरसाद के सिर में गंभीर चोट आई है। चिकित्सकों के अनुसार तीनों की स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। इस संबंध में तरयासुजान थाना प्रभारी ने बताया कि बड़ी घटना टल गई। सभी छात्र खतरे से बाहर हैं। तीनों का ईलाज सीएचसी तमकुहीराज में चल रहा है।

लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा योजना के शुभारम्भ कार्यक्रम का गांधी भवन सभागार में किया गया सजीव प्रसारण

वेब वार्ता, लक्ष्मीकान्त पाठक

हरदोई।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लखनऊ में लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा का शुभारम्भ किये जाने के क्रम में आज हरदोई के गांधी भवन सभागार में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम एवं जिला प्रशासन द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि राज्य मंत्री उच्च शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश रजनी तिवारी एवं उपस्थित जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों ने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारम्भ किया। इस अवसर पर माताओं-बहनों को उपहार प्रदान किये गये तथा मुख्यमंत्री के उद्बोधन का लाइव प्रसारण देखा गया। मुख्यमंत्री ने अपने उद्बोधन में बताया कि रक्षाबंधन के अवसर पर उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम एवं सिटी बस सेवा की बसों में सभी बहनों, बेटियों और माताओं को एक सहयात्री के साथ 27, 28 और 29 अगस्त 2026 तक तीन दिनों की नि:शुल्क यात्रा सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही महिला स्वावलंबन और सशक्तीकरण को समर्पित लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा योजना प्रारंभ की गई है। इसके अंतर्गत 60 वर्ष एवं उससे अधिक आयु की महिलाओं को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में नि:शुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध होगी।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए एम्स की भॉति एनसीए भवन की मांग

वेब वार्ता, लखनऊ। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष इं. हरिकिशोर तिवारी ने प्रदेश के उपमुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री श्री बृजेश पाठक को पत्र लिखकर दिल्ली एम्स की भॉति उत्तर प्रदेश में एनसीए भवन स्थापित किए जाने की मांग की है। उन्होंने बताया कि एम्स में वरिष्ठ नागरिकों के इलाज के लिए मानसिक रोग विभाग, आथोर्पेडिक विभाग, न्यूरोलॉजी विभाग, कार्डियोलॉजी विभाग, यूरोलॉजी विभाग और सर्जरी विभाग जैसी सुविधाएं दी जा रही है। उन्होंने इस आशय का पत्र श्री जगतप्रसाद नड्डा, केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, प्रतापराव गणपतराव जाधव राज्य मन्त्री, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय सुश्री पुण्य सलिला श्रीवास्तव सचिव भारत सरकार को भी प्रेषित किया है। इं. हरिकिशोर तिवारी ने पत्र में कहा है कि अभी प्रदेश सरकार ने एक अच्छा कदम उठाते हुये 70 वर्ष के ऊपर के नागरिको को भी आयुष्मान स्वास्थ्य योजना से जोड़ कर इलाज कराने का निर्णय लिया है।

याद-ए-मुस्तफा में डूबा कछौना, अकीदत के साथ निकला जुलूस-ए-मोहम्मदी

वेबवार्ता/हरदोई ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर बुधवार को कस्बा कछौना में जुलूस-ए-मोहम्मदी अकीदत और उल्लास के साथ निकाला गया। विभिन्न मोहल्लों से बड़ी संख्या में अकीदतमंद जुलूस में शामिल हुए। बच्चे, युवा, हाफिज, मौलाना और आम लोग इस्लामी परचम थामे कतारबद्ध होकर चल रहे थे। नात-ओ-मंकबत से वातावरण गूंजता रहा।

जुलूस के मार्ग पर स्थानीय लोगों ने अकीदतमंदों का स्वागत किया। कई स्थानों पर जलपान शिविर लगाकर शीतल जल, शर्बत, फल व खाद्य सामग्री वितरित की गई। पूर्व सभासद प्रतिनिधि मेराज मंसूरी, वारिस मियां, फुरकान मियां, मोहम्मद समीर, सभासद प्रतिनिधि कुर्बान मंसूरी, जाबिर व जुबेर समेत तमाम गणमान्य लोगों ने व्यवस्थाओं में सहयोग किया।

सर्पदंश से किसान की मौत, झाड़-फूंक में गंवाया समय चली गयी जान

वेबवार्ता/कछौना, हरदोई। विकासखंड कछौना क्षेत्र के ग्राम निर्मलपुर में सर्पदंश से 60 वर्षीय किसान बैजनाथ पुत्र सकटे की मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में मातम छा गया और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।बताया गया कि बैजनाथ को रात में सांप ने काट लिया था। सर्पदंश के बाद परिजन उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाने के बजाय झाड़-फूंक कराने में लग गए। उपचार में हुई देरी के चलते किसान की हालत लगातार बिगड़ती गई और आखिरकार उनकी मौत हो गई।

घटना ने एक बार फिर सर्पदंश के मामलों में समय पर चिकित्सकीय उपचार की आवश्यकता को उजागर किया है। चिकित्सकों के अनुसार सांप के काटने पर झाड़-फूंक के चक्कर में समय गंवाने के बजाय पीड़ित को तत्काल नजदीकी अस्पताल पहुंचाना चाहिए, ताकि समय रहते आवश्यक उपचार मिल सके।

रक्षाबंधन पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस अलर्ट

बस स्टैंड पर मिशन शक्ति का चला अभियान

वेब वार्ता, लक्ष्मीकान्त पाठक

हरदोई। रक्षाबंधन पर्व के मद्देनजर महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस ने सतर्कता बढ़ा दी है। बुधवार को क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में थाना कोतवाली शहर की मिशन शक्ति एवं एंटी रोमियो टीम ने बस स्टैंड पर महिला सुरक्षा, सम्मान और जागरूकता को लेकर अभियान चलाया। इस दौरान महिलाओं को सुरक्षा का भरोसा दिलाते हुए उन्हें किसी भी परेशानी की स्थिति में तत्काल पुलिस की मदद लेने के लिए प्रेरित किया गया।

टीम ने महिलाओं को 112, 1090, 1930, 181, 108 और 102 सहित विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी और पंपलेट वितरित किए। महिलाओं से भीड़भाड़ वाले स्थानों पर विशेष सतर्कता बरतने तथा किसी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की जानकारी तत्काल पुलिस को देने की अपील की गई।

बस चालकों को भी दिए सुरक्षा के निर्देश

अभियान के दौरान बस स्टैंड पर मौजूद रोडवेज बस चालकों को भी सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। चालकों से वाहन चलाते समय किसी भी प्रकार के नशे का सेवन न करने और बस में संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने की अपील की गई। क्षेत्राधिकारी नगर ने चालकों से कहा कि किसी संदिग्ध व्यक्ति के बस में प्रवेश करने पर तत्काल पुलिस को सूचना दें। साथ ही बस में फोटो और वीडियोग्राफी कराने की सलाह दी गई, जिससे किसी आपराधिक घटना की स्थिति में संदिग्ध की पहचान कर उसके खिलाफ प्रभावी कानूनी कार्रवाई की जा सके।

हाईवे पर कार ने स्कूटी सवार तीन छात्राओं को मारी टक्कर, दो की दर्दनाक मौत, एक गंभीर

कुशीनगर। कुशीनगर जिले से एक भीषण सड़क हादसे की खबर सामने आई है। हाईवे पर एक तेज रफ्तार कार ने स्कूटी सवार तीन छात्राओं को जोरदार टक्कर मार दी। इस दर्दनाक हादसे में दो छात्राओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरी छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई है। यह हृदय विदारक घटना तमकुहीराज थाना क्षेत्र के माधोपुर बुजुर्ग कट के पास घटी।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, तीनों छात्राएं एक ही स्कूटी पर सवार होकर अपने घर लौट रही थीं। जैसे ही वे माधोपुर बुजुर्ग कट के समीप पहुंचीं, एक अनियंत्रित और तेज रफ्तार कार ने उनकी स्कूटी को जोरदार ठोकर मार दी। टक्कर इतनी भयंकर थी कि हादसे के तुरंत बाद कार का टायर भी फट गया।

इस हादसे में जान गंवाने वाली दोनों छात्राएं पड़ोसी राज्य बिहार के गोपालगंज जिले की रहने वाली थीं। जिनकी पहचान अनामिका (22 वर्ष) निवासी सुकदेव पट्टी, थाना गोपालपुर (जिला गोपालगंज), निशा (21 वर्ष) निवासी एराजीपुर बोधाछापर, थाना गोपालपुर (जिला गोपालगंज) और इस हादसे में गंभीर रूप से घायल तीसरी छात्रा की पहचान आलीसा खातून (23 वर्ष) के रूप में हुई है, जो कुशीनगर के तमकुहीराज थाना क्षेत्र के छपरा अहिरौली की निवासी है।

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों मृतक छात्राओं के शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं, गंभीर रूप से घायल आलीसा खातून को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां उसका सघन उपचार चल रहा है।

इस बीच, पटहेरवा थाना पुलिस ने दुर्घटना करने वाली कार को अपने कब्जे में ले लिया है। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। इस दर्दनाक घटना की खबर मिलते ही छात्राओं के परिवारों में कोहराम मच गया है।

स्नातक में पढ़ने वाली 50 हजार बेटियों को स्कूटी अक्टूबर-नवंबर में: मुख्यमंत्री

वेब वार्ता, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षाबंधन से ठीक पहले नारी शक्ति को कई सौगातें दीं। उन्होंने घोषणा की कि स्नातक में पढ़ने वाली 50 हजार बेटियों को अक्टूबर-नवंबर में स्कूटी दी जाएंगी। सीएम ने लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा योजना का शुभारंभ किया, जिसके तहत उप्र राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में 60 वर्ष व उससे अधिक आयु की प्रदेश की महिलाएं नि:शुल्क यात्रा कर सकेंगी। सीएम ने रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में 27 से 29 अगस्त तक महिला व एक सहकर्मी को नि:शुल्क बस यात्रा की सुविधा दिए जाने का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की महिलाएं अब चूल्हे से चेक, चेक से कारोबार और कारोबार से टेक्नोलॉजी तक पहुंच रही हैं।

यूपी में साढ़े 12 करोड़ आधी आबादी

इंदिरा प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी में लगभग साढ़े 12 करोड़ आधी आबादी है। सरकार महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन व नेतृत्व की यात्रा में सहभागी है। हर बेटी-बहन-माता आत्मनिर्भर महसूस करे, यही हमारी नीति है। डबल इंजन सरकार ने बेटी के जन्म से लेकर उसकी पढ़ाई, सुरक्षा, रोजगार, आय और उसके सपनों की उड़ान को ईकोसिस्टम से जोड़ने का काम किया है। सीएम ने बहनों से अपील की कि रक्षाबंधन पर अपने भाई के साथ ही सैनिकों, पूर्व सैनिकों व पुलिस के जवानों को रक्षासूत्र बांधकर सुरक्षा के ईकोसिस्टम को मजबूती प्रदान करने में योगदान दें।

महिला स्वावलंबन की मिसाल हैं लोकमाता

सीएम ने कहा कि देश जब मुगल आक्रांताओं की चपेट में था, उस समय लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर ने सुशासन, आध्यात्मिक/सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण व महिला स्वावलंबन का आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया था। काशी विश्वनाथ, सोमनाथ समेत देश में सैकड़ों मंदिर का पुनरुद्धार लोकमाता ने किया था। लखनऊ, कानपुर, आगरा, गाजियाबाद, मुरादाबाद, बरेली, प्रयागराज, अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी, झांसी सभी जनपदों में अहिल्याबाई होल्कर के नाम पर कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास का निर्माण किया जा रहा है। प्रत्येक हॉस्टल में 500 कामकाजी महिलाओं के नि:शुल्क रहने की व्यवस्था रहेगी।

अब जब चाहे अयोध्या-काशी जाएंगे, निशुल्क सफर की सौगात पर भावुक हुईं बुजुर्ग

वेब वार्ता, लखनऊ। निशुल्क बस यात्रा की सुविधा मिलने के शुभारंभ कार्यक्रम में पहुंचीं महिलाओं का उत्साह देखते ही बना। मुख्यमंत्री से संवाद के दौरान कई महिलाएं भावुक हो गईं और बोलीं कि अब उन्हें यात्रा के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। अयोध्या, काशी या प्रदेश में कहीं और जाने के लिए किराये की चिंता नहीं करनी होगी। इस दौरान उत्साहित बेटियों ने कहा कि हमें योगी जी पर गर्व है। सीएम को देखते ही सभी महिलाओं ने हर-हर महादेव का उद्घोष किया।

गोसाईंगंज की गणेश देवी ने मुख्यमंत्री की इस पहल पर खुशी जताते हुए कहा कि अब वह निश्चिंत होकर यात्रा कर सकेंगी। वहीं, राजरानी ने कहा कि अब जहां जाने की इच्छा होगी, वहां जा सकेंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माताओं को बड़ा उपहार दिया है। लखनऊ के निजामपुर की मिठाना देवी ने कहा कि योगी सरकार ने ऐसी सुविधा दी है कि अब यात्रा के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। महिलाओं के लिए यह सुविधा केवल पारिवारिक यात्राओं तक सीमित नहीं रहेगी। कार्यक्रम में आईं कई बुजुर्ग महिलाओं ने अयोध्या और काशी जैसे धार्मिक स्थलों की यात्रा की इच्छा जताई। उनका कहना था कि किराये की चिंता खत्म होने से अब तीर्थयात्रा करना भी आसान होगा।

छात्राओं में रक्षाबंधन के सफर को लेकर उत्साह

मुंशी पुलिया की रहने वाली और नारी शिक्षा निकेतन पीजी कॉलेज में बीएससी द्वितीय वर्ष की छात्रा अंजली श्रीवास्तव ने कहा कि वह रक्षाबंधन पर अपने भाई को राखी बांधने जाएंगी और मुफ्त यात्रा सुविधा का लाभ लेंगी। जानकीपुरम की आस्था राजपूत ने बताया कि वह अपनी मां के साथ राखी बांधने जाएंगी और दोनों इस सुविधा का लाभ उठाएंगी। खदरा की शगुन निषाद भी योजना को लेकर उत्साहित दिखीं। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में महिलाओं को साड़ी और मिठाई का उपहार भी दिया गया। अहमामऊ की रचना रावत ने कहा कि पहली बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर उन्हें बहुत अच्छा लगा। महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री की योजनाओं के बारे में सुनना उत्साह बढ़ाने वाला है।

फैजुल्लागंज की हिना परवीन ने कहा कि महिलाओं और बच्चों के लिए मुख्यमंत्री की सोच और योजनाएं देखकर गर्व महसूस होता है। वहीं, सिद्धार्थनगर की दिव्या पाठक ने कहा कि महिलाओं को लेकर मुख्यमंत्री की सम्मान देने वाली सोच है। युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं। कार्यक्रम में सरोजनीनगर की कृष्णावती, जनक दुलारी और उबराजा समेत बड़ी संख्या में बुजुर्ग महिलाएं भी पहुंचीं।

सिविल अस्पताल की स्ट्रोक यूनिट में इलाज से लौटी आवाज और अंगों की शक्ति

लखनऊ। डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी (सिविल) चिकित्सालय, लखनऊ में हाल ही में प्रारंभ की गई स्ट्रोक उपचार सुविधा के माध्यम से तीव्र इस्कीमिक स्ट्रोक के मरीजों का सफलतापूर्वक उपचार किया जा रहा है।

समय पर पहचान, तत्काल मस्तिष्क की सीटी जांच तथा पात्र मरीजों में निर्धारित समय-सीमा के भीतर आरटीपीए रक्त-घोलक उपचार शुरू किए जाने से न केवल जीवन बचाने में मदद मिल रही है, बल्कि मरीजों को संभावित स्थायी विकलांगता से बचाने में भी महत्वपूर्ण सफलता मिल रही है।

42 वर्षीय महिला कर्मी, जो सिविल अस्पताल में सफाई कार्य से जुड़ी हैं, को ड्यूटी समाप्त होने के समय अचानक बेहोशी हुई। सहकर्मियों ने तत्काल उन्हें गहन चिकित्सा कक्ष में पहुंचाया। कुछ होश में आने के बाद वह बोल नहीं पा रही थीं तथा उनके दाहिने हाथ-पैर में कमजोरी थी। गहन चिकित्सा कक्ष की प्रभारी नर्स पुष्पा ने तत्काल स्ट्रोक के लक्षणों को पहचाना और न्यूरोसर्जन डॉ. विनोद कुमार तिवारी से संपर्क किया। चिकित्सालय की टीम द्वारा तत्काल मस्तिष्क की सीटी जांच कराई गई, जिसमें रक्तस्राव नहीं पाया गया। चिकित्सकीय मानकों के अनुसार आरटीपीए रक्त-घोलक उपचार शुरू किया गया। लगभग दो घंटे के भीतर मरीज की आवाज वापस आने लगी और दाहिने हाथ-पैर की शक्ति में स्पष्ट सुधार हुआ।

इसी प्रकार पूर्व में एक मरीज को भी समय पर अस्पताल पहुंचने और त्वरित स्ट्रोक उपचार व्यवस्था का लाभ मिला था तथा उसकी स्थिति में संतोषजनक सुधार हुआ था। आज वह ठीक है। न्यूरोसर्जन डॉ. विनोद कुमार तिवारी ने बताया कि तीव्र इस्कीमिक स्ट्रोक में उपयुक्त मरीजों के लिए लक्षण शुरू होने के साढ़े चार घंटे के भीतर रक्त-घोलक उपचार अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकता है। अचानक चेहरा टेढ़ा होना, हाथ-पैर में कमजोरी या बोलने में कठिनाई जैसे लक्षण दिखाई दें तो समय गंवाए बिना तत्काल अस्पताल पहुंचाना चाहिए।

पूरी टीम को दी बधाई

सिविल अस्पताल में स्ट्रोक मरीजों के लिए गहन चिकित्सा कक्ष में पांच बिस्तर, 24 घंटे मस्तिष्क की सीटी जांच तथा आवश्यक रक्त-घोलक दवा की व्यवस्था उपलब्ध है। अस्पताल के निदेशक डॉ. जी.पी. गुप्ता के निर्देश पर पात्र मरीजों को आरटीपीए उपचार निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. डी.के. पाण्डेय एवं अधीक्षक डॉ. एस.आर. सिंह ने इस उपलब्धि के लिए चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ, गहन चिकित्सा कक्ष, रेडियोलॉजी विभाग एवं पूरी टीम को बधाई दी।

ग्रामीण महिलाओं को दिया गया रोजगार का प्रशिक्षण, आत्मरक्षा के भी सिखाए गुर

वेबवार्ता/हरदोई। ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें घर बैठे रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हेल फाउंडेशन एनजीओ की ओर से यू.जे. पैलेस में विशेष बैठक एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें क्षेत्र की करीब 200 महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।कार्यक्रम में हेल फाउंडेशन की प्रेसिडेंट एवं सहयोगियों मीरा देवी, रीता देवी और बीना देवी ने महिलाओं को धूपबत्ती निर्माण, सिलाई-कढ़ाई समेत विभिन्न कुटीर उद्योगों से जुड़े कार्यों का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया। महिलाओं को कम लागत में घर से ही रोजगार शुरू करने के तौर-तरीकों की जानकारी दी गई। महिलाओं की सुरक्षा और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए सेल्फ डिफेंस मोटिवेशनल प्रोग्राम भी आयोजित किया गया। गरिमा कपूर ने महिलाओं को आत्मरक्षा की विभिन्न तकनीकों और उनके उपयोग की जानकारी दी।कार्यक्रम के समापन पर वक्ताओं ने कहा कि इस तरह के प्रशिक्षण से ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनने के साथ आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। कार्यक्रम का संचालन हेल फाउंडेशन की ओर से कथाकल ब्रांड के सहयोग से किया गया।

महत्वपूर्ण ख़बर

न्यूयॉर्क में संघ प्रमुख भागवत के कार्यक्रम का मेयर ने किया विरोध

■ न्यूयॉर्क। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के 29 अगस्त को न्यूयॉर्क के मैडिसन स्क्वायर गार्डन में होने वाले कार्यक्रम को लेकर विवाद गरमा गया है। न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर जोहरान ममदानी ने इस आयोजन का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि वह इसका समर्थन नहीं करते। हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि शहर प्रशासन के पास किसी निजी कार्यक्रम को रद्द करने का अधिकार है या नहीं, इसे लेकर वह निश्चित नहीं हैं। मोहन भागवत 25 अगस्त को अमेरिका पहुंचे हैं। उनका यह दौरा आरएसएस के शताब्दी वर्ष में चलाए जा रहे वैश्विक संपर्क अभियान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अमेरिका के बाद, वे कनाडा और ब्रिटेन भी जाएंगे। न्यूयॉर्क में 29 अगस्त को भागवत सार्वभौमिक एकता उत्सव कार्यक्रम में भारतीय- अमेरिकी समुदाय को संबोधित करेंगे। आयोजकों के मुताबिक, इस कार्यक्रम में लगभग 5,000 लोगों के शामिल होने की उम्मीद है।

रोहिंग्याओं ने रैली निकाली कहा- हमें राखाइन भेजें

■ वल्लढाका। बांग्लादेश के शिविरों में रह रहे हजारों रोहिंग्या शरणार्थियों ने म्यांमार के रखाइन राज्य में सुरक्षित वापसी की मांग को लेकर एक बड़ी रैली आयोजित की। इस सभा को उन्होंने रोहिंग्या नरसंहार की नौवीं वर्षगांठ दिवस के रूप में मनाया, जिसमें अंतरराष्ट्रीय समुदाय से रखाइन में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया। वर्तमान में, म्यांमार के जातीय और धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय से ताल्लुक रखने वाले 10 लाख से अधिक रोहिंग्या शरणार्थी बांग्लादेश के कॉक्सबाजार के विभिन्न शिविरों में रह रहे हैं। इनमें से अधिकांश 2017 में म्यांमार द्वारा रखाइन में एक रोहिंग्या मुस्लिम विद्रोही समूह के हमले के जवाब में शुरू की गई सैन्य कार्रवाई के बाद बड़े पैमाने पर पलायन कर आए थे।

मराठी भाषा विवाद: मनसे ने कहा- मराठी बोलने में दिक्कत है तो महाराष्ट्र छोड़ दें

मुंबई के कांदिवली में ऑटो-टैक्सी चालकों के लिए मराठी अनिवार्यता पर बढ़ा विवाद मनसे नेता दिनेश सालवी का बयान

मुंबई। महाराष्ट्र में ऑटो-रिक्शा और टैक्सी चालकों के लिए मराठी भाषा के कामचलाऊ ज्ञान को अनिवार्य करने के मुद्दे पर विवाद तेज हो गया है।

राज ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) ने मुंबई के कांदिवली इलाके में मराठी भाषा के समर्थन में कई बोर्ड लगाए हैं। चारकोप विधानसभा क्षेत्र में मनसे नेता दिनेश सालवी ने कहा कि जिन ऑटो-रिक्शा चालकों को मराठी सीखने या बोलने में परेशानी है, वे महाराष्ट्र छोड़कर अपने राज्यों में वापस जा सकते हैं।

मनसे नेता का यह बयान कांदिवली में एक मराठी भाषी ऑटो चालक के साथ कथित मारपीट की घटना के बाद आया है। घटना के बाद मराठी भाषी लोगों और उत्तर भारत से जुड़े कुछ ऑटो-टैक्सी चालकों के बीच तनाव की स्थिति बन गई है।

दिनेश सालवी ने कहा कि पार्टी ने कांदिवली के विभिन्न इलाकों में बोर्ड लगाकर राज्य सरकार के नियम का समर्थन किया है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि मुंबई के स्थानीय लोगों पर दबाव बनाने की कोशिश की गई तो मनसे चुप नहीं बैठेगी। पार्टी का कहना है

कि महाराष्ट्र में काम करने वाले ऑटो और टैक्सी चालकों को स्थानीय भाषा का बुनियादी ज्ञान होना चाहिए।

सोमवार को बड़ी संख्या में ऑटो-रिक्शा चालक मराठी भाषा से जुड़े नियम के विरोध में कांदिवली के एमजी रोड पर एकत्र हुए थे। प्रदर्शन के दौरान कुछ चालकों ने अन्य ऑटो चालकों से भी वाहन नहीं चलाने की अपील की।

20 अगस्त से शुरू हुआ परिवहन विभाग का अभियान

महाराष्ट्र परिवहन विभाग ने 20 अगस्त से राज्यभर में विशेष अभियान शुरू किया है। इसके तहत गैर-मराठी भाषी ऑटो-रिक्शा और टैक्सी चालकों के मराठी भाषा के व्यावहारिक ज्ञान की जांच की जा रही है। परिवहन विभाग के अनुसार, ऑटो-रिक्शा और टैक्सी चलाने के लिए कामचलाऊ मराठी भाषा का ज्ञान वर्ष 1989 से आवश्यक है, लेकिन लंबे समय तक इस नियम को सख्ती से लागू नहीं किया गया। हाल के महीनों में चलाए गए मराठी भाषा अभियान के दौरान बड़ी संख्या में गैर-मराठी भाषी ऑटो और टैक्सी चालक मराठी सीखने के लिए आगे आए हैं। अब इस मुद्दे पर परिवहन विभाग की कार्रवाई और राजनीतिक संगठनों की सक्रियता के कारण विवाद और चर्चा तेज हो गई है।

जनता ने जिस सीएम को नकारा है उन्हें वही पसंद है: पूनावाला

शहजाद का अभिजीत दीपके पर पलटवार

नई दिल्ली। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके द्वारा कुछ मुख्यमंत्रियों को देश के सर्वश्रेष्ठ नेताओं की सूची में शामिल करने पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे शहजाद पूनावाला ने अभिजीत दीपके और उनकी कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) पर तीखा हमला बोला है। पूनावाला ने कहा है कि दीपके को जिन मुख्यमंत्रियों को अच्छे लगते हैं, उन्हें जनता पहले ही नकार चुकी है। उन्होंने सीजेपी को फ्रॉड पार्टी करार देते हुए दीपके के चुने गए तीन मुख्यमंत्रियों के चयन पर गंभीर सवाल उठाए।

हाल ही में एक कार्यक्रम में अभिजीत दीपके ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, द्रविड़ मुन्नेत्र कझगम (डीएमके) के नेता एमके स्टालिन और केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को देश के सबसे अच्छे मुख्यमंत्रियों में शामिल किया था। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए शहजाद पूनावाला ने कहा, ये तीनों ऐसे मुख्यमंत्री हैं, जिन्हें उनकी जनता ने रिजेक्ट कर दिया है। तो सीजेपी को वो सीएम अच्छे लगते हैं, जिन्हें जनता ने रिजेक्ट कर दिया है। उन्होंने तंज कसा कि कॉकरोच जनता पार्टी में से जनता को हटाकर सिर्फ कॉकरोच पार्टी कर देना चाहिए, क्योंकि जनता का निर्णय कुछ और रहा है। पूनावाला ने अभिजीत दीपके के दावों का खंडन करते हुए तमिलनाडु की अर्थव्यवस्था पर एमके स्टालिन के कार्यकाल को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि स्टालिन ने तमिलनाडु की नहीं, बल्कि अपने परिवार की अर्थव्यवस्था और अपने बेटे का उदय किया।

आंकड़ों का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि स्टालिन के पांच सालों के कार्यकाल में तमिलनाडु का कर्ज 2021 में 4.86 लाख करोड़ से बढ़कर 9.52 लाख करोड़ हो गया था। पूनावाला ने टिप्पणी की, जितना 60-70 सालों में बढ़ा, उतना पांच सालों में स्टालिन ने बढ़ाया। ये अच्छा कर रहे थे इकोनॉमी को।

केरल के पूर्व सीएम पिनराई विजयन के स्वास्थ्य मॉडल की तारीफ पर भी पूनावाला ने आपत्ति जताई। उन्होंने कोविड की दूसरी लहर का जिक्र करते हुए कहा कि केरल की आबादी साढ़े तीन करोड़ थी, और आंकड़ों के अनुसार वहां 71 हजार मौतें हुईं। इसकी तुलना में, उत्तर प्रदेश की आबादी 24 करोड़ थी और वहां कोविड से जुड़ी मौतें 23 हजार 700 हुईं थीं। पूनावाला ने इसे कुप्रबंधन बताते हुए कहा, छोटा राज्य होने के बावजूद केरल में यूपी से ज्यादा मौतें हुईं। ये था केरल हेल्थ मॉडल।

सीजेपी के नेताओं ने सरकार पर साधा निशाना

5 सितंबर को इंडिया गेट से पुलिस मुख्यालय तक मार्च का ऐलान

नई दिल्ली। जेन-जी से जुड़े एक हालिया कान्क्लेव में कॉकरोच जनता पार्टी के तीनों मुख्य चेहरे अभिजीत दीपक, आशुतोष रांका और सौरव दास शामिल हुए। इस दौरान जब अभिजीत दीपक से सवाल किया गया कि क्या वे दिल्ली केवल बवाल मचाने आते हैं और उन्होंने फिर से मार्च का ऐलान क्यों किया है, तो उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्हें यह कदम मजबूरी में उठाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि लगभग एक महीना बीत जाने के बाद भी सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। उनका मुख्य उद्देश्य उन बच्चों के परिजनों को एक करोड़ रुपये का मुआवजा दिलाना है जिन्होंने आत्महत्या कर ली है।

दीपके ने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार के लिए एक करोड़ रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है, क्योंकि सांसद और विधायकों की खरीद-फरोख्त में 50 से 100 करोड़ रुपये आसानी से खर्च कर दिए जाते हैं, लेकिन पीड़ित परिवारों की मदद करने में कंजूसी दिखाई जा रही है। उन्होंने कहा कि उनकी दूसरी प्रमुख मांग छात्रों पर दर्ज की गई एफआईआर को तुरंत वापस लेने की है, क्योंकि प्रदर्शन करने वाले छात्र अपने शिक्षा से जुड़े अधिकार मांग रहे थे, न कि किसी से वोट। कार्यक्रम के दौरान घोषणा करते हुए दीपके ने बताया कि आगामी 5 सितंबर को इंडिया गेट 1.0 के तहत वे इंडिया गेट से पुलिस मुख्यालय तक शांति मार्च निकालेंगे। उन्होंने बताया कि वे आकांक्षा चतुर्वेदी के परिवार से मिले थे, जिनके पिता को बेटी की मौत के सदमे में पैरालिसिस और हार्ट अटैक आ गया था।

नई बैच के प्रशिक्षण से लेकर वरिष्ठता और वेतन निर्धारण तक पर पड़ सकता है असर

नई दिल्ली। क्रीमी लेयर का मुद्दा एक बार फिर से सुर्खियों में है। यह मामला संघ लोक सेवा आयोग सिविल सर्विसेज परीक्षा से जुड़ा तकरीबन 10 साल पुराना मामला है। यूपीएससी-सिविल सर्विसेज की परीक्षा में सफल ओबीसी कैटेगरी के 100 उम्मीदवारों को कार्मिक विभाग ने अयोग्य घोषित कर दिया था। विभाग ने क्रीमी लेयर को आधार बनाते हुए यह कदम उठाया था। बाद में यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया।

सुप्रीम कोर्ट ने 11 मार्च 2026 को इन सभी अभ्यर्थियों के दावों पर विचार करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने कहा था कि सिर्फ आय को आधार बनाते हुए क्रीमी लेयर को तय नहीं किया जा सकता है। साथ ही कोर्ट ने केंद्र को इस पर विचार करने के लिए 6 महीनों का वक्त दिया था। यह मियाद सितंबर में खत्म हो रही है। इसे देखते हुए डीओपीटी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर इस मामले में साफ स्पष्टीकरण और दिशा-निर्देश देने की मांग की है।

ओबीसी क्रीमी लेयर के मामले में केंद्र सरकार ने ऐसे समय में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर स्पष्टीकरण मांगा है, जब देशभर में आरक्षण के सपोर्ट और उसके खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि सिविल सेवा परीक्षा-2025 के मामले में कैटेगरी-वाइज मेरिट और आवंटन सूची को अंतिम रूप देने में देरी का व्यापक असर पड़ सकता है। केंद्र के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का 11 मार्च का फैसला सीएसई-2025 का अंतिम परिणाम घोषित होने के 5 दिन बाद आया था, ऐसे में यदि कैटेगरी-वाइज मेरिट और सर्विस अलोकेशन लिस्ट को दोबारा अंतिम रूप देने की प्रक्रिया शुरू होती है, तो इसका असर नई बैच के प्रशिक्षण से लेकर वरिष्ठता और वेतन निर्धारण तक पर पड़ सकता है। सरकार ने कहा कि इस देरी का ह्यकैस्केडिंग इफेक्टह्न होगा और एक प्रक्रिया में बदलाव से नियुक्ति से जुड़े कई स्तर प्रभावित हो सकते हैं। केंद्र ने इसी आधार पर मामले में स्पष्टता और उचित दिशा-निर्देश देने का आग्रह किया है।

इटली में सैकडों साल पुराने कुएं में मिले महिला-पुरुष के कंकाल

रोम। इटली में पुरातत्वविदों को कुएं की गहराई से एक पुरुष और एक महिला के कंकाल बरामद हुए हैं, जो करीब 2500 साल पुरानी होने का दावा किया जा रहा है। खुदाई में मिली चीजों ने प्राचीन एट्रस्कन सभ्यता के धार्मिक अनुष्ठानों को लेकर नई दिलचस्पी पैदा कर दी है। महिला और पुरुष के कंकाल के अलावा तांबे और टिन से बने कांस्य की महिला मूर्तियों के टूटे हुए हिस्से और एक दुर्लभ कांस्य प्लेट भी मिली है। शोधकताओं का मानना है कि यह कुआं केवल पानी जमा करने के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि इसका इस्तेमाल धार्मिक गतिविधियों के लिए भी किया जाता रहा होगा। यह पुराना कुआं आधुनिक इटली के बोलोन्या शहर के बाहरी इलाके में मिला है।

पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी अमेरिका को की थी लीक

पूर्व सीडीएस अनिल चौहान का बड़ा खुलासा

नई दिल्ली। पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) अनिल चौहान ने पिछले साल हुए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उन्होंने आशंका जताई है कि इस ऑपरेशन से जुड़ी संवेदनशील जानकारी पाकिस्तान की ओर से अमेरिका को लीक की गई होगी। पूर्व सीडीएस ने स्पष्ट किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम को लेकर पूरी तरह द्विपक्षीय बातचीत हुई थी और इसमें किसी भी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं थी। ऐसे में उन्होंने इस बात पर गहरी हैरानी जताई कि भारत की आधिकारिक घोषणा से पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर इसका ऐलान कैसे कर दिया।

पूर्व सीडीएस ने बताया कि गत वर्ष 29 अप्रैल को आतंकवादी ठिकानों को सटीक निशाना बनाने का अहम फैसला लिया गया था और इस पूरी प्रक्रिया के दौरान सेना पर किसी भी प्रकार का कोई राजनीतिक दबाव नहीं था। संघर्ष विराम की प्रक्रिया के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि दोनों

देशों के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस (डीजीएमओ) के बीच आपसी सहमति से समय तय किया गया था। फोन पर बातचीत के बाद शाम पांच बजे का समय निर्धारित हुआ था, जिससे यह पूरी तरह स्पष्ट है कि सीजफायर केवल दो सैन्य अधिकारियों के बीच की आपसी समझ का परिणाम था। जब उनसे यह सवाल किया गया कि यह गोपनीय जानकारी अमेरिका तक कैसे पहुंची, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि यह सूचना भारतीय पक्ष की तरफ से बिल्कुल लीक नहीं की गई थी। उन्होंने अंदेशा जताया कि यह जानकारी निश्चित तौर पर दूसरे पक्ष यानी पाकिस्तान की तरफ से ही लीक हुई होगी। इसके अलावा, पूर्व सीडीएस ने किराना हिल्स पर किए गए हमलों की अटकलों पर भी विराम लगाया। उन्होंने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों वाले क्षेत्र किराना हिल्स को निशाना नहीं बनाया गया था। उन्होंने समझाया कि हमलों से पहले सरगोधा क्षेत्र में कई ड्रोन भेजे गए थे, जिनका मुख्य उद्देश्य वहां के रडार का पता लगाना था। हवा में लंबे समय तक मंडराने के बाद यदि इन ड्रोनों को कोई लक्षित स्थान नहीं मिलता है, तो वे नीचे उतरकर टकरा जाते हैं। संभवतः इसी प्रक्रिया के दौरान कोई ड्रोन किराना पहाड़ियों से टकरा गया होगा, जिसे पाकिस्तानी मीडिया ने गलत तरीके से प्रचारित किया था।

ट्रंप से मुलाकात को लेकर कई देशों के प्रतिनिधि उनके व्यवहार को लेकर रहते हैं अलर्ट

नई दिल्ली। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने वाले कई देशों के प्रतिनिधिमंडल उनके अप्रत्याशित व्यवहार को लेकर अलर्ट रहते हैं। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति और यूक्रेन के नेताओं के साथ उनकी बातचीत के दौरान भी कई बार ऐसा देखने को मिला है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि ऐसे में भारत भी कोई जोखिम नहीं लेना चाहता और बेहद सोच-समझकर आगे बढ़ रहा है। यही वजह है कि अमेरिका के साथ बातचीत और संभावित मुलाकातों को लेकर भारत का रुख सतर्क और सावधानी भरा है।आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ ऐसा क्या किया था, जिसके बाद भारत को ये सतर्कता बरतनी पड़ी। ये दोनों ही घटनाएं व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में हुई थीं। बता दें मई 2025 में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा व्यापार और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए अमेरिका के व्हाइट हाउस पहुंचे थे। ट्रंप के साथ बैठक में अचानक माहौल बदल गया। ट्रंप ने दक्षिण अफ्रीका के विपक्षी नेता जूलियस मालेमा का एक वीडियो दिखाया, जिसमें वह नारा लगाते नजर आए। ट्रंप ने इसके साथ दक्षिण अफ्रीका में श्वेत किसानों के खिलाफ हिंसा से जुड़े कुछ लेख भी पेश किए। इस दौरान उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में श्वेत लोगों के नरसंहार का मुद्दा भी

उठाया। ट्रंप ने इस बैठक में रामाफोसा के सामने इन दावों को लेकर कई सवाल रखे, जिसने उन्हें असमंजस में डाल दिया।रामाफोसा ने स्पष्ट किया कि किसी नेता के राजनीतिक नारे को दक्षिण अफ्रीकी सरकार की नीति नहीं माना जा सकता। उन्होंने यह भी कहा कि दक्षिण अफ्रीका में अपराध किसी एक समुदाय तक सीमित नहीं है और इसका असर अलग-अलग समुदायों पर पड़ता है। उन्होंने अमेरिका के एक प्रतिनिधिमंडल को दक्षिण अफ्रीका आने और वहां निवेश के अवसर तलाशने का न्योता भी दिया। इस मुलाकात के दौरान ट्रंप का आक्रामक रुख और रामाफोसा का शांत जवाब दोनों देशों के बीच कूटनीतिक बातचीत का प्रमुख हिस्सा बन गया।

वहीं 28 फरवरी 2025 को अमेरिका-यूक्रेन संबंधों के सबसे असाधारण सार्वजनिक टकरावों में गिना गया। ट्रंप और उपराष्ट्रपति वेंस और यूक्रेन के जेलेंस्की की व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में बैठक कैमरों के सामने ही तीखी बहस में बदल गई। जेलेंस्की अमेरिका से यूक्रेन को आगे भी समर्थन और रूस के खिलाफ सुरक्षा की गारंटी हासिल करना चाहते थे। वहीं ट्रंप का मुख्य जोर रूस-यूक्रेन युद्ध को जल्द खत्म कराने और दोनों पक्षों को बातचीत की मेज पर लाने पर था। बैठक में यूक्रेन के प्राकृतिक संसाधनों को लेकर अमेरिका-यूक्रेन के बीच एक मिनरल्स डील पर भी हस्ताक्षर होने की उम्मीद थी, लेकिन विवाद के बाद यह समझौता साइन नहीं हो सका। जेलेंस्की ने वेंस से लगभग चुनौती देते हुए पूछा कि वह किस तरह की कूटनीति की बात कर रहे हैं। वेंस ने जवाब दिया कि वह ऐसी कूटनीति की बात कर रहे हैं जिससे यूक्रेन में जारी तबाही खत्म हो।

1971 की विजय: जब भारत ने पाकिस्तान के घमंड को तोड़ा

नई दिल्ली। 16 दिसंबर, 1971 भारतीय इतिहास में एक ऐसा दिन है जिसे हमेशा याद रखा जाएगा, जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान के गुरूर को तोड़ते हुए एक ऐसी जीत हासिल की जो दुनिया के सैन्य इतिहास में शायद ही कभी देखी गई हो।

यह सिर्फ सैन्य समर्पण नहीं था, बल्कि एक नए राष्ट्र, बांग्लादेश, का जन्म भी था।उस ठंडी दिसंबर की रात को, पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) पूरी तरह से भारतीय सेना से घिरा हुआ था। ढाका शहर की ओर भारतीय फौजें तेजी से बढ़ रही थीं, और शहर के चारों ओर घेरा कस चुका था। ठीक एक दिन पहले, 15 दिसंबर को, पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति यह्या खान अभी भी अंत तक लड़ने के बड़े-बड़े दावे कर रहे थे।

हालांकि, यह सिर्फ खोखली बातें थीं, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी सेना पहले ही टूट चुकी थी। यह्या खान संयुक्त राष्ट्र (यूएन) पर भरोसा कर रहे थे कि वह एक सीजफायर या संघर्षविराम करवा देगा। अमेरिका और चीन उस समय पाकिस्तान का समर्थन कर रहे थे, और यूएन महासभा में 104 देशों ने युद्ध रोकने का प्रस्ताव भी पारित कर दिया था। लेकिन भारत ने अगस्त में ही सोवियत संघ के साथ संधि कर ली थी, और सोवियत संघ यूएन के ऐसे प्रस्तावों पर वीटो लगा रहा था, जिससे पाकिस्तान की उम्मीदें टूट रही थीं। 14 दिसंबर को ही यह्या ने पूर्वी पाकिस्तान में अपनी सेना के

जनरल नियाजी और गवर्नर मलिक को लड़ाई रोकने और जान बचाने के लिए उपाय करने का संदेश भेज दिया था। अपनी जनता को दिखाने के लिए, पाकिस्तान के राजनेता यूएन में हजार साल तक लड़ने की बातें कर रहे थे, लेकिन असलियत यह थी कि इस्लामाबाद में यह्या खान भी अपनी फौजों की वापसी की उम्मीद लगाए बैठे थे। इसी बीच, 16 दिसंबर की सुबह, भारतीय सेना प्रमुख सैम मानेकशॉ ने ईस्टर्न कमांड के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल जे. एफ. आर. जेकब को ढाका जाने और आत्मसमर्पण करवाने का आदेश दिया। जनरल जेकब बिना किसी हथियार के, एक स्टाफ ऑफिसर के साथ हेलीकॉप्टर से ढाका पहुँचे। पाकिस्तान के जनरल नियाजी सोच रहे थे कि वह युद्धविराम पर बातचीत करने आए हैं, लेकिन जनरल जेकब ने पहुँचते ही आत्मसमर्पण की शर्तें पढ़ दीं। नियाजी ने इसका विरोध किया, क्योंकि वह सिर्फ युद्धविराम की बात कर रहे थे। यदि ऐसा नहीं होता तो तुरंत हमला शुरू कर दिया जाएगा, ढाका पर हवाई बमबारी की जाएगी, और मुक्ति वाहिनी किसी को बख्शेगी नहीं।

जेकब ने उन्हें तीस मिनट का समय दिया। तीस मिनट बाद, नियाजी की खामोशी को स्वीकृति मानते हुए, रेसकोर्स के मैदान में दोपहर करीब साढ़े चार बजे, लेफ्टिनेंट जनरल ए.ए.के. नियाजी ने लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने आत्मसमर्पण के दस्तावेज पर दस्तखत किए। उन्होंने अपनी पिस्तौल सौंपी और अपनी वर्दी से अपमानजनक तरीके से बैज उतारे। किसी सेना के लिए इससे बढ़कर अपमान कुछ नहीं हो सकता। उसी शाम, बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया।

डॉ. ममता साहू ने राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष से की मुलाकात

महिला अधिकार, जागरूकता और सशक्तिकरण को लेकर प्रशिक्षण कार्यक्रम के सफल आयोजन पर हुई चर्चा

रायपुर. महिला अधिकारों के संरक्षण, महिलाओं में जागरूकता बढ़ाने और उन्हें सशक्त बनाने की दिशा में छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग द्वारा महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डा. ममता साहू ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्यालय में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती विजया रहाटकर से सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित प्रशिक्षण कार्यक्रम को लेकर विस्तार से महत्वपूर्ण चर्चा हुई। डॉ. ममता साहू ने प्रशिक्षण कार्यक्रम के सफल एवं प्रभावी आयोजन के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग से आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त

किया। कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं के अधिकारों, उनके संरक्षण से जुड़े प्रावधानों तथा उपलब्ध सहायता तंत्र की जानकारी अधिक प्रभावी ढंग से पहुंचाने पर जोर दिया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में प्रस्तावित यह प्रशिक्षण कार्यक्रम महिला अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के साथ-साथ महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति सजग और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल साबित होगा। प्रशिक्षण के माध्यम से महिला सशक्तिकरण से जुड़े विषयों पर व्यावहारिक जानकारी उपलब्ध कराने तथा जमीनी स्तर पर जागरूकता को और मजबूत करने का प्रयास किया जाएगा। डॉ. ममता साहू ने कहा कि महिलाओं को उनके अधिकारों और कानूनों की जानकारी देना सशक्तिकरण की पहली सीढ़ी है। राष्ट्रीय महिला आयोग के मार्गदर्शन से छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित प्रशिक्षण कार्यक्रम को प्रभावी रूप से आयोजित कर महिलाओं तक अधिकार एवं सुरक्षा संबंधी जानकारी पहुंचाने के प्रयासों को नई गति मिलेगी।

ताजा खबर
संक्षिप्त

जिला कार्यालयों के लिए 100 सहायक ग्रेड-3 पदों पर भर्ती को मंजूरी

रायपुर. छत्तीसगढ़ सरकार ने युवाओं को रोजगार देने और जिला स्तरीय प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक बड़ा निर्णय लिया है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने राज्य के विभिन्न जिलों में सहायक ग्रेड-3 के 100 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती की स्वीकृति प्रदान करते हुए सभी संबंधित जिला कलेक्टरों को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश जारी कर दिए हैं। इस निर्णय पर खुशी जताते हुए राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री श्री टंक राम वर्मा ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में सरकार युवाओं को शासकीय सेवाओं से जोड़ने और आम जनता को पारदर्शी व त्वरित सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासनों में इन पदों की भर्ती से जहाँ एक ओर युवाओं के लिए शासकीय सेवा के नए द्वार खुलेंगे, वहीं दूसरी ओर जिला कार्यालयों के कामकाज में और अधिक कसावट व गतिशीलता आएगी। विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, यह भर्ती प्रक्रिया सामान्य प्रशासन विभाग के दिशा-निर्देशों और प्रचलित सेवाभर्ती नियमों का पूरी तरह पालन करते हुए संपन्न की जाएगी। इस प्रस्ताव को वित्त विभाग से भी वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है। स्वीकृत 100 पदों में गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में 8, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी 7, खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई 7, मुंगेली 7, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर 7, बलौदाबाजार-भाटापारा 5, गरियाबंद 5, बेमेतरा 5, बिलासपुर 5, कोरबा 5, सक्ती 5, दुर्ग 4, बालोद 4, राजनांदगांव 4, कबीरधाम 3, जांजगीर-चांपा 3, रायगढ़ 3, धमतरी 2, सारंगढ़-बिलाईगढ़ 2, बलरामपुर-रामानुजगंज 2, सूरजपुर 2, सुकमा 2, बीजापुर 2 और जशपुर में 1 पद शामिल हैं। शासन ने सभी कलेक्टरों को निर्धारित आरक्षण एवं नियमानुसार शीघ्र भर्ती कार्यवाही पूरी करने के निर्देश दिए हैं।

सितंबर में 7 दिन मांस-मटन की बिक्री पर रोक

रायपुर. रायपुर में सितंबर महीने में शहर के सात प्रमुख पावन पर्वों के दौरान मांस-मटन की बिक्री और परोसने पर रोक रहेगी। रायपुर नगर निगम ने पशुवध गृह, मांस-मटन की दुकानों के साथ-साथ होटल, कैफे और रेस्टोरेंट को भी प्रतिबंध के दायरे में रखा है। महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग ने यह आदेश जारी किया है। निगम ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित तिथियों पर मांस-मटन की बिक्री या परोसने की शिकायत मिलने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी।

होटल, कैफे और रेस्टोरेंट भी दायरे में

नगर निगम के अनुसार, प्रतिबंध केवल मांस-मटन की दुकानों तक सीमित नहीं रहेगा। होटल, कैफे और रेस्टोरेंट में भी मांसाहारी खाद्य पदार्थ बेचने या परोसने पर कार्रवाई की जाएगी। यदि प्रतिबंधित तिथियों पर किसी प्रतिष्ठान में मांस-मटन की बिक्री या परोसने की पुष्टि होती है, तो निगम की टीम सामग्री जब्त करेगी और संबंधित व्यक्ति या संस्था के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

छत्तीसगढ़ का पहला पूरी तरह डिजिटल टोल प्लाजा : केसला टोल प्लाजा

रायपुर। राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा को अधिक सुगम, पारदर्शी और तकनीक-सक्षम बनाने की दिशा में छत्तीसगढ़ ने एक नई उपलब्धि हासिल की है। बिलासपुर-रायगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग-49 पर स्थित केसला टोल प्लाजा प्रदेश का पहला पूरी तरह डिजिटल टोल प्लाजा बन गया है, जहां टोल भुगतान की डिजिटल व्यवस्था के साथ-साथ स्थानीय नागरिकों के लिए लोकल मासिक पास की सुविधा भी पूरी तरह ऑनलाइन उपलब्ध करा दी गई है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (ठलअक) द्वारा देशभर के चयनित टोल प्लाजा पर शुरू की गई फास्टैग डिजिटल लोकल पास सुविधा के तहत छत्तीसगढ़ में केसला टोल प्लाजा को इस नई व्यवस्था से जोड़ा गया है। अब स्थानीय यात्रियों को मासिक पास बनवाने के लिए टोल प्लाजा पर व्यक्तिगत रूप से जाने अथवा भौतिक दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी।

बहनों के स्नेह से सजी 'विष्णु भैया' की कलाई, सुरक्षा-सम्मान का लिया संकल्प

नक्सलवाद के अंत से बहनों को मिला सुरक्षा और विश्वास का सबसे बड़ा उपहार : मुख्यमंत्री

रायपुर. रक्षाबंधन के पावन पर्व से पहले राजधानी रायपुर में आज भाई-बहन के स्नेह और राष्ट्ररक्षा के संकल्प का भावपूर्ण संगम देखने को मिला। बलवीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में आयोजित 'स्नेह की डोर' कार्यक्रम में केंद्रीय सुरक्षा बलों, सेना और पुलिस के जवानों की कलाइयों पर जब स्कूली बेटियों, दिव्यांग बेटियों और महिला स्व-सहायता समूहों की दीदियों ने रक्षा सूत्र बांधे तो पूरा वातावरण आत्मीयता, सम्मान और कृतज्ञता के भाव से भर उठा। कार्यक्रम का सबसे भावुक क्षण तब आया, जब वर्ष 2017 में रक्षाबंधन के ठीक एक दिन पूर्व नक्सली मुठभेड़ में वीरगति को प्राप्त हुए शहीद उपनिरीक्षक श्री युगल किशोर वर्मा की धर्मपत्नी श्रीमती माधुरी वर्मा ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की कलाई पर राखी बांधी। मुख्यमंत्री इस अवसर पर भावुक हो उठे। उन्होंने शहीद श्री वर्मा के सर्वोच्च बलिदान को नमन करते हुए शहीद जवानों के परिवारों के साथ सदैव खड़े रहने का संकल्प दोहराया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि राखी का यह धागा केवल भाई-बहन के स्नेह का बंधन नहीं, बल्कि एक शहीद परिवार के विश्वास और अपनत्व का प्रतीक है। हमारे वीर जवानों का बलिदान और उनके परिवारों का त्याग छत्तीसगढ़ कभी नहीं भूल सकता। शहीदों के परिवार हमारे अपने परिवार हैं और उनके सम्मान, स्वाभिमान तथा हर सुख-दु:ख में उनके साथ खड़े रहने का यह रिश्ता सदैव अटूट रहेगा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि देश और छत्तीसगढ़

को नक्सलवाद के आतंक से मुक्त कराने के लिए हमारे सुरक्षा बलों ने अदम्य साहस का परिचय दिया है और अनेक जवानों ने सर्वोच्च बलिदान दिया है। नक्सलवाद के अंत की ओर बढ़ता छत्तीसगढ़ हमारी बहनों के लिए सुरक्षा और विश्वास का सबसे बड़ा उपहार है। अब वह समय आ रहा है जब नक्सल हिंसा के कारण किसी बहन का सुहाग नहीं उजड़ेगा, किसी मां को अपना बेटा नहीं खोना पड़ेगा और किसी बहन को अपने भाई के सकुशल घर लौटने की चिंता नहीं सताएगी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दृढ़ संकल्प तथा सुरक्षा बलों के साहस और पराक्रम का उल्लेख करते हुए कहा कि नक्सलवाद के विरुद्ध निर्णायक सफलता ने बस्तर सहित पूरे छत्तीसगढ़ में शांति और विकास के नए युग का मार्ग प्रशस्त किया है। इस परिवर्तन में बस्तर की जनता का विश्वास और सहयोग भी महत्वपूर्ण रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अब बस्तर की पहचान हिंसा से नहीं, बल्कि शांति, विकास, समृद्ध जनजातीय संस्कृति, पर्यटन और नई संभावनाओं से होगी। लंबे समय तक नक्सलवाद के कारण विकास से वंचित रहे क्षेत्रों तक सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार और रोजगार के अवसर तेजी से पहुंचाए जा रहे हैं। सरकार का संकल्प बस्तर को देश के श्रेष्ठ और विकसित आदिवासी अंचलों में शामिल करना है। 'स्नेह की डोर' कार्यक्रम में सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, सेना और पुलिस के लगभग 800 जवान शामिल हुए। स्कूली छात्राओं, दिव्यांग बेटियों, स्वच्छता दीदियों, ड्रोन दीदियों, लखपति दीदियों और महिला स्व-सहायता समूहों की बहनों ने जवानों की कलाइयों पर राखी बांधी और राष्ट्र तथा समाज की सुरक्षा में उनके योगदान के प्रति आभार व्यक्त किया।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि उन्होंने अपने जीवन में ऐसा आत्मीय और अद्भुत दृश्य पहली बार देखा है। देश और प्रदेश की सुरक्षा के लिए घर-परिवार से दूर रहकर कठिन परिस्थितियों में अपने कर्तव्य का निर्वहन करने वाले जवानों को जब इतनी बड़ी संख्या में बहनों ने राखी बांधी तो रक्षाबंधन का पर्व अपने व्यापक अर्थ में साकार होता दिखाई दिया। हमारे जवान केवल सीमाओं और समाज के सुरक्षा प्रहरी नहीं, बल्कि प्रदेश की बहनों के भाई भी हैं। इस अवसर पर सुरक्षा बलों के जवानों ने भी बहनों की रक्षा, सम्मान और सुरक्षा का संकल्प लिया। मुख्यमंत्री ने सुरक्षा बलों के जवानों के शौर्य और समर्पण को नमन करते हुए नक्सलवाद के विरुद्ध निर्णायक लड़ाई में उल्लेखनीय योगदान देने वाले जवानों का सम्मान किया।

छत्तीसगढ़ में होगी देश की पहली राज्य स्तरीय हॉकी लीग

छह टीमें लेंगी हिस्सा, राज्य के खिलाड़ियों को मिलेगा बड़ा मंच, लोगो लांच

रायपुर। छत्तीसगढ़ में हॉकी की नई तस्वीर गढ़ने की तैयारी है। राज्य के खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा हॉकी इंडिया से मान्यता प्राप्त छत्तीसगढ़ हॉकी लीग के पहले सीजन का आयोजन किया जा रहा है। राजधानी रायपुर के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में होने वाली यह लीग देश के किसी भी राज्य में आयोजित होने वाली पहली राज्य-स्तरीय हॉकी लीग होगी, जिसे हॉकी इंडिया लीग की तर्ज पर पूरी तरह प्रोफेशनल और व्यावसायिक स्वरूप में आयोजित किया जाएगा। आयोजन की संभावित तिथियों 21 अक्टूबर से 1 नवम्बर तक लीग के मुकाबले खेले जाएंगे। उप मुख्यमंत्री (खेल युवा कल्याण) अरुण साव ने लीग के लोगो, टैगलाइन और शुभंकर का अनावरण किया। उन्होंने लॉन्चिंग कार्यक्रम में लीग के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि लीग का मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ की युवा हॉकी प्रतिभाओं को बड़ा मंच उपलब्ध कराना और उन्हें देश के श्रेष्ठ खिलाड़ियों के साथ खेलने तथा उनसे सीखने का अवसर देना है। खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सचिव यशवंत कुमार, संचालक सुश्री आकांक्षा शिक्षा खलखो, संयुक्त संचालक प्रभाकर पाण्डेय और छत्तीसगढ़ हॉकी संघ के अध्यक्ष फिरोज अंसारी सहित अनेक विभागीय अधिकारी भी लीग के लॉन्चिंग कार्यक्रम में मौजूद थे। उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में हॉकी की समृद्ध परंपरा रही है और राज्य में अनेक प्रतिभाशाली खिलाड़ी मौजूद हैं। छत्तीसगढ़ हॉकी लीग इन प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर देगी और प्रदेश के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर के अनुभव तथा प्रतिस्पर्धी वातावरण से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

केंद्रीय जेल रायपुर में बंदियों के लिए लगा नि:शुल्क नेत्र परीक्षण शिविर

रायपुर. राष्ट्रीय अंधत्व एवं अल्पदृष्टि नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत केंद्रीय जेल रायपुर में मंगलवार को बंदियों के लिए नि:शुल्क नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ केंद्रीय जेल रायपुर के अधीक्षक श्री योगेश सिंह क्षत्री ने किया। इसी के साथ रायपुर जिले में 41वें नेत्रदान पखवाड़े का भी शुभारंभ हुआ। देशभर में यह नेत्रदान पखवाड़ा 25 अगस्त से 8 सितंबर तक मनाया जा रहा है।

नेत्रदान को लेकर भ्रांतियां दूर करने पर जोर

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जेल अधीक्षक श्री योगेश सिंह क्षत्री ने कहा कि नेत्रदान मानवता की सेवा का महत्वपूर्ण माध्यम है। कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से, उम्र, लिंग, रक्त समूह अथवा धर्म की परवाह किए बिना नेत्रदान का संकल्प ले सकता है। मृत्यु के बाद किसी जरूरतमंद व्यक्ति के जीवन में रोशनी लाने का यह एक पुनीत प्रयास है। स्वास्थ्य विभाग के नेत्र चिकित्सक डॉ. मुकेश भगत ने नेत्रदान

से जुड़ी सावधानियों और भ्रांतियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नेत्रदान से केवल कॉर्निया से संबंधित दृष्टिहीनता वाले व्यक्ति ही लाभान्वित हो सकते हैं। मृत्यु के बाद निर्धारित समय-सीमा के भीतर कॉर्निया निकालना आवश्यक होता है। उन्होंने कहा कि नेत्रदान की प्रक्रिया में सामान्यत: 10 से 15 मिनट का समय लगता है और इससे चेहरे पर किसी प्रकार का निशान या विकृति नहीं आती। नेत्रदान को बढ़ावा देने के लिए देशभर में आयोजित होने वाला यह पखवाड़ा लोगों को मृत्यु के बाद नेत्रदान के महत्व के प्रति जागरूक करने और इससे जुड़ी भ्रांतियों को दूर करने का महत्वपूर्ण अवसर है। राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत नेत्र बैंकिंग और कॉर्निया प्रत्यारोपण सेवाओं को भी सुदृढ़ किया जा रहा है।

स्वास्थ्य विभाग की टीम ने किया नेत्र परीक्षण

शिविर में स्वास्थ्य विभाग की ओर से नेत्र चिकित्सक डॉ. मुकेश भगत, डॉ. टिकेश्वर, महिला खंड के लिए डॉ. स्वाति शर्मा, डॉ. आकांक्षा सहित नेत्र चिकित्सा सहायक अधिकारी श्री संजय शर्मा, श्री आर.पी. यादव, श्री प्रकाश राठौर, श्री ललित पाटकर, श्री अशोक श्रीवास, श्री प्रवीण शर्मा सहित चिकित्सकों एवं नेत्र चिकित्सा सहायकों की टीम उपस्थित रही। टीम ने बंदियों का नेत्र परीक्षण किया और उन्हें आंखों की देखभाल तथा दृष्टि संबंधी समस्याओं के प्रति आवश्यक परामर्श दिया।

प्रशिक्षण छोड़कर गायब हुए तीन बीएसएफ कांस्टेबल

हाईकोर्ट ने खारिज की बर्खास्तगी के खिलाफ याचिका

बिलासपुर. छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने प्रशिक्षण के दौरान बिना अनुमति लंबे समय तक गायब रहने वाले सीमा सुरक्षा बल के तीन कांस्टेबलों को सेवा से हटाने के फैसले को सही ठहराया है। अदालत ने तीनों पूर्व कांस्टेबलों की याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि वर्दीधारी बलों में अनुशासन सर्वोच्च प्राथमिकता है और कोई भी कर्मचारी अपनी मर्जी से कर्तव्य से अनुपस्थित नहीं रह सकता। जस्टिस राकेश मोहन पांडेय की एकल पीठ ने यह निर्णय सुनाया। मामले के अनुसार, त्रिलोक चंद साहू, तीरथ दास बर्मन और लक्ष्मीनारायण पटेल की नियुक्ति वर्ष 2008-09 में कांस्टेबल के पद पर हुई थी। विभाग ने जून 2009 में तीनों को महाराष्ट्र के चाकुर स्थित बीएसएफ स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर में बुनियादी प्रशिक्षण के लिए भेजा था। प्रशिक्षण के दौरान ही तीनों

बिना अनुमति के कैंप छोड़कर चले गए और निर्धारित समय पर वापस नहीं लौटे। इसमें त्रिलोक चंद साहू और तीरथ दास बर्मन करीब 47-47 दिन तक ड्यूटी से गायब रहे, जबकि लक्ष्मीनारायण पटेल 70 दिन बाद वापस लौटे। बिना अनुमति लंबी अनुपस्थिति के बाद विभाग ने वर्ष 2010 में एक महीने का नोटिस देकर तीनों को सेवा से हटा दिया था। इसके खिलाफ तीनों ने विभागीय अपील और दया याचिका दायर की, लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिली। इसके बाद, उन्होंने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी गई कि वे स्वास्थ्य संबंधी कारणों से अनुपस्थित रहे और उनके पास इसके दस्तावेज मौजूद हैं। विभाग ने कहा कि वर्दीधारी बल में बिना अनुमति अनुपस्थित रहना गंभीर अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। उच्च न्यायालय ने पाया कि तीनों कर्मचारी स्थायी नहीं थे, बल्कि 1960 के नियमों के तहत अस्थायी थे। तीन साल की सेवा पूरी न होने के कारण उन्हें क्वासी-पर्मानेंट कर्मचारी का दर्जा नहीं मिला था। अदालत ने माना कि अस्थायी कर्मचारियों की सेवा नियम 12 के तहत एक महीने के नोटिस पर समाप्त की जा सकती है और विभागीय जांच अनिवार्य नहीं है। अदालत ने स्पष्ट किया कि प्रशिक्षण अधूरा छोड़कर लंबे समय तक गायब रहना गंभीर मामला है। अदालत ने सेवा से हटाने की कार्रवाई को उचित मानते हुए तीनों याचिकाएं खारिज कर दीं।

मंत्री चौधरी ने सेक्टर-12 फेस-2 में 119.89 करोड़ रुपए की आवासीय परियोजना का किया भूमिपूजन

नवा रायपुर को देश की अग्रणी ग्रीनफील्ड सिटी के रूप में विकसित करने पर जोर: ओपी चौधरी

रायपुर. आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओ.पी. चौधरी ने नवा रायपुर अटल नगर के सेक्टर-12 फेस-2 में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल की 119.89 करोड़ रुपए की आवासीय परियोजना का भूमिपूजन किया। मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि नवा रायपुर अटल नगर में आवासीय सुविधाओं के विस्तार की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि परियोजना के अंतर्गत HIG एवं स्ङ्घत्न श्रेणी के कुल 348 भवनों का निर्माण किया जाएगा। आवासों की बढ़ती मांग को देखते हुए इसी सेक्टर में आगामी चरण में 704 नए फ्लैट का निर्माण भी शीघ्र किया जाएगा।

गुणवत्ता के नए मानदंड स्थापित करे हाउसिंग बोर्ड

मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल को केवल आवास निर्माण तक सीमित नहीं रहना है, बल्कि एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में अपनी पहचान मजबूत करनी है। उन्होंने निर्माण कार्यों में गुणवत्ता को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि केवल सरकारी स्ह्रक्र के आधार पर कार्य करने के बजाय आवश्यकतानुसार उससे बेहतर गुणवत्ता की सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए। भवनों में गुणवत्तापूर्ण टाइल्स, फिटिंग्स और आकर्षक एवं आधुनिक रंगों का उपयोग किया जाए, ताकि हाउसिंग बोर्ड

की कॉलोनियां सरकारी परियोजनाओं की पारंपरिक छवि से अलग दिखाई दें। उन्होंने कहा कि गुणवत्ता में सुधार के लिए यदि परियोजना की लागत में 5 से 10 प्रतिशत तक वृद्धि भी होती है, तो इसे उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। आने वाले समय में हाउसिंग बोर्ड की परियोजनाओं में गुणवत्ता का नया मानदंड स्थापित किया जाना चाहिए।

आरडब्ल्यूए को मजबूत कर समय पर कॉलोनियां हैंडओवर करने पर जोर

आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री चौधरी ने हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनियों में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (ऋङ्ख) को मजबूत करने और कॉलोनियों का समय पर हैंडओवर सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि कॉलोनी के विकास एवं रखरखाव की जिम्मेदारी सरकार के साथ-साथ रहवासियों की भी है। दोनों पक्षों को अपनी-अपनी जिम्मेदारियां निभानी होंगी। उन्होंने सेक्टर-12 के रहवासियों से ऋङ्ख का गठन कर कॉलोनी के रखरखाव में सक्रिय भूमिका निभाने का आग्रह किया। साथ ही नए हितग्राहियों से निर्माण कार्य की गुणवत्ता की निगरानी में सहयोग करने और किसी भी कमी की जानकारी मंडल के अध्यक्ष, आयुक्त अथवा संबंधित अधिकारियों को देने की अपील की।

बिना मांग के नहीं होगी नई आवासीय परियोजना ः मंत्री चौधरी

मंत्री ओ.पी. चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल को नई दिशा देने के लिए कई महत्वपूर्ण नीतिगत सुधार किए हैं। उन्होंने कहा कि एक समय कर्ज से जूझ रहे मंडल को लगभग 700 करोड़ रुपए का ऋण चुकाकर कर्जमुक्त किया गया। इसके बाद मंडल की कार्यप्रणाली में सुधार करते हुए यह नीति निर्धारित की गई कि बिना मांग के किसी स्थान पर आवासीय परियोजना शुरू नहीं की जाएगी।

नवा रायपुर में शिक्षा, स्वास्थ्य और तकनीकी क्षेत्र में तेजी से हो रहा विस्तार

मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि नवा रायपुर अटल नगर देश की प्रमुख ग्रीनफील्ड सिटी के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है। उन्होंने बताया कि नवा रायपुर के लगभग एक-तिहाई हिस्से को रिक्रिएशनल क्षेत्र के रूप में विकसित किया गया है, जबकि 28 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र में हरियाली है। उन्होंने नवा रायपुर में तेजी से विकसित हो रहे शिक्षा, स्वास्थ्य, तकनीक और अन्य क्षेत्रों का उल्लेख करते हुए कहा कि यहां NIFT, NFSU, NIELIT, IIM, HNLU और IIIT जैसे प्रतिष्ठित संस्थान मौजूद हैं। इसके अलावा नरसी मोनजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, श्री श्री रविशंकर जी का केंद्र, ब्रह्मकुमारी परिसर, एआई डेटा सेंटर और सेमीकंडक्टर यूनिट जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाएं भी नवा रायपुर के विकास को नई गति दे रही हैं।

आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने कहा कि नवा रायपुर में स्वास्थ्य सुविधाओं का भी विस्तार हो रहा है। सत्य साईं अस्पताल में जरूरतमंद मरीजों के नि:शुल्क हृदय ऑपरेशन किए जा रहे हैं।

अस्पताल परिसर के विस्तार के लिए अतिरिक्त भूमि उपलब्ध कराई गई है, जहां हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर, जीनोम रिसर्च सेंटर और नर्सिंग कॉलेज जैसी सुविधाओं का विकास किया जाएगा। मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि नवा रायपुर में खेल, कॉन्फ्रेंस, शिक्षा, स्वास्थ्य और वेडिंग डेस्टिनेशन सहित विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से विकास हो रहा है। आने वाले एक-दो वर्षों में वर्तमान में चल रही अनेक परियोजनाओं का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देगा।

क्रिकेट इतिहास में सबसे अधिक ओवर फेंकने वाले शीर्ष दो गेंदबाज है मुरलीधरन और कंबले

कोलंबो। श्रीलंका के महान स्पिनर मुथैया मुरलीधरन के नाम गेंदबाजी में कई रिकार्ड है। इन्हीं में एक सबसे अधिक ओवर फैंकने का रिकार्ड भी मुरलीधरन के नाम है। वहीं भारतीय टीम के दिग्गज स्पिनर रहे अनिल कुंबले का नाम दूसरे स्थान पर है। मुरलीधरन ने अपने 1992 से 2010 तक के करियर में कुल 133 टेस्ट मैचों में 7339.5 ओवर गेंदबाजी की। इन ओवरों में उन्होंने 800 टेस्ट विकेट लिए हैं, जो टेस्ट क्रिकेट में किसी भी गेंदबाज द्वारा लिए गए सर्वाधिक विकेट हैं, और उनका गेंदबाजी औसत 22.73 रहा। उनके ठीक बाद, भारत के कुंबले ने 1990 से 2008 के बीच 132 टेस्ट मैचों में 6808.2 ओवर फेंके। कुंबले ने अपने दमदार करियर में 619 विकेट हासिल किए और उनका औसत 29.65 रहा, जो उनकी निरंतरता को दशार्ता है।

इस विशेष सूची में ऑस्ट्रेलिया के महान लेग स्पिनर शेन वॉर्न भी तीसरे स्थान पर हैं, जिन्होंने 1992 से 2007 तक 145 टेस्ट मैचों में

6784.1 ओवर डाले और 708 विकेट झटके। उनके बाद इंग्लैंड के तेज गेंदबाजी के दिग्गज जेम्स एंडरसन का नाम आता है, जिन्होंने 2003 से लेकर अब तक 188 टेस्ट मैचों में 6672.5 ओवर फेंके हैं। एंडरसन ने इस दौरान 704 विकेट लिए हैं।

ऑस्ट्रेलिया के ऑफ स्पिनर नाथन लियोन भी इस सूची में अपनी जगह बनाए हुए हैं, जिन्होंने 2011 से अब तक 143 टेस्ट मैचों में 5853.1 ओवर फेंके हैं और 571 विकेट अपने नाम किए हैं। लियोन भी एंडरसन की तरह अभी तक टेस्ट क्रिकेट में सक्रिय हैं। इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड ने अपने 167 टेस्ट मैचों के करियर (2007-2023) में 5616.2 ओवर फेंके और 604 विकेट लिए। वेस्टइंडीज के दिग्गज तेज गेंदबाज कोर्टनी वॉल्श ने भी 1984 से 2001 के बीच 132 टेस्ट मैचों में 5003.1 ओवर डालकर 519 विकेट लेकर अपनी छाप छोड़ी। ये सभी आंकड़े दशार्ते हैं कि टेस्ट क्रिकेट में लंबी अवधि तक सफल रहने के लिए न केवल कौशल बल्कि अविश्वसनीय शारीरिक और मानसिक दृढ़ता की आवश्यकता होती है।

टी20 में जडेजा के नाम नहीं है एक भी अर्धशतक

मुम्बई। भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर रविन्द्र जडेजा के नाम गेंदबाजी और बल्लेबाजी में कई रिकार्ड हैं। टी20 टूनार्मेंटों में अपने प्रदर्शन से उन्होंने कई बार भारतीय टीम को जीत दिलायी है। इसके बाद भी वह अपने पूरे टी20 करियर में एक भी अर्धशतक नहीं लगा पाये हैं। जडेजा ने 2025 टी20 विश्वकप में भारतीय टीम की जीत के बाद इस प्रारुप से संन्यास ले लिया था। वहीं अगर इस प्रारुप में सबसे अधिक अर्धशतक की बात करें तो वह पाकिस्तान के बाबर आजम के नाम हैं। बाबर ने सबसे अधिक 42 अर्धशतक लगाये हैं।

जडेजा ने अपने करियर में भारतीय टीम की ओर से 74 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले। 41 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए जडेजा ने 515 रन बनाए, जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 46 रन रहा। इस दौरान उनका बल्लेबाजी औसत 21.45 और स्ट्राइक रेट 127.16 रहा। उन्होंने अपने करियर में 39 चौके और 14 छक्के भी लगाए, लेकिन एक भी बार वह अर्धशतक नहीं लगा पये।

हालांकि, अगर उनके पूरे टी20 करियर पर नजर डालें तो तस्वीर थोड़ी अलग है। इंटरनेशनल क्रिकेट से बाहर फ्रेंचाइजी और घरेलू टी20 मैचों को मिलाकर जडेजा ने कुल 360 टी20 मैच खेले हैं। इन मैचों की 263 पारियों में उन्होंने 4251 रन बनाए हैं। यहां उनका बल्लेबाजी औसत 27.42 और स्ट्राइक रेट 131.08 रहा है। सबसे खास बात यह है कि इस दौरान उनके नाम 5 अर्धशतक दर्ज हैं, जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 77 रन है। यह दशार्ता है कि उनमें टी20 प्रारूप में अर्धशतक लगाने की क्षमता तो थी, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निचले क्रम में बल्लेबाजी करने और कम मौके मिलने के कारण वे यह मुकाम हासिल नहीं कर पाए।

रवींद्र जडेजा की असली पहचान उनकी बहुमुखी प्रतिभा रही है, खासकर उनकी धारदार गेंदबाजी और चुस्त फील्डिंग। बल्लेबाजी में अर्धशतक न बना पाने के बावजूद, उन्होंने गेंद से लगातार टीम के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। अपने 74 टी20 इंटरनेशनल मैचों की 71 पारियों में गेंदबाजी करते हुए जडेजा ने 54 विकेट लिए उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 15 रन देकर 3 विकेट रहा और उनकी इकॉनमी रेट 7.13 रही। पूरे टी20 करियर में उन्होंने 326 पारियों में 245 विकेट लिए, जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 16 रन देकर 5 विकेट रहा। भारतीय टीम के लिए जडेजा ने एक ऐसे ऑलराउंडर की भूमिका निभाई, जो निचले क्रम में तेजी से रन बनाने, विकेट लेने वाली गेंदबाजी करने और अपनी लाजवाब फील्डिंग से मैच का रुख बदलने में सक्षम थे।

3 अक्टूबर से शुरू होगी वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स लीग

सिडनी। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स लीग क्रिकेट (डब्लयूसीएल) का तीसरा सत्र 3 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा। ऐसे में प्रशंसकों को एक बार फिर गुजरे जमाने के दिग्गज बल्लेबाजों का आक्रामक खेल देखने को मिलेगा। चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स लीग से कई पूर्व क्रिकेटरों को एक मंच मिलता है। इस बार बांग्लादेश के महमुदुल्लाह रियाद जैसे खिलाड़ी भी इस लीग में शामिल होंगे।

वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स का यह तीसरा सत्र है। लीग के पहले सत्र में इंडिया चैंपियंस ने पाकिस्तान चैंपियंस को हराकर खिताब जीता था। वहीं, दूसरे सत्र में दक्षिण अफ्रीका चैंपियंस ने पाकिस्तान चैंपियंस को हराकर ट्रॉफी जीती थी। इस बार टूनार्मेंट में बांग्लादेश चैंपियंस को भी शामिल किया गया है, जिससे टूनार्मेंट में नई टीमों और खिलाड़ियों का प्रवेश होगा होगा और प्रतिस्पर्धा और भी बढ़ने की उम्मीद है।

वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स की ओर से कहा गया है कि दो सफल सत्र के बाद, लीग का तीसरा सत्र अधिक रोमांचक रहने की उम्मीद है। ये सत्र प्रशंसकों को एक अभूतपूर्व अनुभव देने का वादा करता है, जहां क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी एक बार फिर अपने पुराने और आकर्षक अंदाज में नजर आएंगे। लीग का लक्ष्य रिटायर हो चुके खिलाड़ियों को एक मंच देना है, जिससे वे खेल के प्रति अपने जुनून को जीवित रख सकें और प्रशंसकों का मनोरंजन कर सकें। लीग के सीईओ हर्षित तोमर ने आगामी सीजन को लेकर अपनी उत्सुकता जाहिर की। उन्होंने कहा, सीजन 3 बहुत खास होने वाला है। इस सत्र का आयोजन इंग्लैंड से बाहर होगा। इस सत्र में क्रिकेट के सबसे बड़े नाम और ऐसे स्टार्स को लेकर आएंगे जिनके बारे में प्रशंसक सोच सकते हैं।

सिंधु और आयुष चाइना मास्टर्स में नजर नहीं आयेंगे

नई दिल्ली। भारतीय महिला बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु अगले माह की शुरूआत में होने वाले चाइना मास्टर्स सुपर 750 टूनार्मेंट में नजर नहीं आयेंगी। सिंधु के अलाव पुरुष एकल खिलाड़ी आयुष शेट्टी भी इस टूनार्मेंट में नहीं खेलेंगे। चाइना ओपन अगले माह 1 सितंबर से शुरू हो रहा है। एशियाई खेलों से पहले बीडब्लयएफ विश्व टूर का यह एकमात्र बड़ा इवेंट है, जिसका आकर्षण इन खिलाड़ियों के नहीं होने से कम होगा।

हाल में हुई विश्व चैंपियनशिप में आयुष ने शानदार प्रदर्शन किया था, जहां उन्होंने पहले ही दौर में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी शी युकी को हैरानर कर दिया था। हालांकि, वह राउंड ऑफ 16 में इंडोनेशिया के अल्वी फरहान से हार गए थे। वहीं सिंधु भी वर्ल्ड चैंपियनशिप में

राउंड ऑफ 16 तक पहुंची थीं पर चीन की दुनिया की नंबर 3 खिलाड़ी वांग झी यी से उन्हें कड़े मुकाबले में हार झेलनी पड़ी थी। माना जा रहा है कि उस मैच से उन्हें जो थकान हुई है। उसी कारण वह चायना ओपन नहीं खेल रही है।

पुरुष एकल में आयुष के हटने के बाद अब लक्ष्य सेन और किदांबी श्रीकांत भारत की आर से उतरेंगे। लक्ष्य ने विश्व चैंपियनशिप में निराशाजनक प्रदर्शन किया था, जहां वह दूसरे दौर में अमेरिका के दुनिया के नंबर 92 खिलाड़ी गैरेट टैन से हारकर जल्दी बाहर हो गए थे। दूसरी ओर महिला एकल में मालविका बंसोद और आकर्षी कश्यप भी नहीं उतरेंगी। ऐसे में अब उन्नति हुड्डा, देविका सिहाग और तन्वी शर्मा भारत की ओर से पदक दावेदार रहेंगी।

टेस्ट क्रिकेट में जिम्बाब्वे के फ्लावर के नाम है सबसे अधिक स्कोर का रिकार्ड

हरारे। जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान और विकेटकीपर बल्लेबाज एंडी फ्लावर के नाम एक ऐसा रिकार्ड है जो अब तक कोई भी नहीं तोड़ पाया है। फ्लावर ने टेस्ट क्रिकेट में ये रिकार्ड 26 साल पहले बनाया था।

फ्लावर ने साल 2000 में नागपुर में भारत के खिलाफ 444 गेंदों पर नाबाद 232 रन बनाए थे। फ्लावर ने अपनी उस पारी में 30 चौके और 2 छक्के लगाये थे। उन्होंने करीब 544 मिनट बल्लेबाजी करते हुए भारतीय गेंदबाजों को कोई अवसर नहीं दिया था। संगाकारा ने अपनी पारी में 327 गेंदें खेलीं और 33 चौके तथा 3 छक्के लगाए। उनकी यह पारी न सिर्फ सर्वाधिक रन बनाने वाली रही, बल्कि धैर्य, एकाग्रता और लंबे समय तक क्रीज पर टिके रहने का अद्भुत उदाहरण भी पेश करती है। इस रिकॉर्ड को तोड़ने के सबसे करीब श्रीलंका के दिग्गज कुमार संगाकारा पहुंचे थे। उन्होंने साल 2002 में पाकिस्तान के खिलाफ लाहौर में 230 रनों की शानदार पारी खेली थी पर वह मात्र तीन रन से एंडी फ्लावर के विश्व रिकॉर्ड को तोड़ नहीं पाये थे

वहीं भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और

विकेटकीपर महेन्द्र सिंह धोनी भी एक बार इस आंकड़े के बेहद करीब पहुंचे थे पर रिकार्ड नहीं तोड़ पाये। उन्होंने साल 2013 में चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 224 रन बनाए थे, जो किसी विकेटकीपर-बल्लेबाज द्वारा तीसरी सबसे बड़ी पारी है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज विकेटकीपर बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट, ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जोहान्सबर्ग में 2002 में नाबाद 204 रन बनाये थे। गिलक्रिस्ट ने यह पारी केवल 213 गेंदों में खेली थी, जिससे उनकी आक्रामक पारी का अंदाजा लगाया जा सकता है। बांग्लादेश के मुशफिकुर रहीम भी इस विशिष्ट सूची में शामिल हैं। उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ मीरपुर में नाबाद 219 रन बनाये थे।

इस प्रकार साल 2000 से लेकर अब तक, टेस्ट क्रिकेट में कई बेहतरीन विकेटकीपर-बल्लेबाज आए और उन्होंने यादगार पारियां खेलीं पर कोई भी फ्लावर का रिकार्ड नहीं तोड़ पाया। इसी कारण फ्लावर की भारत के खिलाफ खेली गई नाबाद 232 रनों की पारी आज भी टेस्ट क्रिकेट में विकेटकीपर-बल्लेबाज द्वारा सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर का अटूट रिकॉर्ड बनी हुई है, जो उनकी असाधारण प्रतिभा और धैर्य का बेजोड़ प्रमाण है।

कारोबार

चीनी के दाम 18 फीसदी घटे, कारखाने से निकलने पर भाव 55 रुपए किलो पर आया, अभी और होगी सस्ती

नई दिल्ली। सरकार की ओर से चीनी के आयात को अनुमति दिए जाने के बाद दाम 18 फीसदी तक गिरकर 55 रुपए प्रति किलो पर आ गए हैं। ये एक्स-मिल यानी कारखाने से निकलने वाले दाम है।

पिछले हफ्ते चीनी का भाव 67 प्रति रुपए किलोग्राम के ऑल-टाइम हाई स्तर पर पहुंच गया था। केंद्रीय खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने बताया कि सरकार ने चीनी की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने 10 लाख टन कच्चे चीनी के आयात की अनुमति दी थी। इसके अलावा, बड़े खरीददारों पर स्टॉक लिमिट लागू की गई है और राज्यों को जमाखोरी रोकने के निर्देश दिए गए हैं। इन फैसलों के बाद मिल स्तर पर कीमतों में गिरावट शुरू हो चुकी है। आमतौर पर एक्स-मिल रेट और थोक बाजार की कीमत में दो से तीन रुपए प्रति किलोग्राम का अंतर होता है। वहीं, एक्स-मिल और खुदरा बाजार की दरों में सात से आठ रुपए प्रति किग्रा का अंतर रहता है।

फिलहाल खुदरा बाजार में ग्राहकों को पूरी राहत नहीं मिली है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 24 अगस्त को देशभर में चीनी का औसत थोक भाव 58.29 रुपए प्रति किग्रा और औसत खुदरा भाव 63.05 रुपए प्रति किग्रा दर्ज किया गया। हालांकि,

मिल स्तर पर दाम घटने के बाद जल्द ही आम उपभोक्ताओं के लिए भी रिटेल दुकानों पर चीनी सस्ती हो जाएगी नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज के प्रबंध निदेशक प्रकाश नाइकनावरे ने कहा कि देशभर में एक्स-मिल कीमतें 55 रुपए किलो से नीचे आ गई हैं। बाजार में कालाबाजारी और जमाखोरी को रोकने के लिए फ्लाइंग स्क्वॉड तैनात किए गए हैं, जो लगातार निरीक्षण कर रहे हैं।

15 दिन से ज्यादा स्टॉक रखने पर पाबंदी

सरकार ने चीनी व्यापारियों और डीलरों पर स्टॉक रखने की सीमा लागू कर चुकी है। नए नियमों के तहत महीने में 10 मीट्रिक टन से अधिक चीनी का कारोबार करने वाले डीलर 15 दिन से अधिक की खपत का स्टॉक जमा करके नहीं रख सकते। बता दें कि चीनी के आयात को टैक्स फ्री भी कर दिया है। निर्यात पर 30 सितंबर, 2026 तक रोक लगा दी है। डीलरों के लिए 30 नवंबर तक 400 टन तक की स्टॉक लिमिट तय की।

देश में चीनी का पर्याप्त स्टॉक, कमी का दावा गलत

खाद्य मंत्रालय के मुताबिक, विपणन वर्ष 2025-26 (अक्तूबर-सितंबर) के लिए देश में चीनी का उत्पादन लगभग 306 लाख टन रहने का अनुमान है। हालांकि यह आंकड़ा शुरूआती अनुमान 343 लाख टन से कम है, लेकिन देश की सालाना घरेलू मांग केवल 280 से 285 लाख टन के आसपास रहती है। ऐसे में देश के पास मांग पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त बफर स्टॉक उपलब्ध है।

सेबी ने मैक्स फाइनेंशियल, मैक्स लाइफ समेत एक्सिस समूह की कंपनियों का मामला निपटाया

नई दिल्ली। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने 3,911 करोड़ रुपये के कथित शेयरधारक नुकसान से जुड़े मामले में मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, मैक्स लाइफ और एक्सिस समूह की कंपनियों के खिलाफ कार्यवाही समाप्त कर दी है। बाजार नियामक ने कहा कि खुलासा संबंधी चूक और धोखाधड़ी की योजना के आरोप साबित नहीं हुए। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का अब नाम एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस है।

सेबी ने सोमवार को पारित अंतिम आदेश में मैक्स समूह के संस्थापक एवं चेयरमैन अनलजीत सिंह समेत सात व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही समाप्त कर दी। यह कार्यवाही 24 अक्टूबर, 2024 को जारी कारण बताओ नोटिस (एससीएन) के बाद शुरू हुई थी। यह नोटिस 2009-10 से 2021-22 के दौरान मैक्स और एक्सिस समूह की कंपनियों के बीच हुए लेनदेन की जांच के बाद जारी किया गया था।

सेबी ने 2010, 2015 और 2020 में किए गए तीन समझौतों की जांच की थी। मामले में आरोप था कि मैक्स फाइनेंशियल ने इन लेनदेन के बारे में पर्याप्त और समय पर खुलासा नहीं किया। साथ ही, मैक्स फाइनेंशियल, मैक्स

लाइफ और एक्सिस समूह की कंपनियों ने ऐसी योजना बनाई जिससे मैक्स समूह की कंपनियों तथा उनके शेयरधारकों के नुकसान पर एक्सिस बैंक को अनुचित लाभ मिला। वर्ष 2010 के समझौते के तहत मैक्स लाइफ के शेयर एक्सिस बैंक को अंकित मूल्य पर जारी किए गए और बाद में उन्हें कई चरणों में लगातार ऊंची कीमतों पर खरीदा गया। वर्ष 2015 के समझौते में मैक्स फाइनेंशियल, मित्सुई सुमितोमो इंश्योरेंस कंपनी और एक्सिस बैंक के बीच मैक्स लाइफ की करीब 4.99 प्रतिशत हिस्सेदारी के हस्तांतरण का समझौता हुआ। बाद में इन शेयर को ऊंची कीमतों पर चरणबद्ध तरीके से वापस खरीदा गया।

वर्ष 2020 के समझौते के तहत शुरूआत में एक्सिस बैंक द्वारा मैक्स लाइफ में 29.002 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने की बात शामिल थी। नियामकीय चचाओं के बाद समझौते में बदलाव किया गया और मार्च-अप्रैल 2021 में एक्सिस समूह की कंपनियों ने मैक्स लाइफ में हिस्सेदारी खरीदी। सेबी के कारण बताओ नोटिस में आरोप लगाया गया था कि इन लेनदेन को इस तरह तैयार किया गया था कि अनुमत 'कमीशन' से अधिक लाभ एक्सिस समूह की कंपनियों को मिले। इसमें कहा गया था कि इन समझौतों से मैक्स फाइनेंशियल के शेयरधारकों को 3,911.95 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ और इतनी ही राशि का लाभ एक्सिस समूह की कंपनियों को मिला। हालांकि, ये कारण बताओ नोटिस में लगाए गए आरोप थे और अंततः ये साबित नहीं हो पाए।

सेबी के पूर्णकालिक सदस्य अमरजीत सिंह ने कहा कि सूचीबद्ध कंपनियों पर लागू खुलासा संबंधी ढांचा 2010 के बाद काफी विकसित हुआ है। उन्होंने कहा कि एमएफएसएल के खुलासे अधिक व्यापक हो सकते थे और अधिक सतर्क रुख अपनाना बेहतर होता। सिंह ने कहा कि आचरण का आकलन उस समय लागू कानूनी प्रावधानों के आधार पर किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, "एससीएन में जिन विशिष्ट प्रावधानों का उल्लेख किया गया है, उनके उल्लंघन को साबित करने वाली सामग्री के अभाव में खुलासा संबंधी आरोप कायम नहीं रह सकते।" नियामक ने धोखाधड़ी की योजना के आरोप को भी खारिज कर दिया। सेबी ने कहा कि मैक्स फाइनेंशियल द्वारा महत्वपूर्ण जानकारी को जानबूझकर छिपाने का आरोप साबित नहीं हुआ। उसे कीमत या कारोबार की मात्रा में हेरफेर, कृत्रिम बाजार तैयार करने या बाजार की निष्पक्षता में किसी अन्य तरह के हस्तक्षेप का भी कोई सबूत नहीं मिला।

सेबी ने कहा कि मैक्स फाइनेंशियल, मैक्स लाइफ, एक्सिस बैंक, एक्सिस कैपिटल और एक्सिस सिक्योरिटीज ने मैक्स फाइनेंशियल के शेयरधारकों को धोखा देने के लिए धोखाधड़ी की योजना बनाई थी, यह आरोप भी साबित नहीं हुआ। आदेश में अलग-अलग अवधि में मैक्स फाइनेंशियल का नेतृत्व करने वाले लोगों के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर भी विचार किया गया। सेबी ने 114 पृष्ठ के आदेश में कहा, "एमएफएसएल के खिलाफ मूल खुलासा संबंधी उल्लंघन या धोखाधड़ी साबित नहीं होने और उनके व्यक्तिगत कार्यों एवं दायित्वों से संबंधित कारणों के मद्देनजर एमएफएसएल के प्रमुख प्रबंधकीय कर्मचारियों के खिलाफ आरोप भी कायम नहीं रह सकते।" आदेश में अलग से कहा गया कि कारण बताओ नोटिस 25 इकाइयों को जारी किया गया था। इनमें से एमएफएसएल के 13 गैर-कार्यकारी/स्वतंत्र निदेशकों ने निपटान आवेदन दाखिल किए हैं जो फिलहाल प्रक्रियाधीन हैं। सेबी के (निपटान कार्यवाही) विनियम, 2018 के तहत किसी निर्दिष्ट कार्यवाही में निपटान आवेदन दाखिल करने से कार्यवाही जारी रखने पर रोक नहीं लगती।

शेयर बाजार में उछाल, तेल की कीमतों में गिरावट से सेंसेक्स-निफ्टी ने भरी उड़ान

नई दिल्ली। बुधवार को भारतीय शेयर बाजार में तेजी जारी रही। सेंसेक्स 321 अंक और निफ्टी 42 अंक ऊपर बंद हुए। हॉर्मुज जलडमरूमध्य के फिर से खुलने की उम्मीद और तेल की कीमतों में गिरावट ने बाजार को सहारा दिया। जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के विशेषज्ञों ने बाजार के लिए सकारात्मक कारकों और आगे की संभावनाओं पर प्रकाश डाला।

बुधवार को भारतीय शेयर बाजार में तेजी का सिलसिला जारी रहा। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों प्रमुख सूचकांक हरे निशान पर कारोबार करते दिखे। तेल की कीमतों में गिरावट ने बाजार को बड़ा सहारा दिया। ईरान ने ओमान के साथ हॉर्मुज जलडमरूमध्य के प्रबंधन पर बातचीत फिर से शुरू की है। इससे इस रणनीतिक जलमार्ग के जल्द खुलने की नई उम्मीदें जगी हैं। सेंसेक्स 321 अंक बढ़कर 77,970 के स्तर पर पहुंच गया। निफ्टी 50 करीब 42 अंक की वृद्धि के साथ 24,377 पर पहुंच गया। व्यापक बाजार भी सकारात्मक रुख के साथ खुले। निफ्टी स्मॉलकैप 100 और निफ्टी मिडकैप 100 सूचकांक 0.45 फीसदी ऊपर चढ़े। एनएसई पर 1,931 शेयरों में बढ़त दर्ज की गई। वहीं, 566 शेयरों में गिरावट आई और 120 शेयर अपरिवर्तित रहे। ईद-ए-मिलाद की छुट्टी के कारण बुधवार को भारतीय विदेशी मुद्रा बाजार बंद रहेगा।

सेंसेक्स में इटरनल शेयर्स करीब दो फीसदी उछलकर सबसे अधिक लाभ में रहे। आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई के शेयरों में भी करीब एक फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई। दूसरी ओर, टाटा स्टील, इंफोसिस और भारती एयरटेल के शेयरों में करीब एक फीसदी की गिरावट आई। विभिन्न क्षेत्रों में निफ्टी पीएसयू बैंक सूचकांक एक फीसदी से अधिक बढ़ा। हालांकि, निफ्टी मेटल, निफ्टी आईटी और निफ्टी ऑटो लाल निशान में फिसले। जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के मुख्य निवेश रणनीतिकार वी के विजयकुमार के अनुसार, बाजार के लिए दो मुख्य सकारात्मक कारक हैं। पहला, अमेरिका और ईरान के बीच एक और युद्धविराम की खबर है। हॉर्मुज जलडमरूमध्य के माध्यम से शिपिंग फिर से शुरू करने की पहल हुई है। इससे ब्रेंट क्रूड दर 86.3 डॉलर पर आ गई है। भारतीय बाजार की तेजी मुख्य रूप से कच्चे तेल की ऊंची कीमतों से बाधित थी। कच्चे तेल में यह तेज गिरावट बाजार के लिए सकारात्मक है। दूसरा, अमेरिका में बॉन्ड यील्ड में गिरावट आई है।

मोहन कैबिनेट ने सिवनी-बालाघाट फोरलेन पर लगाई मुहर

3,961 करोड़ की लागत से होगा तैयार, कई प्रस्ताव मंजूर

नई दिल्ली। प्रदेश की राजधानी भोपाल में मंगलवार को मोहन कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सरकार ने सिवनी और बालाघाट के फोरलेन निर्माण पर मुहर लगा दी। अब सिवनी और बालाघाट के लोगों का सफर आसान होने जा रहा है। यह अभी यह टू-लेन मार्ग है, जो कि कई जगह घुमावदार भी है। इस सड़क के बार-बार खराब होने के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार तो ट्रैफिक जाम भी लग जाता है। यही वजह है कि 91 किलोमीटर के सफर में लगभग 3 से 4 घंटे का समय लगता है। यह फोरलेन सड़क बनने के बाद यह सफर लगभग दो घंटे में पूरा हो जाएगा। इससे लोगों को आने-जाने में काफी आसानी मिलेगी। इस सड़क के फोरलेन बनने से दोनों शहरों के बीच रहने वाले हजारों परिवारों की आवाजाही भी आसान हो जाएगी। यानी लगभग पांच लाख राहगीरों को इसका फायदा होगा। आसपास के क्षेत्रों को जोड़ें तो 8 से 10 लाख लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी।

हादसों में आएगी कमी

इसके फोरलेन बनने से छात्रों, मरीजों, किसानों और नौकरी या कारोबार के लिए आने-जाने वालों का समय बचेगा। सड़क बनने से हादसों में भी कमी आएगी। सबसे खास बात यह है कि इलाज और पढ़ाई के लिए दूसरे शहरों में आने-जाने वाले लोगों को समय पर पहुंचने में काफी मदद मिलेगी। इस स्टेट हाईवे के निर्माण के लिए सरकार ने 3961 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। फोरलेन का काम हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल पर होगा। यह फोरलेन राष्ट्रीय राजमार्ग-44 और 543 को भी जोड़ेगा। इसके अलावा कैबिनेट ने प्रदेश की 22 प्रमुख सड़कों का मालिकाना हक एमपीआरडीसी को देने का निर्णय भी लिया है।

पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

इसके बदले एमपीआरडीसी राज्य सरकार को अपनी अंश पूंजी जारी करेगा। इन सड़कों से मिलने वाला टोल और अन्य राजस्व एमपीआरडीसी की आय माना जाएगा। इससे निगम कर्ज के ब्याज और मूलधन का भुगतान करेगा। सिवनी-बालाघाट सड़क बनने से इन इलाकों के पर्यटन को भी काफी फायदा मिलने वाला है। फोरलेन सड़क से कान्हा और पेंच जैसे पर्यटन क्षेत्रों तक पहुंच आसान हो जाएगी। इस मार्ग में लगभग 13 किमी का कान्हा कॉरिडोर भी शामिल रहेगा।

कॉरिडोर और अंडरपास को जोड़ा जाएगा

इसमें लगभग 3 किमी हिस्सा अंडरपास भी होगा। वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए कॉरिडोर और अंडरपास को जोड़ा जाएगा। 91 किमी मार्ग में कुछ बायपास भी बनाए जाएंगे। इससे भीड़ वाले हिस्सों में यातायात का दबाव कम करने और सफर भी आसान हो जाएगा। इसके अलावा, इससे स्थानीय लोगों को काफी राहत मिलेगी। इसके अलावा 12 प्रमुख मार्गों के निर्माण के लिए एमपीआरडीसी को 4,600 करोड़ रुपए का बैंक कर्ज लेने की सरकारी गारंटी दी जाएगी। यह कर्ज नाबार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट असिस्टेंस (एनआईडीए) से लिया जाएगा। इनमें भोपाल-विदिशा फोरलेन, इंदौर-देपालपुर, मंदसौर-सीतामऊ और पूर्वी भोपाल बाईपास को 4 से 6 लेन करने का काम शामिल है।

धन्वंतरी स्वास्थ्य विश्वविद्यालय के लिए 244 पद मंजूर

मोहन कैबिनेट में उज्जैन में स्थापित होने वाले धन्वंतरी स्वास्थ्य विश्वविद्यालय के लिए 244 पद मंजूर किए गए हैं। इनमें 154 नियमित, एक संविदा और 89 पद आउटसोर्सिंग से भरे जाएंगे। विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार इंदौर, उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर, नर्मदापुरम और चंबल संभाग के 31 जिलों में रहेगा।

महत्वपूर्ण ख़बर

बाबा महाकाल की कृपा से सिंहस्थ-2028 का आयोजन भव्य और दिव्य होगा

- भोपाल। बाबा महाकाल की कृपा से सिंहस्थ-2028 महापर्व का आयोजन भव्य, दिव्य, अद्भुत और अलौकिक होगा। सिंहस्थ के दृष्टिगत उज्जैन में किए जा रहे विकास कार्यों से महापर्व के पूर्व उज्जैन का सुंदर और सुव्यवस्थित होगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सिंहस्थ मेला प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री जगदीश अग्रवाल के दायित्व ग्रहण समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सिंहस्थ के लिए संत, प्रशासन, संगठन सभी अपने-अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए अपनी भूमिका का निर्वहन करे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि संत-महात्माओं के मार्गदर्शन में शासन-प्रशासन द्वारा सिंहस्थ महापर्व के लिए श्रद्धालुओं एवं साधु-संतों की सुविधा और सेवा के लिए चाक-चौबंद व्यवस्थाएं की जा रही हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का मंत्रालय कर्मचारियों ने किया अभिनंदन

- भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश के शासकीय अधिकारी और कर्मचारियों के प्रमोशन की प्रक्रिया अब रुकेगी नहीं, अब पदोन्नति का यह क्रम साल दर साल चलता रहेगा। इस साल सभी विभागों में पदोन्नति के लिए डीपीसी प्रारंभ होने वाली है। सभी पात्र कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। पारदर्शी निर्णय और दृढ़ संकल्प ही सुशासन का आधार स्तंभ है। कर्मचारियों के हित में राज्य सरकार सभी कल्याणकारी निर्णय लेने के लिए सदैव तत्पर है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कर्मचारियों बहनों को रक्षाबंधन के पावन पर्व की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव मंत्रालय में आयोजित अभिनंदन समारोह को संबोधित कर रहे थे।

एमपी में साइबर ठगी का अजब नियम

500 रुपये की रकम वापस लेने के लिए भी देना होगा 1000 रुपये का बॉन्ड

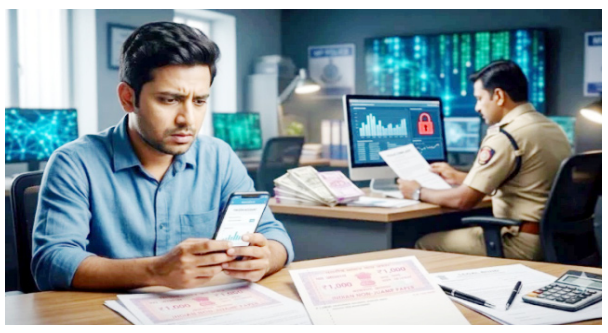

भोपाल। मध्य प्रदेश में साइबर ठगी का शिकार हुए लोगों को अपनी ही लूटी हुई रकम वापस पाने में एक अजीबोगरीब परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

केंद्र सरकार के नए दिशा-निर्देशों के बाद ठगों के बैंक खातों में होल्ड (फ्रीज) की गई राशि लौटाने की प्रक्रिया भले ही शुरू हो गई है, लेकिन इसके लिए मध्य प्रदेश में पीड़ितों को 1000 रुपये का क्षतिपूर्ति बॉन्ड देना पड़ रहा है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि अगर किसी पीड़ित को महज 500 रुपये का रिफंड भी लेना है, तब भी उसे 1000 रुपये का स्टाम्प खरीदना ही होगा।

स्टाम्प कानून की बाध्यता बन रही बाधा

यह पूरी समस्या 'इंडियन स्टाम्प एक्ट-1899' के नियमों के कारण पैदा हुई है। इस एक्ट के तहत मध्य प्रदेश में क्षतिपूर्ति बॉन्ड के लिए 1000 रुपये की स्टाम्प ड्यूटी अनिवार्य है। वर्तमान एसओपी में यह स्पष्टीकरण नहीं है कि कितनी रकम की वापसी पर कितने मूल्य का स्टाम्प देना होगा। इसी कानूनी पेंच के कारण जिन लोगों की कम राशि ठगी गई है, उनके लिए रिफंड प्रक्रिया आर्थिक रूप से अव्यावहारिक साबित हो रही है।

राजस्थान और कश्मीर ने दी राहत, मप्र में भी प्रस्ताव लंबित

इस समस्या को देखते हुए राजस्थान सरकार ने अपने यहां क्षतिपूर्ति बॉन्ड की राशि को घटाकर 200 रुपये कर दिया है। इसी तरह जम्मू-कश्मीर और कुछ अन्य राज्यों ने भी इसमें कटौती कर पीड़ितों को राहत दी है। इस तर्ज पर मध्य प्रदेश की साइबर पुलिस ने भी राज्य के गृह विभाग को एक प्रस्ताव भेजा है, जिसमें बॉन्ड की राशि को घटाकर 100 रुपये करने की सिफारिश की गई है। गृह विभाग इस प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजेगा।

आखिर क्यों भरवाया जाता है यह बॉन्ड?

अधिकारियों के अनुसार, क्षतिपूर्ति बॉन्ड भरवाने का मुख्य उद्देश्य कानूनी जटिलताओं से बचना है। अगर पीड़ित को पैसे वापस मिलने के बाद भविष्य में कोई दूसरा दावेदार अदालत पहुंच जाता है। कोर्ट किसी अन्य वैधानिक कारण से वह रकम वापस मांगता है, तो ऐसे में वह व्यक्ति जवाबदेह होगा, जिसे रिफंड मिला है।

इंदौर में दूध के रेट 65 रुपये करने की मांग

दूध उत्पादक किसानों ने खोला मोर्चा

इंदौर। इंदौर जिले में एक सितंबर से दूध की नई खरीदी दर तय होने से पहले दूध उत्पादक किसानों ने 65 रुपये प्रति लीटर खरीदी मूल्य की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया है। किसान शोषण विरोधी मंच के नेतृत्व में मंगलवार को बड़ी संख्या में किसानों ने कलेक्टर और संभागायुक्त कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा।

किसानों का कहना है कि पशुपालन और दूध उत्पादन की लागत लगातार बढ़ रही है, लेकिन उन्हें इसके अनुपात में दूध का मूल्य नहीं मिल रहा है। दरअसल, ज्ञापन सौंपने से पहले बायपास स्थित झालरिया में दूध उत्पादक किसानों की बैठक हुई थी। इसमें दिलीप सिंह पवार, महेंद्र सिंह, लाखन सिंह सहित बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए। बैठक में तय किया गया कि दूध उत्पादन की वास्तविक लागत और किसानों की मेहनत को देखते हुए सरकार के सामने 65 रुपये प्रति लीटर खरीदी मूल्य की मांग रखी जाएगी। इसी मांग को लेकर मंगलवार को ज्ञापन सौंपा गया। दूध व्यापारियों का कहना है कि किसानों को फैट के आधार पर करीब 9.50 रुपये प्रति फैट की दर से भुगतान किया जा रहा है। आगामी दिनों में दूध के भाव को लेकर बैठक होगी। इसमें खरीदी दर बाजार मूल्य के साथ उत्पादन की वास्तविक लागत को आधार बनाकर तय की जाए।

किसानों ने कहा कि पशुओं की कीमत के साथ खली-भूसा, चारा, दवाइयों और मजदूरी पर खर्च लगातार बढ़ रहा है। इसके बावजूद गांवों के दूध उत्पादक किसानों को व्यापारियों से करीब 52 से 55 रुपये प्रति लीटर ही मिल रहे हैं। किसानों के अनुसार, मौजूदा दर में दूध उत्पादन की लागत निकालना भी मुश्किल हो रहा है। वर्तमान में खली 50 रुपये प्रति किलो तक पहुंच चुकी है और भैंस भी डेढ़ से पौने दो लाख रुपये तक मिल रही है। मजदूरी, भूसा, बिजली और डॉक्टर व दवाइयों का खर्च भी बढ़ चुका है।

बाजार में अधिक दाम पर बिक्री

किसानों ने खरीद और बिक्री मूल्य के अंतर पर भी सवाल उठाए। किसान शेरसिंह और महेंद्र सिंह का कहना है कि गांवों में जिस दूध के लिए 52 से 55 रुपये प्रति लीटर मिल रहे हैं, वही दूध शहर में उपभोक्ताओं को 65 से 70 रुपये प्रति लीटर तक बेचा जा रहा है। किसानों के अनुसार, इस अंतर में उत्पादकों को पर्याप्त हिस्सा नहीं मिल रहा है।

इंदौर में बांबे अस्पताल के सर्विस रोड पर फंसी थी शहर कांग्रेस अध्यक्ष की कार, अब वहीं बैठकर किया प्रदर्शन

इंदौर। बांबे अस्पताल की सर्विस रोड की बदहाली का शिकार मंगलवार को शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे स्वयं हो गए थे। यहां से गुजरते समय उनकी कार कीचड़ में फंस गई थी। इसके बाद चौकसे ने वीडियो जारी कर बदहाल सड़क के लिए महापौर पुष्यमित्र भार्गव को जिम्मेदार ठहराया।

इधर बुधवार को वे अन्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर पहुंची और कीचड़ से भरी सड़क पर बैठकर प्रदर्शन किया।

चौकसे ने कहा कि किसी काम से जा रहे थे, तभी सर्विस रोड पर जमा गहरे कीचड़ और गड्ढों में कार के पहिए फंस गए। स्थानीय लोगों की मदद से काफी मशक्कत के बाद कार बाहर निकाली गई। कार कीचड़ से लथपथ हो गई और उन्हें भी परेशानी हुई।

सड़क कागजों पर ही बन रही

उन्होंने कहा कि दो साल पहले ड्रेनेज लाइन डालने के लिए इस सड़क को खोदा गया था। तब से यह सड़क कागजों पर ही बन रही है। हकीकत में एक इंच भी काम नहीं हुआ। उन्होंने कहा- ह्यजब मेरी कार ही कीचड़ में फंस सकती है, तो सोचिए रोज यहां से गुजरने वाले हजारों दोपहिया वाहन चालकों का क्या हाल होता होगा। हर दिन लोग यहां फिसलकर गिर रहे हैं और चोटिल हो रहे हैं।

चौकसे ने कहा कि पोस्टर पर विकास का दावा करने वाले महापौर को दो साल से खोदकर छोड़ी गई यह सड़क दिखाई नहीं दे रही। उनके नेतृत्व में टूटी-फूटी और अधूरी सड़कों से ही इंदौर की पहचान बन गई है। भाजपा की परिषद का कार्यकाल खत्म होने को है, लेकिन शहर की सड़कों की हालत जस की तस है।

अनुसूचित जाति वर्ग का कल्याण सर्वोच्च प्राथमिकता

भोपाल। अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री श्री नागर सिंह चौहान ने कहा कि अनुसूचित जाति वर्ग का कल्याण शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक अनिवार्य रूप से पहुंचे, जिससे उनके सामाजिक और आर्थिक जीवन स्तर में प्रभावी सुधार लाया जा सके। मंत्री श्री नागर ने मंत्रालय में अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के कार्यों और कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। मंत्री श्री चौहान ने भिंड, मुरैना, शाजापुर और विदिशा में स्वीकृत कन्या छात्रावासों का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए।

आमजन के काम हेल्प लाइन तक पहुंचने से पहले हो जाएं

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि आम जनता से जुड़े कार्यों का समय-सीमा में निराकरण किया जाए। आमजन के कार्य हेल्प लाइन तक पहुंचने से पहले ही पूरे हो जाएं, ऐसे प्रयास किए जाएं। जनता से जुड़े सभी प्राथमिक कार्यों का समय पर निपटारा आवश्यक है। राज्य शासन ने मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान: 2026 के माध्यम से साप्ताहिक शिविर और संवाद के आयोजन प्रारंभ किए हैं। गत तीन सप्ताह में इसके अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। त्योहार या अन्य कारणों से जब शुक्रवार को जन विश्वास अभियान के तहत शिविर और संवाद का आयोजन नहीं हो सके तो आगामी दिवस अर्थात शनिवार को यह कार्यवाही की जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंत्रालय में विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों से एक विशेष बैठक में यह निर्देश दिए। बैठक में मुख्य सचिव श्री अशोक बर्णवाल, मुख्यमंत्री कार्यालय में अपर मुख्य सचिव श्री नीरज मंडलोई सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य शासन ने उत्तरदायी प्रशासन के लिए मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान: 2026 प्रारंभ किया है। इस अभियान के संचालन से बड़ी संख्या में आमजन के लंबित कार्यों और समस्याओं का समाधान हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने निर्देश दिए कि जन विश्वास अभियान की आगामी एक माह की तैयारी रखी जाए, ताकि जनता को संवाद और शिविर का पूरा लाभ प्राप्त हो। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राजधानी में मंत्रालय सहित विंध्याचल और सतपुड़ा भवनों में बायोमैट्रिक अटैंडेंस की व्यवस्था प्रारंभ की जा रही है। यह प्रदेश के जिलों में भी लागू की जाएगी। अधिकारी-कर्मचारी निर्धारित समय पर कार्यालय पहुंचें और समय पर कार्यों को पूर्ण करें, इस पर वरिष्ठ अधिकारी नजर रखेंगे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने निर्देश दिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी की भूमि नि:शुल्क रजिस्ट्री के लिए अधिकार अभिलेखों के पंजीयन, जिला स्तर पर राजस्व और पंचायत ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों की संयुक्त कमेटी गठित करने और ग्राम की दखल रहित भूमि का चिन्हांकन का कार्य पूर्ण किया जाए। ग्रामीण आबादी को बैंक ऋण आसानी से मिले इसके लिए सभी को नि:शुल्क रजिस्ट्री का लाभ दिलवाने की अभियान के संचालन के लिए रूपरेखा तैयार कर अंतिम रूप दिया जाए। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि घोषित कर भूमिहीनों को आवास पट्टे प्रदान करने के लिए आवश्यक प्रक्रिया संचालित की जाए।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने निर्देश दिए कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग नर्मदा समग्र मिशन (नमन) के गठन और क्रियान्वयन के लिए आवश्यक कार्यवाही को शीघ्र पूर्ण किया जाए।

इंदौर में रांग साइड से आई बाइक के हैंडल में फंसा महिला का बैग

झटके से सड़क पर गिरने से मौत

इंदौर। राखी मनाने पति और बेटे के साथ मायके (उज्जैन) जा रही 30 वर्षीय महिला की सड़क हादसे में मौत हो गई। बायपास पर गलत दिशा से आए बाइक सवार के हैंडल में महिला का बैग अटक गया। इससे दोनों बाइक का संतुलन बिगड़ा और महिला सड़क पर गिर गई। सिर में गहरी चोट लगने के कारण उसकी मौत हो गई।

महिला की पहचान तिल्लौर निवासी 30 वर्षीय पूजा पाटीदार के रूप में हुई है। वह पति निर्मल पाटीदार और आठ वर्षीय बेटे शिवाय के साथ मायके जा रही थी। पूजा बाइक पर पीछे बैठी थी और उसके हाथ में कपड़ों से भरा बैग था। बायपास (बेस्ट प्राइस के पास) पर दूसरी बाइक पर सवार युवक गलत दिशा से ओवरटेक करते हुए निकला। इसी दौरान पूजा के हाथ में मौजूद बैग उस बाइक के हैंडल में फंस गया। अचानक हैंडल में फंसे बैग के खिंचने से दोनों बाइक असंतुलित हो गईं और पूजा सड़क पर जा गिरी।

सिर में लगी गंभीर चोट, खून बहता रहा

जेठ प्रदीप के मुताबिक, बाइक पूजा को दूर तक घसीटते हुए ले गई थी। हादसे में पूजा के सिर में गहरी चोट आई। चोट इतनी गंभीर थी कि उसके मुंह, नाक और कान से खून निकलने लगा। पति निर्मल ने एंबुलेंस (108) से तत्काल उसे उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने पूजा को मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद परिवार में राखी की खुशियां मातम में बदल गईं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। निर्मल खेती के साथ नमकीन कारखाने में गाड़ी चलाने का काम भी करता है। निर्मल और शिवाय को भी मामूली चोट आई है।

विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा से होगा विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त

भोपाल। उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष मंत्री श्री इन्दर सिंह परमार ने कहा कि राष्ट्र पुनर्निर्माण के महायज्ञ में शिक्षा की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है और हमारा मुख्य केंद्रबिंदु विद्यार्थी है, इसलिए उच्च शिक्षा में होने वाला प्रत्येक परिवर्तन विद्यार्थी के सर्वांगीण हित और विकास को ध्यान में रखकर होना चाहिए। शिक्षा केवल उपाधि प्राप्त करने का माध्यम नहीं, बल्कि ज्ञान, कौशल, व्यक्तित्व, संस्कार, नैतिक मूल्यों और जीवन-दृष्टि के निर्माण का माध्यम है। विद्यार्थियों को रोजगार एवं कौशल के लिए सक्षम बनाने के साथ उनमें मानवीय संवेदनाएं, नैतिक मूल्य और सामाजिक उत्तरदायित्व विकसित करना भी आवश्यक है। हमारा ध्येय केवल रोजगार प्राप्त करने वाली पीढ़ी तैयार करना नहीं, बल्कि ज्ञानवान, कुशल, संवेदनशील, चरित्रवान और राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों को समझने वाले श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण करना होना चाहिए।

इंदौर में ट्रैफिक पुलिस ने एक हजार से ज्यादा मोडिफाइड साइलेंसर पर चलवाया रोड रोलर

इंदौर। इंदौर शहर के चौराहों और मुख्य मार्गों पर बेहतर यातायात प्रबंधन के साथ नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई की जा रही है।

यातायात पुलिस ने विजय नगर में मोडिफाइड साइलेंसर पर रोड रोलर चलाकर उन्हें नष्ट किया। आकस्मिक चेकिंग कर तेज या लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाने वालों, मोडिफाइड साइलेंसर लगाकर तेज और कर्कश ध्वनि निकालकर आम जनता में भय पैदा करने वाले वाहन चालकों और हूटर लगे वाहनों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे।

मोडिफाइड साइलेंसर भी जब्त किये गये

बीते माह से यातायात प्रबंधन पुलिस के सभी अधिकारियों द्वारा यातायात प्रबंधन जोन के अंतर्गत आने वाले मुख्य मार्गों और चौराहों पर यातायात अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम बनाकर तेज और कर्कश ध्वनि वाले मोडिफाइड साइलेंसर एवं हूटर लगे वाहनों के विरुद्ध सघन जांच कर कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई के दौरान मोडिफाइड साइलेंसर भी जब्त किए गए।

साइलेंसर लगाकर डराने की कोशिश

विजय नगर क्षेत्र में भी डीसीपी यातायात राजेश कुमार त्रिपाठी और यातायात के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में जब्त एक हजार से ज्यादा साइलेंसरों पर रोड रोलर चलाकर उन्हें नष्ट किया गया। डीसीपी त्रिपाठी ने कहा कि नियम विरुद्ध तेज और कर्कश ध्वनि वाले साइलेंसर लगाकर आम जनता में भय पैदा करने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई है।

स्वामी, प्रकाशक : अली आदिल खान द्वारा साईं प्रिंटिंग प्रेस डी 85 सेक्टर 8, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर 201301 से मुद्रित और एच 41 ए, अबुल फजल एनक्लेव, जामिया नगर, दक्षिण पूर्व दिल्ली 110025 से प्रकाशित। संपादक : अली आदिल खान
RNI No.: DELMUL/2012/47011 | Email:timesofpedia@gmail.com | समाचार चयन एवं प्रकाशन के लिए पीआरबी एक्ट के तहत जिम्मेदार तथा समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन होंगे।